सितंबर 2020 ■ ₹ 30

सभी परीक्षाओं को समर्पित प्रतियोगी पत्रिका

समसामयिकी क्रॉनिकल

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी
- नीति आयोग पहल एआईएम आईक्रेस्ट
- आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
- वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020
- वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020
- फिश क्रायोबैंक
- नासा मार्स 2020 पर्सिवेरेन्स रोवर मिशन
- यूएई का पहला मंगल मिशन
- वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020
- सतत विकास रिपोर्ट 2020

- इन्हें भी जानें
- पत्र-पत्रिका संपादकीय
- संस्थान-संगठन
- समसामयिक प्रश्न
- लोक सभा-राज्य सभा प्रश्नोत्तर सार

24 वर्षों से

आपकी सफलता का मार्गदर्शक

सर्वोत्तम ज्ञान का संदर्भ-कोष

भारत सरकार की पहल व विकास से जुड़ी नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम, रिपोर्ट, समिति, सूचकांक, अधिनियम, संशोधन एवं संगठन

मूल्य 215/-

मुख्य आकर्षण

- सामाजिक विकास
- विनिर्माण क्षेत्र
- शिक्षा
- कृषि
- ऊर्जा
- सुरक्षा
- सेवा क्षेत्र
- परिवहन
- पर्यावरण
- भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन
- समकालीन अर्थव्यवस्था
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत सार्वभौमिक विश्व का बाजीगर

- 350 लाख करोड़ की भारतीय अर्थव्यवस्था की पहल
- भारत के कूटनीतिक आयाम
- सामाजिक एकीकरण व समरसता
- भारत के निर्माण में मजबूत संस्थानों की भूमिका
- ए.आई.: मानव रहित विश्व
- भारत में वैज्ञानिक विकास
- सामाजिक न्याय के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण
- पर्यावरण सक्रियता

Cover Story

कोविड-19: व्यवधान, प्रावधान व प्रभाव

- एक जैविक आपदा के रूप में
- वायरस का पर्यावरण पर प्रभाव
- भारत में ग्रामीण जीवन व आजीविका पर प्रभाव
- अर्थव्यवस्था पर प्रभाव व समाधान
- महिलाओं पर प्रभाव
- नागरिक समाज की भूमिका
- स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा अध्यादेश
- भारत में चिकित्सा और संरचना
- मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव
- आत्मनिर्भर भारत अभियान

CHRONICLE BOOKS

write us:

Also Available on
www.chronicleindia.in
amazon flipkart.com

A-27D, Sector-16, Noida, U.P.-201301
Mob.: 9953007630, E-mail: circulation@chronicleindia.in

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा

2020 संस्करण

हल प्रश्न पत्र

Also Available on

www.chronicleindia.in

amazon

flipkart.com

Contact us

CHRONICLE BOOKS

A-27D, Sector-16, Noida, U.P.-201301
Ph.: 0120-2514610/12, www.chronicleindia.in
E-mail: circulation@chronicleindia.in

टू द पॉइंट

NCERT Plus

6 भागों में

2020 संस्करण

इस पुस्तक को टू द पॉइंट रूप में सामान्य अध्ययन व सामान्य ज्ञान (GK/GS) की प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर व NCERT की सामग्रियों को समाहित कर तैयार किया गया है। इसमें NCERT कक्षा 6-12 की नई व पुरानी पुस्तकों तथा IGNOU, NIOS, राज्य बोर्ड एवं अन्य महत्त्वपूर्ण पुस्तकों से सामग्री संकलित की गई है।

NCERT, IGNOU, NIOS व State Board द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अध्ययन से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन व सामान्य ज्ञान की आधारभूत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह पुस्तक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, यू.जी.सी.-नेट/जे.आर.एफ., कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा, बीएड, राज्य कर्मचारी चयन आयोग व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं तथा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति व राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, ओलंपियाड के अलावा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं व प्रवेश परीक्षाओं जैसे- CLAT, विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

Also Available on

www.chronicleindia.in

amazon flipkart.com

CHRONICLE BOOKS

Corporate Office

A-27D, Sector-16, Noida, U.P.-201301
Ph.: 0120-2514610/12,Mob.: 9953007630
E-mail: circulation@chronicleindia.in, info@chronicleindia.in

आपकी सफलता का मार्गदर्शक

आईएएस तथा पीसीएस परीक्षाओं, यू.जी.सी. की जे.आर.एफ./नेट परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित एवं अन्य समकक्ष परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी

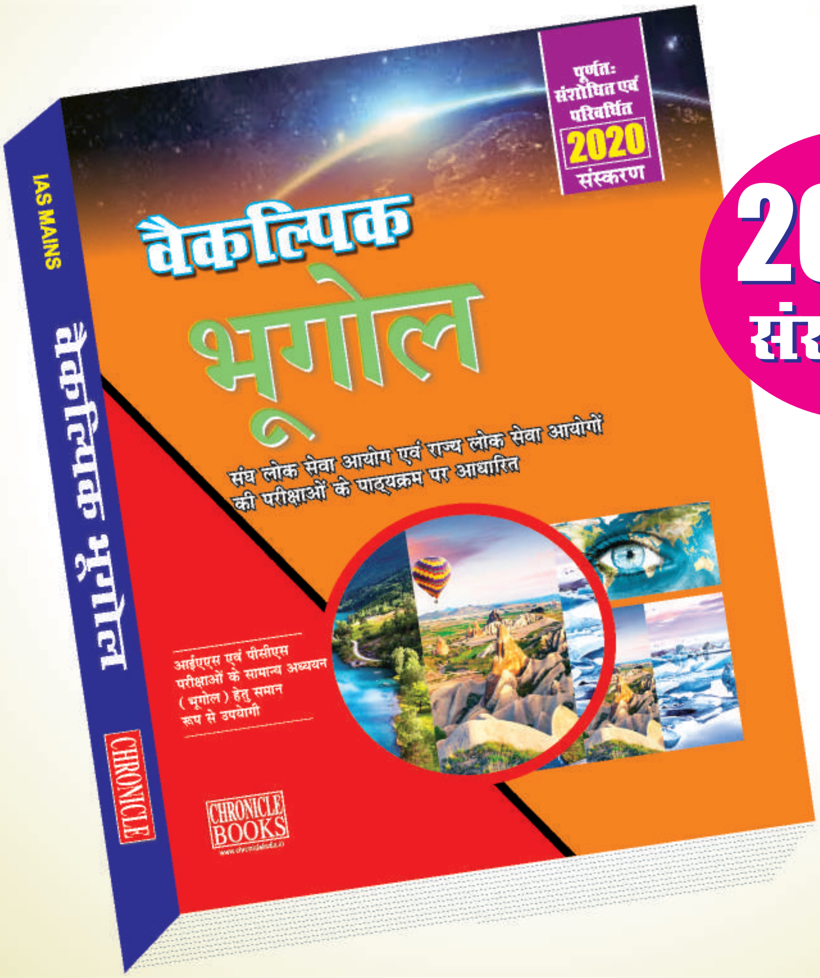

2020 संस्करण

Also Available on

www.chronicleindia.in

amazon

flipkart.com

Contact us

CHRONICLE BOOKS

A-27D, Sector-16, Noida, U.P.-201301
Ph.: 0120-2514611/12, www.chronicleindia.in
E-mail: circulation@chronicleindia.in

सभी परीक्षाओं को समर्पित प्रतियोगी पत्रिका

समसामयिकी क्रॉनिकल

सितंबर 2020 | वर्ष : 7 | अंक : 7

इस अंक में...

लोक सभा राज्य सभा प्रश्नोत्तर-सार 56

इन्हें भी जानें 57

07 आर्थिकी
- आरबीआई 'वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट'
- कृषि से उत्सर्जन कम करने हेतु 'ग्रीन एजी पायलट परियोजना'
- कृषि निर्यात पर गठित उच्च स्तरीय समूह ने सौंपी रिपोर्ट
- आरबीआई का श्रीलंका के केन्द्रीय बैंक के साथ मुद्रा अदला-बदली का समझौता
- क्यूआर कोड विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट
- राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण तकनीकी सलाहकार समिति
- नाबार्ड की जल संभर परियोजनाओं हेतु पुनर्वित्त योजना
- भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम
- फिश क्रायोबैंक

13 राष्ट्रीय
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी
- नीति आयोग की पहल 'एआईएम आईक्रेस्ट'
- डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय प्रबंधन सूचकांक
- नीति आयोग आकांक्षी जिला रैंकिंग
- सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन
- भारत की भू-सीमा से लगे देशों से सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध
- संशोधित प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार योजना 2020

19 अंतरराष्ट्रीय
- वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020
- यूएई परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला अरब देश
- गांधी-किंग एक्सचेंज एक्ट
- दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च
- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापना रूपरेखा संशोधन लागू
- 2064 में दुनिया की आबादी चरम पर: लांसेट अध्ययन

23 विज्ञान-पर्यावरण
- नासा 'मार्स 2020 पर्सिवेरेन्स रोवर मिशन'
- चीन का मंगल मिशन तिआनवेन-1
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 'ज्ञान संसाधन केंद्र नेटवर्क'
- अरुणाचल हिमालय भूकम्प-आवृत्ति अध्ययन
- प्लास्टिक का सफाया करने वाली बीटल लार्वा की नई प्रजाति
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का युवा सलाहकार समूह
- 'असम कीलबैक' साँप प्रजाति
- यूएई का पहला मंगल मिशन

29 BFSI

31 बिजनेस

32 राज्य

35 खेल

38 सार-संक्षेप

51 पत्र-पत्रिका संपादकीय

53 समसामयिक प्रश्न

55 संस्थान-संगठन

संपादक
एन.एन. ओझा

विज्ञापन
अध्यक्ष
संजीव नन्दक्योलियार
advt@chronicleindia.in
Ph. 9953007627

प्रसार
सहायक महाप्रबंधक
पंकज पांडेय
circulation@chronicleindia.in
Mob.: 9953007630
subscription@chronicleindia.in
Mob.: 0-9953007629

व्यावसायिक कार्यालय
क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27डी, सेक्टर-16
नोएडा-201301
फोन: 0120-2514611-12

सर्वाधिकार सुरक्षित (c) क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि. न्यायिक-क्षेत्र दिल्ली।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा. लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा**। द्वारा एच-31, प्रथम तल, ग्रीन पार्क एक्स. नयी दिल्ली - 110016, से प्रकाशित एवं रत्ना ऑफसेट, सी-101, ओखला फेस 2, नई दिल्ली, से मुद्रित। **संपादक. एन.एन.ओझा**

आर्थिकी

आरबीआई 'वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट'

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 24 जुलाई, 2020 को जुलाई 2020 की 'वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' जारी की गई। यह रिपोर्ट का 21वां अंक था।

महत्वपूर्ण तथ्यः यदि कोविड-19 महामारी का प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव 'बहुत गंभीर' रहा तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात चालू वित्त वर्ष के अंत तक मार्च 2020 के 8.5% से बढ़कर 14.7% हो सकता है। जबकि आधारभूत परिदृश्य (baseline scenario) के तहत यह 2021 तक 12.5% हो सकता है।

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जोखिम-भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (Capital to Risk-weighted Assets Ratio- CRAR) सितंबर 2019 में 15% की तुलना में मार्च 2020 में घटकर 14.8% हो गया था।
- आरबीआई ने अनुमान लगाया कि CRAR मार्च 2021 में 'आधारभूत परिदृश्य' के तहत 13.3% और 'बहुत गंभीर तनाव परिदृश्य' के तहत 11.8% तक पहुंच सकता है।
- बैंक ऋण, जो 2019-20 की पहली छमाही के दौरान काफी कमजोर हो गया था, मार्च 2020 तक 5.9% तक नीचे फिसल गया और बाद की अवधि में बैंक समूहों में मंदी के वैविध्यपूर्ण होने के साथ इसमें और गिरावट आई।

जीके फैक्ट

✧ 'वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' आरबीआई द्वारा वर्ष में दो बार जून या जुलाई तथा दिसंबर में जारी की जाती है।

कृषि से उत्सर्जन कम करने हेतु 'ग्रीन एजी पायलट परियोजना'

केंद्र सरकार ने 28 जुलाई, 2020 को कृषि क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने और सतत कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मिजोरम में 'ग्रीन एजी परियोजना' (Green-Ag Project) की शुरुआत की।

महत्वपूर्ण तथ्यः मिजोरम उन पांच राज्यों में शामिल है, जहां परियोजना लागू की जानी है। मिजोरम के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड इस परियोजना का हिस्सा हैं।

- मिश्रित भूमि उपयोग प्रणालियों के साथ परियोजना को पांच परिदृश्यों में कम से कम 1.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि में कई वैश्विक पर्यावरणीय लाभ प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसका उद्देश्य कम से कम 1,04,070 हेक्टेयर कृषि भूमि को सतत भूमि और जल प्रबंधन के तहत लाना है। कृषि की सतत विकास पद्धतियां 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन में कमी को सुनिश्चित करेगी।
- यह पायलट परियोजना 31 मार्च, 2026 तक समाप्त होगी। मिजोरम के दो जिलों- लुंगलेई और मामित में 1,45,670 हेक्टेयर भूमि इसके दायरे में आएगी। दो संरक्षित क्षेत्रों- दंपा टाइगर रिजर्व और थोरंगलांग वन्यजीव अभयारण्य सहित कुल 35 गांव इसके तहत कवर करने का लक्ष्य है।

जीके फैक्ट

✧ ग्रीन एजी परियोजना को 'वैश्विक पर्यावरण सुविधा' (Global Environment Facility) द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इस परियोजना को क्रियान्वित कराने की जिम्मेदारी कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग पर है।

कृषि निर्यात पर गठित उच्च स्तरीय समूह ने सौंपी रिपोर्ट

15वें वित्त आयोग द्वारा कृषि निर्यात पर गठित उच्च स्तरीय समूह (एचएलईजी) ने 31 जुलाई, 2020 को आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

महत्वपूर्ण तथ्यः कृषि निर्यात को बढ़ावा देने हेतु राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन देने और भारी आयात की भरपाई करने वाली फसलों को बढ़ावा दिए जाने के लिए आईटीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव पुरी की अध्यक्षता में इस उच्च-स्तरीय समूह का गठन किया गया था।

प्रमुख सिफारिशेंः एक मांग आधारित दृष्टिकोण और 22 फसल मूल्य श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित करना।

- हितधारकों की भागीदारी के साथ राज्य आधारित निर्यात योजना का निर्माण करना।
- समूह ने सिफारिश की है, कि निजी क्षेत्र को कृषि निर्यात योजना के निष्पादन और परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, जबकि केंद्र को प्रोत्साहन देने वाली की भूमिका निभानी होगी।

- वित्तपोषण और कार्यान्वयन को समर्थन देने के लिए एक मजबूत संस्थागत तंत्र होना चाहिए।

अन्य तथ्यः समूह के अनुसार सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद उत्पन्न अतिरिक्त निर्यात से देश में अनुमानित 70 लाख से 1 करोड़ रोजगार सृजन की संभावना है।

- कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में 40 अरब डॉलर से बढ़कर 70 अरब डॉलर तक पहुंचने की क्षमता है।
- इनपुट (सामग्रियों), बुनियादी ढांचा, प्रसंस्करण और मांग बढ़ाने के उपायों पर कृषि निर्यात में 8-10 अरब डॉलर का निवेश होने का अनुमान है।

आरबीआई का श्रीलंका के केन्द्रीय बैंक के साथ मुद्रा अदला-बदली का समझौता

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जुलाई 2020 में श्रीलंका के केन्द्रीय बैंक के साथ 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला-बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था नवंबर 2022 तक उपलब्ध रहेगी।

महत्वपूर्ण तथ्यः 'सार्क मुद्रा अदला बदली फ्रेमवर्क' (SAARC Currency Swap Framework) के तहत मुद्रा विनिमय सुविधा के लिए श्रीलंकाई पक्ष के अनुरोध के आधार पर यह सुविधा प्रदान की गई।

- ज्ञात हो कि 23 मई, 2020 को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबया राजपक्षे ने भारत से सार्क व्यवस्था के तहत 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा विनिमय और द्विपक्षीय रूप से अतिरिक्त 1.1 अरब डॉलर की मुद्रा विनिमय की सहायता मांगी थी।
- मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था में, एक देश एक विदेशी केंद्रीय बैंक को डॉलर प्रदान करता है, जो उसी समय (लेन-देन के समय) बाजार विनिमय दर के आधार पर अपनी मुद्रा के बराबर धनराशि पहले देश को प्रदान करता है।
- पार्टियां भविष्य में निर्दिष्ट तिथि पर अपनी दो मुद्राओं की इन मात्राओं को पहले लेन-देन के समान विनिमय दर का उपयोग करते हुए वापस अदला-बदली के लिए सहमत होती हैं, जो कि अगले दिन या दो साल बाद भी हो सकती हैं। श्रीलंका के मामले में, यह दो साल से अधिक है।

जीके फैक्ट

✧ भारतीय रिजर्व बैंक 2019-22 तक 'सार्क मुद्रा अदला बदली फ्रेमवर्क' के तहत सार्क क्षेत्र में केंद्रीय बैंकों के लिए 2 बिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय व्यवस्था प्रदान करेगा।

क्यूआर कोड विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट

आईआईटी बॉम्बे के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डी. बी. पाठक की अध्यक्षता में गठित 'क्यूआर कोड विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट' भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 22 जुलाई, 2020 को जारी की गई।

महत्वपूर्ण अनुशंसाएंः कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार को उपभोक्ताओं के लिए क्यूआर (त्वरित प्रतिक्रिया) कोड लेनदेन के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजना (Incentives Scheme) प्रदान करनी चाहिए।

- जो व्यापारी इलेक्ट्रानिक तरीके से भुगतान स्वीकार करते हैं उन्हें 'कर प्रोत्साहन' दिया जाना चाहिये।
- 'प्रोप्राइटरी क्यूआर' (Proprietary QR) कोड एक खुले, परस्पर भुगतान परिप्रणाली में एक बाधा है, इसलिए खुले तथा अंतःप्रचालनीय मानक (Interoperable standards) के पक्ष में प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड को चरणबद्ध तरीके से हटाने की स्पष्ट योजना होनी चाहिए।
- समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि नियामक व्यापारिक गतिविधियों के लिए मौजूदा बैंक खाते को वैध केवाईसी के रूप में स्वीकार कर सकता है। सभी उद्देश्यों के लिए, व्यापारी अधिग्रहण बैंक (वित्तीय संस्थान जो व्यापारी के बैंक खाते का रखरखाव करता है) व्यापारी के केवाईसी के लिए जिम्मेदार होगा।

क्यूआर कोडः यह एक दो आयामी मशीन द्वारा पठनीय बारकोड हैं, जिनका उपयोग 'पॉइंट ऑफ सेल' पर मोबाइल भुगतान की सुविधा के लिए किया जाता है।

- भारत में क्यूआर कोड भुगतान प्रणाली व्यापक तौर पर भारत क्यूआर, यूपीआई क्यूआर और प्रोप्राइटरी क्यूआर के जरिये काम करती है।

जीके फैक्ट

✧ 1994 में डेंसो वेव नाम की एक जापानी कंपनी ने क्यूआर कोड का आविष्कार किया था।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण तकनीकी सलाहकार समिति

लेखा परीक्षा नियामक राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) ने 17 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु के प्रोफेसर आर. नारायणस्वामी की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) का गठन किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः समिति में अध्यक्ष सहित सात सदस्य शामिल हैं।

- समिति लेखा मानकों और ऑडिटिंग मानकों के ड्राफ्ट से संबंधित मुद्दों पर NFRA के कार्यकारी निकाय को सहायता और सलाह देगी।
- यह वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं, तैयारीकर्ताओं तथा लेखा परीक्षकों के दृष्टिकोण से भी इनपुट प्रदान करेगी।

प्रमुख कार्यः लेखा परीक्षा गुणवत्ता के उपायों के विकास पर सलाह देना।

- जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त तरीकों पर सलाह देना, जिसमें निम्न को शामिल किया गया है

(क) लेखांकन और लेखा परीक्षा के मानकों के अनुपालन से संबंधित।
(ख) स्वतंत्र लेखा परीक्षक विनियमन के माध्यम से निवेशकों की रक्षा करने में NFRA की भूमिका से संबन्धित।

जीके फैक्ट

✧ राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का गठन भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के उप खंड (1) के तहत 1 अक्टूबर, 2018 को किया गया था। इसका प्रमुख कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों तथा कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों की अनुशंसा करना है।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020

16 जुलाई, 2020 को 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (UNDP) और 'ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल' (OPHI) द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 जारी किया गया।

रिपोर्ट शीर्षकः 'बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता तैयार करनाः एसडीजी को हासिल करना' (Charting pathways out of multidimensional poverty- Achieving the SDGs)।

महत्वपूर्ण तथ्यः 107 विकासशील देशों में, 1.3 बिलियन लोग (22%) बहुआयामी गरीबी से प्रभावित हैं।

- बच्चे बहुआयामी गरीबी की उच्च दर प्रदर्शित करते हैं। बहुआयामी गरीब लोगों में से लगभग आधे (644 मिलियन) 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। छः वयस्कों में से एक की तुलना में तीन में से एक बच्चा गरीब है।
- उप-सहारा अफ्रीका (558 मिलियन) और दक्षिण एशिया (530 मिलियन) में लगभग 84.3% बहुआयामी गरीब लोग रहते हैं।
- 107 मिलियन बहुआयामी रूप से गरीब लोग 60 या उससे अधिक उम्र के हैं। 65 देशों ने अपने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) में काफी कमी दर्ज की है।
- चार देशों ने अपने बहुआयामी गरीबी को आधा कर दिया है। भारत ने 10 वर्षों (2005/06 - 2015/16) में राष्ट्रीय स्तर पर 273 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है।

बहुआयामी गरीबीः बहुआयामी गरीबी दैनिक जीवन में गरीब लोगों द्वारा अनुभव किए गए विभिन्न अभावों को समाहित करती है - जैसे खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, जीवन स्तर में अपर्याप्तता, बेरोजगारी, काम की खराब गुणवत्ता आदि।

सूचकांक आयाम तथा संकेतकः यह बताता है कि लोग 10 संकेतक सहित तीन प्रमुख आयामों 'स्वास्थ्य', 'शिक्षा' और 'जीवन स्तर' में कैसे पीछे छूट जाते हैं। जो लोग इन भारित संकेतकों में से कम से कम एक तिहाई में अभाव का अनुभव करते हैं, वे बहुआयामी रूप से गरीब की श्रेणी में आते हैं।

गरीबी का आयाम	संकेतक	भारिता
स्वास्थ्य	पोषण	1/6
	बाल मृत्यु दर	1/6
शिक्षा	स्कूली शिक्षा के वर्ष	1/6
	विद्यालय उपस्तिथि	1/6
जीवन स्तर	पेयजल	1/18
	खाना पकाने का ईंधन	1/18
	स्वच्छता	1/18
	आवास	1/18
	बिजली	1/18
	परिसंपति	1/18

तमिलनाडु देश का शीर्ष निवेश गंतव्य

देश में निवेश परियोजनाओं पर नजर रखने वाली एक स्वतंत्र फर्म 'प्रोजेक्ट्स टुडे' द्वारा जुलाई 2020 में जारी 'प्रोजेक्स सर्वे' ('Projex Survey) के अनुसार तमिलनाडु इस वित्तीय वर्ष (2020-21) की पहली तिमाही में देश के शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में उभरकर सामने आया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः सर्वे के अनुसार विस्तारित महामारी-प्रेरित लॉकडाउन की अवधि के बीच भारत में समग्र ताजा निवेश घोषणाएं पांच साल में सबसे कम हो गई हैं।

- तमिलनाडु ने पहली तिमाही में देश में 97,859 करोड़ रुपए के 1,241 परिकल्पित परियोजनाओं को निष्पादित करने में 18, 236 करोड़ रुपए निवेश के प्रवाह के साथ 18.63% का योगदान किया है।
- कुल 7,400 करोड़ के निवेश के साथ देश में आने वाले पाँच डेटा केंद्रों में से तीन में तमिलनाडु द्वारा मेजबानी की गई है।
- अन्य दो डेटा केंद्र महाराष्ट्र में प्रस्तावित हैं, जो 11,228.8 करोड़ रुपए के नए निवेश के साथ तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर है।
- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने श्रम कानूनों में बदलाव किया, भूमि बैंकों (land banks) का निर्माण शुरू किया और अपने राज्यों में निवेश के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया।

जीके फैक्ट

✧ महाराष्ट्र ने जून 2020 में सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और अमेरिकी फर्मों के साथ एक वर्चुअल 'मैग्नेटिक महाराष्ट्र शिखर सम्मेलन' (Magnetic Maharashtra summit) के माध्यम से 12 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे।

अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार

जुलाई 2020 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में अमेरिका लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना रहा।

महत्वपूर्ण तथ्यः 2019-20 में, अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 में 87.96 बिलियन डॉलर के मुकाबले 88.75 बिलियन डॉलर था।

- अमेरिका उन कुछ देशों में से है, जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष (trade surplus) है। आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों के बीच व्यापार अंतर 2019-20 में बढ़कर 17.42 बिलियन डॉलर हो गया, जो 2018-19 में 16.86 बिलियन डॉलर था।
- 2018-19 में अमेरिका, चीन को पीछे छोड़ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया था। भारत और चीन के बीच द्वि पक्षीय व्यापार 2018-19 में 87.08 बिलियन डॉलर से कम होकर 2019-20 में 81.87 बिलियन डॉलर हो गया है।

जीके फैक्ट

✧ भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा 2019-20 में घटकर 48.66 बिलियन डॉलर हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष में 53.57 बिलियन डॉलर था।

नाबार्ड की जल संभर परियोजनाओं हेतु पुनर्वित्त योजना

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 13 जुलाई, 2020 को अपनी 2,150 जल संभर (वाटरशेड) विकास परियोजनाओं के लाभार्थियों को वित्त प्रदान करने हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 5,000 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त योजना की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्यः ये परियोजनाएं 23.04 लाख हेक्टेयर के वर्षा वाले क्षेत्र, जल क्षेत्र और आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों को कवर करती हैं।

- नाबार्ड ने देश के सहकारी बैंकिंग ढांचे का आधार प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को बहु सेवा केंद्रों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तपोषण की भी घोषणा की।
- नाबार्ड ने 13 जुलाई को अपने 39वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर अपनी पहली 'डिजिटल चौपाल' आयोजित की। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई,1982 को की गई थी।

जल संभर कार्यक्रमः जल संभर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण एवं मृदा संरक्षण हेतु वर्षा के जल के बहाव की गति को कम कर, जल में मृदा अवसाद को कम करना तथा वर्षा की बूँदों को भूमि की सतह पर रोककर मिट्टी के कटाव के साथ जल को संरक्षित करना है।

जीके फैक्ट

✧ केंद्रीय वित्त मंत्री के 1999-2000 की बजट घोषणा के अनुसार नाबार्ड के अंतर्गत जल संभर विकास फंड (Watershed Development Fund- FWD) स्थापित किया गया। इसमें कृषि मंत्रालय, भारत सरकार और नाबार्ड प्रत्येक के द्वारा 100 करोड़ रुपए का शुरुआती अंशदान किया गया था।

वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020

प्रोपर्टी कंसल्टेंट 'कुशमैन एंड वेकफील्ड' (Cushman & Wakefield) द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार, भारत वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में तीसरे स्थान पर है।

महत्वपूर्ण तथ्यः चीन और अमेरिका शीर्ष दो स्थान पर बरकरार हैं। यूरोप, अमेरिका और एशिया-प्रशांत के 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की वार्षिक रैंकिंग में भारत इस साल शीर्ष-3 देशों में है और परिचालन स्थिति और लागत प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से वैश्विक स्तर पर आगामी विनिर्माण हब है।

- सूचकांक में राजनीतिक और आर्थिक जोखिमों के निम्न स्तर को प्रस्तुत करने वाले देशों को उच्च स्थान दिया गया है।
- लागत परिदृश्य में उन देशों को उच्च स्कोर दिया गया है, जो लागत में कमी पर अधिक जोर देते हैं तथा जहां श्रम सहित परिचालन लागत कम होती है।
- लागत के लिहाज से चीन और वियतनाम के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। हालांकि, भारत जोखिम परिदृश्य में 30वें स्थान पर है।
- सूचकांक प्रत्येक देश को विनिर्माण को प्रभावित करने वाले 20 कारकों पर स्कोर करता है, जो तीन अंतिम भारित रैंकिंग (weighted rankings) 'परिचालन स्थिति', 'लागत' और 'जोखिम' को कवर करते हैं।

जीके फैक्ट

✧ भारत वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2019 में चौथे स्थान पर था।

भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम

2 जुलाई, 2020 को 'सतत विकास आधार स्तंभ' (Sustainable Growth Pillar) के संयुक्त कार्य समूह की बैठक में 'भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम' (India Energy modeling Forum) का शुभारंभ किया गया।

उद्देश्यः महत्वपूर्ण ऊर्जा और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया से भारत सरकार को अवगत कराना।

सतत विकास आधार स्तंभः यह 'नीति आयोग' और 'अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी' (US-AID) की सह-अध्यक्षता वाला मंच है, जो तीन प्रमुख गतिविधियों ऊर्जा डेटा प्रबंधन, ऊर्जा मॉडलिंग प्रबंधन और कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों के सहयोग पर जोर देता है।

महत्वपूर्ण तथ्यः 'भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम' मॉडलिंग टीमों, सरकार एवं ज्ञान साझेदारों और वित्त पोषकों के बीच सहयोग में सुधार, विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा तथा उच्च गुणवत्तापरक अध्ययन सुनिश्चित करेगा।

- फोरम विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान अंतराल की पहचान करेगा और भारतीय संस्थानों की क्षमता निर्माण में मदद करेगा।
- शुरुआती स्तर पर नीति आयोग इस फोरम की गतिविधियों का समन्वय करेगा और इसकी शासकीय संरचना को अंतिम रूप देगा। फोरम में ज्ञान साझेदार, डेटा एजेंसियां और संबंधित सरकारी मंत्रालय शामिल होंगे।

जीके फैक्ट

✧ दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ऊर्जा मॉडलिंग फोरम मौजूद हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एनर्जी मॉडलिंग फोरम की स्थापना 1976 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रमुख मॉडलिंग विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाने के लिए की गई थी।

भारत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 रिपोर्ट

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने 13 जुलाई, 2020 को संयुक्त राष्ट्र उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच (High level political Forum-HLPF) पर सतत विकास पर 'भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020' (Voluntary National Review-VNR) रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्ट का शीर्षकः 'कार्रवाई का एक दशकः एसडीजी को वैश्विक से स्थानीय स्तर पर ले जाना' (Decade of Action: Taking SDGs from Global to Local)।

उद्देश्यः 2030 एजेंडा को लागू करने में मिली सफलताओं, चुनौतियों और सबक सहित प्राप्त अनुभवों को साझा करना।

महत्वपूर्ण तथ्यः संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के तत्वावधान में 'उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच' 2030 एजेंडा और17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) म प्रगति की निरंतरता और समीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंच है। यह समीक्षा स्वैच्छिक रूप से सदस्य देशों द्वारा खुद की जाती है।

- समीक्षा रिपोर्ट में पूरे समाज को सम्मिलित करने की भावना को शामिल करने की नीति आयोग की 'राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर' पर 'एसडीजी को अपनाने और उस पर निगरानी करने' की कोशिशों को प्रस्तुत किया गया है।
- नीति और उचित माहौल को सक्षम करने, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण, और कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करने के लिए भारत के दृष्टिकोण की विस्तृत चर्चा की गई है।
- समीक्षा में 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ' तथा 'लागत और वित्तपोषण' को सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के सुदृढ़ीकरण के दो उत्तोलकों (बल प्रदान करने वाले) के रूप में पेश किया गया है।

जीके फैक्ट

✧ नीति आयोग ने वर्ष 2017 में भारत की पहली स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

केंद्रीय क्षेत्र योजना-कृषि अवसंरचना कोष

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई, 2020 को नई देशव्यापी 'केंद्रीय क्षेत्र योजना-कृषि अवसंरचना कोष' को मंजूरी प्रदान की।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से, फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी।

- योजना के अंतर्गत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा एक लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, किसानों और केंद्रीय/राज्य एजेंसियों या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को उपलब्ध कराई जाएगी।
- ऋण का वितरण चार वर्षों में किया जाएगा, चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और अगले तीन वित्तीय वर्ष में प्रत्येक वर्ष 30,000 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है।
- इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत, सभी प्रकार के ऋणों में प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी।
- कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।
- इस योजना की समय-सीमा वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर वित्तीय वर्ष 2029 तक 10 वर्ष के लिए होगी।

फिश क्रायोबैंक

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने 10 जुलाई, 2020 को 'राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस' के अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में 'फिश क्रायोबैंक्स' (Fish Cryobanks) स्थापित करने की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्यः इसे राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBFGR) के सहयोग से स्थापित किया जाएगा।

- फिश क्रायोबैंक, मत्स्य किसानों को वांछित मछली प्रजाति के 'शुक्राणुओं' की सभी समय उपलब्धता (All time availability) की सुविधा प्रदान करेगा।
- NBFGR द्वारा विकसित 'क्रायोमिल्ट' तकनीक 'फिश क्रायोबैंक' की स्थापना में सहायक हो सकती है, जो किसी भी समय 'हैचरी' (कृत्रिम परिस्थितियों में अंडे दिए जाने का स्थान) में मछली के शुक्राणुओं की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करेगी।
- यह दुनिया में पहली बार होगा जब 'फिश क्रायोबैंक' की स्थापना की जाएगी।

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्डः देश में मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से 2006 में 'राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड' (NFDB) को मत्स्य विभाग (मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था।

लाभः मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए देश में मत्स्य पालन क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, जिससे मत्स्य किसानों के बीच समृद्धि बढ़ सकती है।

जीके फैक्ट

✧ राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना दिसंबर 1983 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में की गई थी। यह लखनऊ में स्थित है।

विश्व बैंक 'एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम'

विश्व बैंक और भारत सरकार ने 6 जुलाई, 2020 को 'एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम' के लिए 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए।

उद्देश्यः कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वित्त का प्रवाह बढ़ाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

महत्वपूर्ण तथ्यः विश्व बैंक का 'एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम' लगभग 1.5 मिलियन लाभप्रद एमएसएमई की नकदी और ऋण संबंधी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

- भारत सरकार वित्तीय सेक्टर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तरलता का प्रवाह एनबीएफसी की ओर सुनिश्चित करने पर फोकस कर रही है।
- विश्व बैंक समूह, जिसमें उसकी निजी क्षेत्र शाखा अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) भी शामिल हैं, एमएसएमई सेक्टर की रक्षा के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों में इन कदमों के जरिए आवश्यक सहयोग देगा- तरलता को उन्मुक्त करना, एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंक (एसएफबी) की वित्त पोषण क्षमता बढ़ाना तथा वित्तीय नवाचारों को सक्षम करना।
- अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) से मिलने वाले 750 मिलियन डॉलर के ऋण की परिपक्वता अवधि 19 साल है, जिसमें 5 साल की मोहलत अवधि भी शामिल है।

जीके फैक्ट

✧ विश्व बैंक ने एमएसएमई परियोजना सहित भारत के आपातकालीन कोविड-19 उपायों में आवश्यक सहयोग देने के लिए अब तक 2.75 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

चल दर बचत ऋणपत्र, 2020 (कराधीन) योजना

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2020 से 'चल दर बचत ऋणपत्र, 2020 (कराधीन) योजना' {Floating Rate Savings Bonds 2020 (Taxable) Scheme} शुरू करने का फैसला किया है, जिससे सुरक्षित सरकारी साधनों में निवेश करने का अवसर मिलेगा।

महत्वपूर्ण तथ्यः नई योजना को 7.75% बचत (कराधीन) ऋणपत्र, 2018 के स्थान पर लाया गया है, जिसे 28 मई, 2020 को वापिस ले लिया गया था।

- सात साल के ऋणपत्र (बॉन्ड) पर ब्याज का भुगतान हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को अर्ध-वार्षिक रूप से किया जाएगा।
- 1 जनवरी, 2021 को ब्याज का भुगतान 7.15% की दर से किया जाएगा। अगले छमाही के लिए दर हर छः महीने में पुनः नियोजित (reset) की जाएगी। पहला नियोजन 1 जनवरी 2021 को होगा।
- बॉन्ड जारी करने की तिथि से सात साल की समाप्ति पर चुकाया जाएगा। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों को निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए समय से पहले भुगतान की अनुमति दी जाएगी।
- बॉन्ड पर ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सरकार की ओर से बॉन्ड जारी करेगा। बॉन्ड भारत में रहने वाले व्यक्ति और एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) द्वारा लिया जा सकता है।

जीके फैक्ट

✧ आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) एक इकाई है, जिसे एक व्यक्ति के समान कुछ छूट दी गई है। इस अधिनियम में, हिंदू जातीयता के लोग (हिंदू या सिख या बौद्ध या जैन) एक साथ आ सकते हैं और इकाई बनाकर अच्छी मात्रा में कर बचा सकते हैं।

चंबल के विशाल बीहड़ क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने की योजना

केंद्र सरकार ने 26 जुलाई, 2020 को विश्व बैंक के सहयोग से मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल के विशाल बीहड़ (ravine) क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में बदलने का फैसला किया है, इसके लिए एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट एक महीने में तैयार की जाएगी।

महत्वपूर्ण तथ्यः बीहड़ की 3 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि खेती योग्य नहीं है। यदि इस क्षेत्र में सुधार किया जाता है, तो इससे ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में बीहड़ क्षेत्र के एकीकृत विकास में मदद मिलेगी।

- स्थानीय रूप से बीहड़ के नाम से प्रचलित चम्बल घाटी भारत का सबसे निम्नीकृत भूखण्ड है। चम्बल के बीहड़ में बड़े नाले और अत्यधिक विच्छेदित घाटी शामिल है। जिसका विकास मुख्य रूप से चम्बल नदी के दोनों किनारों पर हुआ है।
- बीहड़ अर्ध-शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में बहने वाली नदियों और प्रवाह द्वारा निरंतर ऊर्ध्वाधर कटाव के परिणामस्वरूप बनते हैं।
- परियोजना से न केवल कृषि विकास और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। ■■

राष्ट्रीय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की।

उद्देश्यः 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के साथ विद्यालय-पूर्व शिक्षा से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का सार्वभौमिकरण।

महत्वपूर्ण तथ्यः स्कूल पाठ्यक्रम के 10 + 2 ढांचे की जगह 5 + 3 + 3 + 4 का नया पाठ्यक्रम, जो क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14, और 14-18 आयु के बच्चों के लिए है। नई प्रणाली में तीन साल की आंगनवाड़ी/ प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी।

- कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा / क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई तथा इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का प्रावधान।
- मंत्रालय का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' करने तथा ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 'राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन' की स्थापना का प्रावधान।
- एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल (Early Childhood care) और शिक्षा के लिए एक 'राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा' विकसित करने तथा उच्च शिक्षा में जीईआर को 2035 तक 50% तक बढ़ाये जाने का प्रावधान।
- 'अध्यापक शिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2021' तैयार किया जाएगा। वर्ष 2030 तक, शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होगी।
- देश में वैश्विक मानकों के सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के मॉडलों के रूप में आईआईटी, आईआईएम के समकक्ष 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' स्थापित किए जाएंगे।
- एमफिल पाठ्यक्रम को बंद करने, स्वतंत्र 'राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण' (SSSA) के गठन तथा विधि और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को एकल नियामक 'भारत उच्च शिक्षा आयोग' (एचईसीआई) द्वारा शासित करने का प्रावधान।

जीके फैक्ट

- मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 में लाया गया था और 1992 में संशोधित किया गया था। जून 2017 में डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

नीति आयोग की पहल 'एआईएम आईक्रेस्ट'

नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (AIM) ने 30 जुलाई, 2020 को भारत में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरह की पहली पहल 'एआईएम आईक्रेस्ट' (Atal Innovation Mission Incubator Capabilities enhancement program for a Robust Ecosystem- AIM iCREST) लॉन्च की।

उद्देश्यः देश भर के इनक्यूबेटर इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना और समग्र प्रगति हेतु सक्षम बनाना।

महत्वपूर्ण तथ्यः अटल नवाचार मिशन ने इस पहल के लिए 'बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन' और 'वाधवानी फाउंडेशन' के साथ साझेदारी की है। ये साझेदारी वैश्विक विशेषज्ञता प्रदान करेगी और एआईएम के इनक्यूबेटर नेटवर्क के लिए सर्वोत्तम पद्धतियां उपलब्ध कराएंगी।

- इस पहल के तहत, एआईएम के इनक्यूबेटरों को विस्तारित करने के साथ-साथ इनक्यूबेटर उद्यम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित समर्थन प्रदान किया जाएगा, जो उन्हें उनके प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करेगा।
- इसके अलावा प्रौद्योगिकी संचालित प्रक्रियाओं और प्लेटफार्मों के माध्यम से, उद्यमियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
- कार्यक्रम इनक्यूबेटर क्षमता निर्माण से परे स्टार्ट-अप उद्यमियों को वर्तमान महामारी संकट को देखते हुए ज्ञान सृजन और प्रसार में समर्थन करने के साथ-साथ मजबूत और सक्रिय नेटवर्क विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने 28 जुलाई, 2020 को डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020' जारी की।

महत्वपूर्ण तथ्यः रिपोर्ट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अभिनव तरीकों को समाहित किया गया है।

- मंत्रालय ने 'दीक्षा मंच', 'स्वयं प्रभा टीवी चौनल', ऑन एयर- 'शिक्षा वाणी', दिव्यांगों के लिए एनआईओएस द्वारा विकसित 'डेजी' (DAISY), 'ई-पाठशाला' आदि कई परियोजनाएं शुरू की हैं।
- राज्य सरकारों द्वारा की गई कुछ प्रमुख डिजिटल पहल में राजस्थान में 'स्माइल' (सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट), जम्मू में 'प्रोजेक्ट होम क्लासेस', छत्तीसगढ़ में 'पढ़ाई तुहार दुवार' (आपके द्वार पर शिक्षा), बिहार में 'उन्नयन' पहल पोर्टल और ऐप के माध्यम से शिक्षा, दिल्ली का मिशन 'बुनियाद', मेघालय का 'ई-स्कॉलर पोर्टल' शामिल हैं।
- खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी और खराब बिजली सुविधा वाले सुदूर क्षेत्रों में समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों जैसे ओडिशा, मध्य प्रदेश (दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के तहत), दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव ने बच्चों को घर पर पाठ्य-पुस्तकों का वितरण किया किया है।

जीके फैक्ट

✧ गोवा ने राज्य में प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 'एम्बाइब' से साझेदारी की है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय प्रबंधन सूचकांक

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 24 जुलाई, 2020 को 'ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय प्रबंधन सूचकांक' जारी किया।

उद्देश्यः ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उच्च स्तरीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

महत्वपूर्ण तथ्यः सूचकांक में निम्न मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन को रैंकिंग प्रदान की जाएगी।

1. वार्षिक योजना तैयार करना, वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान लगाना, खर्च के लिए राज्य के हिस्से को शीघ्र जारी करना, धनराशि का समय पर उपयोग करना और उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करना आदि;
2. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का इष्टतम कार्यान्वयन;
3. मनरेगा हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का इष्टतम कार्यान्वयन;
4. आंतरिक लेखा-परीक्षा;
5. और सामाजिक लेखा-परीक्षा।

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों में ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए लगभग 1, 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जीके फैक्ट

✧ मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 90,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि जारी की है।

नीति आयोग आकांक्षी जिला रैंकिंग

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले ने फरवरी-जून 2020 की अवधि के लिए सरकारी थिंक-टैंक नीति आयोग योग द्वारा जुलाई 2020 में जारी आकांक्षी जिला रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः रि-भोई (मेघालय) और बहराइच (उत्तर प्रदेश) को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि नवादा (बिहार) को चौथा और मोगा (पंजाब) को पांचवें स्थान पर रखा गया है।

- डेल्टा रैंकिंग में इस वर्ष फरवरी-जून के दौरान छह विकासात्मक क्षेत्रों में 112 से अधिक आकांक्षी जिलों द्वारा की गई वृद्धिशील प्रगति का आकलन किया गया है।
- स्वास्थ्य और पोषण; शिक्षा; कृषि और जल संसाधन; वित्तीय समावेशन; कौशल विकास और बुनियादी ढांचा जैसे विकास के क्षेत्रों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है।

जीके फैक्ट

✧ जनवरी 2018 में शुरू किए गए 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' का उद्देश्य उन जिलों में बदलाव करना है, जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति दिखाई है और जो अल्प-विकसित क्षेत्र हैं।

सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन

रक्षा मंत्रालय ने 23 जुलाई, 2020 को युद्धक इकाई के अतिरिक्त सेना के सभी क्षेत्रों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन (पीसी) प्रदान करने के लिए औपचारिक मंजूरी प्रदान की।

महत्वपूर्ण तथ्यः सेना की सभी 10 शाखाओं में शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया जाएगा, जिनमें वे वर्तमान में सेवारत हैं - सैन्य वायु रक्षा (एएडी), सिग्नल, इंजीनियर, सैन्य विमानन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, सैन्य सेवा कोर (ASC), सैन्य आयुध कोर (AOC), और जज और एडवोकेट जनरल (JAG), सैन्य शिक्षा कोर (AEC) तथा इंटेलिजेंस कोर।

- यह आदेश फरवरी 2020 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया गया था कि महिला सेना अधिकारियों को युद्धक इकाई के अलावा अन्य सभी सेवाओं में स्थायी कमीशन और कमांड पोस्टिंग दी जाए।

जीके फैक्ट

✧ स्थायी कमिशन के तहत कोई भी अधिकारी सेवानिवृत्ति की उम्र तक सेना में सेवा दे सकता है और इसके बाद वह पेंशन का भी हकदार होगा। जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों का कार्यकाल अधिकतम 14 साल का होता है।

भारत की भू-सीमा से लगे देशों से सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध

22 जुलाई, 2020 को भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से भारत के साथ भू-सीमा साझा करने वाले देशों से सार्वजनिक खरीद पर अंकुश लगाने हेतु सामान्य वित्तीय नियम, 2017 में संशोधन हेतु आदेश जारी किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः आदेश के अनुसार भारत की भू-सीमा से लगे देशों की कंपनियां सक्षम प्राधिकरण से पंजीकृत होने पर ही वस्तुओं, परामर्श और गैर-परामर्श सेवा या परियोजना कार्यों की सरकारी खरीद और नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगी।

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा गठित समिति, पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकरण होगी।
- इसके लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक स्वीकृति और गृह मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी मंजूरी भी अनिवार्य होगी। राज्यों को भी इस आदेश का अनुपालन करना होगा।
- सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थाएं, स्वायत्त निकाय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त सार्वजनिक और निजी भागीदारी परियोजनाएं तथा उपक्रम भी इस आदेश के दायरे में आएंगे।
- 31 दिसंबर, 2020 तक कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा आपूर्ति की खरीद सहित कुछ सीमित मामलों में छूट प्रदान की गई है।

संशोधित प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार योजना 2020

केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 17 जुलाई, 2020 को संशोधित प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार योजना, 2020 और वेब पोर्टल www.pmawards.gov.in को लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः संशोधित योजना में चार प्रमुख श्रेणियों- 'जिला प्रदर्शन संकेतक कार्यक्रम', 'नवाचार सामान्य श्रेणी', 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' और 'नमामि गंगे कार्यक्रम' में नामांकन मांगे गए हैं।

- इसमें पहली बार 'नमामि गंगे' कार्यक्रम में जिला स्तर के अधिकारियों के प्रयासों को मान्यता दी जाएगी।
- इस पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 57 अधिसूचित जिला गंगा समितियों (57 जिलों) में से एक जिले को एक पुरस्कार दिया जाएगा।

योजना का विवरणः भारत सरकार ने केन्द्र और राज्य सरकारों के जिलों/ संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को मान्यता देने के लिए वर्ष 2006 में 'प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार योजना' की शुरुआत की थी।

- 'प्राथमिकता कार्यक्रमों', 'नवाचारों' और 'आकांक्षी जिलों' में जिलाधिकारियों के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए वर्ष 2014 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया था।
- जिले के 'आर्थिक विकास' की दिशा में जिलाधिकारियों के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए इस योजना को 2020 में फिर से पुनर्गठित किया गया।

जीके फैक्ट

✧ 31 अक्टूबर, 2020 को सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के केवडिया में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' में यह पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

'भारत में मातृ मृत्यु 2016-18' पर विशेष बुलेटिन

रजिस्ट्रार जनरल के प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली (Sample Registration System) कार्यालय द्वारा जारी 'भारत में मातृ मृत्यु 2016-18' पर विशेष बुलेटिन के अनुसार, भारत के मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) में एक वर्ष में 9 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 2011-13 में 167, 2014-2016 में 130 तथा 2015-17 में 122 से घटकर 2016-18 में 113 रह गया है।

- मातृ मृत्यु दर के प्रमुख संकेतकों में से एक मातृ मृत्यु अनुपात है, जिसे प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु (Maternal death) की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।
- गर्भवती होने पर या गर्भावस्था एवं उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर महिला की मृत्यु 'मातृ मृत्यु' कहलाती है।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) 'लक्ष्य 3.1' का उद्देश्य वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को प्रति 100,000 जीवित जन्मों में 70 से कम तक करना है।
- एसडीजी लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या अब 3 से बढ़कर 5 हो गई है। इन राज्यों में केरल (43), महाराष्ट्र (46) तमिलनाडु (60), तेलंगाना (63) और आंध्र प्रदेश (65) शामिल हैं।
- देश में 11 राज्यों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा निर्धारित एमएमआर के लक्ष्य (प्रति 100,000 जीवित जन्मों में 100 से कम) को प्राप्त किया है, जिसमें सतत विकास लक्ष्य हासिल करने वाले 5 राज्य तथा झारखंड (71), गुजरात (75), हरियाणा (91), कर्नाटक (92), पश्चिम बंगाल (98) और उत्तराखंड (99) शामिल हैं।
- 5 राज्यों छत्तीसगढ़ (159), राजस्थान (164), मध्य प्रदेश के लिए (173), उत्तर प्रदेश (197) और असम (215), में एमएमआर 150 से ऊपर है।

जीके फैक्ट

✧ राजस्थान में एमएमआर में 22 अंकों की अधिकतम गिरावट देखी गई, जबकि उत्तर प्रदेश में 19 अंकों, ओडिशा में 18 अंकों, बिहार में 16 अंकों की गिरावट दर्ज हुई।

आपातकालीन रक्षा खरीद के लिए सरकार की मंजूरी

रक्षा मंत्रालय ने 15 जुलाई, 2020 को एक बार फिर सशस्त्र बलों को बिना किसी अन्य मंजूरी के 300 करोड़ रुपये तक के तत्काल पूंजीगत रक्षा खरीद के लिए आपातकालीन विशेष अधिकार दे दिए हैं। इसी तरह की शक्तियां फरवरी 2019 में बालाकोट हवाई हमले के बाद दी गई थीं।

महत्वपूर्ण तथ्यः उत्तरी सीमाओं पर मौजूदा स्थिति और सशस्त्र बलों को मजबूत करने की आवश्यकता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की एक विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया।

- इस निर्णय के बाद खरीद से जुड़ी समयसीमा कम हो जाएगी और इससे खरीद के लिए छः महीने के भीतर ऑर्डर देना तथा एक साल के भीतर संबंधित वस्तुओं की उपलब्धता की शुरुआत सुनिश्चित होगी।
- ज्ञात हो कि सेना ने पहले ही यूएसए के 'सिग सॉयर' (Sig Sauer) से 72,400 एसआईजी- 716 असॉल्ट राइफलों (SIG-716 assault rifles) और12 लॉन्चर तथा इजरायल से 250 'स्पाइक' एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों के लिए दुबारा आर्डर करने का निर्णय लिया है।

जीके फैक्ट

✧ सशस्त्र बलों को गोला-बारूद और पुर्जों की खरीद के लिए राजस्व मार्ग (revenue route) के तहत उप-प्रमुखों (Vice-Chief) को अलग-अलग वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।

ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा 'प्रज्ञाता' के दिशा-निर्देश जारी

मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 14 जुलाई, 2020 को ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा 'प्रज्ञाता' के दिशा-निर्देश जारी किए।

महत्वपूर्ण तथ्यः प्रज्ञाता दिशा-निर्देशों में ऑनलाइन/ डिजिटल शिक्षा के आठ चरण- योजना (Plan), समीक्षा (Review), व्यवस्था (Arrange), मार्गदर्शन (Guide) याक या बात (Yalk), असाइन (Assign, ट्रैक (Track), सराहना (Appreciate) शामिल हैं। ये आठ चरण उदाहरणों के साथ चरणबद्ध तरीके से डिजिटल शिक्षा की योजना और कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करते हैं।

- दिशा-निर्देशों में छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का समय निर्धारित किया गया है। प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए प्रतिदिन अधिकतम तीस मिनट; कक्षा 1 से आठ तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 30-45 मिनट के दो सत्र से ज्यादा नहीं होंगे; कक्षा 9 से12वीं तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 30-45 मिनट के अधिकतम चार सत्र निर्धारित किए गए हैं।
- ये दिशा-निर्देश विद्यालय प्रमुखों, शिक्षकों,अभिभावकों और छात्रों सहित हितधारकों के विविध समूहों के लिए प्रासंगिक और उपयोगी होंगे।

छत्तीसगढ़ द्वारा भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायाल ने लंबित मामलों को सुलझाने के लिए 11 जुलाई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः राज्य उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला अदालतें और तहसील अदालतें इस ई-लोक अदालत का हिस्सा थी।

- लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है, जिसमें अदालत में लंबित या मुकदमेबाजी पूर्व विवादों/ मामलों का निपटारा किया जाता है।
- लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। उक्त अधिनियम के तहत, लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को एक सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है।
- यदि पक्षकार लोक अदालत के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इस तरह के निर्णय के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वे आवश्यक प्रक्रिया का पालन करके मामला दर्ज करके उचित क्षेत्राधिकार के न्यायालय से संपर्क करके मुकदमेबाजी शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं।

जीके फैक्ट

✧ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) अन्य विधिक सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का आयोजन करता है।

श्री पदमनाभस्वामी मन्दिर प्रशासन में त्रावणकोर राजशाही परिवार का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई, 2020 को केरल उच्च न्यायालय के वर्ष 2011 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें उसने तिरुवनंतपुरम में स्थित ऐतिहासिक श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रबंधन और संपत्तियों के प्रशासन के लिए राज्य सरकार को एक ट्रस्ट गठित करने का निर्देश दिया था।

महत्वपूर्ण तथ्यः न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखते हुए कहा कि त्रावणकोर के आखिरी शासक की मौत से शाही परिवार की भक्ति और सेवा को उनसे नहीं छीना जा सकता।

- अंतरिम उपाय के रूप में, तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश मंदिर के मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक प्रशासनिक समिति का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा नीतिगत मामलों पर

प्रशासनिक समिति को सलाह देने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक दूसरी समिति भी गठित की जाएगी।

पृष्ठभूमि: त्रावणकोर और कोचिन के शाही परिवार और भारत सरकार के बीच 1949 में अनुबंध के तहत तय हुआ था कि श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का प्रशासन 'त्रावणकोर के शासक' के पास रहेगा।

- 1991 में त्रावणकोर के अंतिम शासक चिथिरा तिरुनाल बलराम वर्मा के निधन के बाद त्रावणकोर के आखिरी शासक के भाई उत्रादम तिरुनाल मार्तण्ड वर्मा के नेतृत्व में प्रशासकीय समिति के पास मंदिर का प्रबंधन सौंपा गया, जिसके खिलाफ भक्तों ने याचिका दायर कर दी थी।

जीके फैक्ट

- 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर राजघराने द्वारा वर्तमान स्वरूप में इस विशाल मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था, जिसने 1947 में भारतीय संघ के साथ रियासत के एकीकरण से पहले दक्षिणी केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन किया था।

रेलवे का 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य

रेल मंत्रालय ने 2030 तक भारतीय रेलवे को पूरी तरह हरित ऊर्जा से संचालित करने और 'शून्य कार्बन उत्सर्जन' हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 'शून्य कार्बन उत्सर्जन' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेल लाइनों का विद्युतीकरण, ट्रेनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार, स्टेशनों के लिए हरित प्रमाणन, कोचों में जैव शौचालय और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल रेलवे की रणनीति का हिस्सा हैं।

- भारतीय रेलवे ने 40 हजार किमी. से अधिक लाइनों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जो कि कुल बडी लाइनों का 63% है। रेलवे ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 7000 किमी. लाइनों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है।
- भारतीय रेलवे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के रूफ टॉप सोलर पैनल (डेवलपर मॉडल) के माध्यम से 500 मेगा वाट ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए काम कर रहा है।
- इसके अलावा भारतीय रेलवे ने इमारतों और स्टेशनों में एलईडी बल्बों के जरिए 100% प्रकाश व्यवस्था और रेलगाड़ियों में 2,44,000 से अधिक जैव-शौचालय जैसी हरित पहलें शुरू की है।

एशिया की सबसे विशाल रीवा सौर परियोजना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 जुलाई, 2020 को मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की 'एशिया की सबसे विशाल सौर परियोजना' राष्ट्र को समर्पित की।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस परियोजना में एक सौर पार्क (कुल क्षेत्रफल 1500 हेक्टेयर) के अंदर स्थित 500 हेक्टेयर भूमि पर 250-250 मेगावाट की तीन सौर उत्पादन इकाइयां शामिल हैं।

- इस सौर पार्क को 'रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड' ने विकसित किया है। यह परियोजना राज्य के बाहर एक संस्थागत ग्राहक को आपूर्ति करने वाली पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना भी है। अर्थात, यह दिल्ली मेट्रो को अपनी कुल उत्पादन का 24% बिजली देगी जबकि शेष 76% बिजली मध्य प्रदेश के राज्य बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को आपूर्ति की जाएगी।
- रीवा परियोजना सालाना लगभग 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी।

जीके फैक्ट

- नवाचार और उत्कृष्टता के लिए इस परियोजना को 'वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवॉर्ड' (World Bank Group President's Award) भी मिला है। यही नहीं, इसे प्रधानमंत्री द्वारा जारी पुस्तक 'ए बुक ऑफ इनोवेशन: न्यू बिगनिंग्स' (A Book of Innovation: New Beginnings) में भी शामिल किया गया है।

नौवहन सहायता विधेयक 2020 मसौदा जारी

जहाजरानी मंत्रालय ने 10 जुलाई, 2020 को सार्वजनिक परामर्श के लिए नौवहन सहायता विधेयक 2020 का मसौदा जारी किया।

उद्देश्य: सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं, तकनीकी विकास और समुद्री नौवहन के क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को समाहित करने हेतु 'दीपस्तंभ अधिनियम, 1927' (Lighthouse Act, 1927) को प्रतिस्थापित करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: मसौदा विधेयक पोत परिवहन सेवाओं, प्रशिक्षण और प्रमाणन तथा उन अंतरराष्ट्रीय संधियों जिन पर भारत हस्ताक्षर कर चुका है, के तहत अन्य दायित्वों के निर्वहन के लिए 'दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय' (Directorate General of Lighthouses and Lightships) को अतिरिक्त अधिकार और शक्तियां प्रदान करता है।

- इसमें प्राचीन धरोहरों के रूप में मौजूद दीप स्तंभों की पहचान करने और उनका विकास करने की भी व्यवस्था है।
- नौवहन में बाधा डालने और किसी तरह का नुकसान पहुंचाने तथा निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर दंडात्मक व्यवस्थाओं और ऐसे कार्यों को अपराध की श्रेणी में रखने के लिए एक नई सूची बनाई गई है।

नौवहन सहायता: दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय ने भारतीय जल में सुरक्षित यात्रा के लिए, समुद्री नौवहन सहायता को दृश्य और रेडियो सहायता के रूप में वर्गीकृत किया है। दृश्य सहायता में दीपस्तम्भ, दीपपोत, पानी पर तैरने वाला चिह्न (buoys) हैं। रेडियो सहायता DGPS, RACONs आदि हैं। ये सभी सहायता निष्क्रिय प्रकृति की हैं, न कि उपयोगकर्ता संवादात्मक (Not user interactive)।

जीके फैक्ट

✧ दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय जहाजरानी मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय है। यह भारतीय तट के साथ समुद्री नौवहन के लिए सामान्य सहायता प्रदान करता है। निदेशालय का मुख्यालय नोएडा में स्थित है।

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत मंगोलियाई कंजुर का प्रकाशन

जुलाई 2020 में संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (National Mission for Manuscripts) के तहत मंगोलियाई कंजुर के 108 अंकों के पुनर्मुद्रण करने परियोजना आरंभ की है। मार्च, 2022 तक ये सभी अंक प्रकाशित किए जाएंगे।

उद्देश्यः पांडुलिपियों में प्रतिष्ठापित (enshrined) ज्ञान को शोधकर्ताओं, विद्वानों एवं बड़े पैमाने पर आम लोगों तक प्रसारित करने हेतु दुर्लभ एवं अप्रकाशित पांडुलिपियों को प्रकाशित करना।

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशनः भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2003 में पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान के दस्तावेजीकरण, संरक्षण एवं प्रसार करने के अधिदेश (mandate) के साथ लांच किया गया था।

मंगोलियाई कंजुरः 108 अंकों का बौद्ध धर्म वैधानिक ग्रंथ 'मंगोलियाई कंजुर' मंगोलिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ माना जाता है। मंगोलियाई भाषा में 'कंजुर' का अर्थ होता है 'संक्षिप्त आदेश' जो विशेष रूप से भगवान बुद्ध के शब्द होते हैं।

- मंगोलियाई बौद्धों द्वारा मंदिरों में कंजुर की पूजा की जाती है मंगोलियाई कंजुर को तिब्बती भाषा से अनुवादित किया गया है। कंजुर की भाषा 'शास्त्रीय मंगोलियाई' (Classical Mongolian) है।

जीके फैक्ट

✧ भारत ने 1955 में मंगोलिया के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए।

एनएचएआई करेगा राजमार्ग दक्षता आकलन और रैंकिंग

6 जुलाई, 2020 को सड़कों को बेहतरीन बनाने के अपने प्रयासों के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीनस्थ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने देश भर में राजमार्गों की दक्षता का आकलन करने के साथ-साथ उनकी रैंकिंग करने का भी निर्णय लिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: आकलन के मानदंड विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं और अध्ययनों पर आधारित हैं। मानदंडों को मुख्यत: तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है: राजमार्ग की दक्षता (45%), राजमार्ग पर सुरक्षा (35%) और उपयोगकर्ता सेवाएं (20%)।

- इसके अलावा, आकलन करते समय परिचालन गति, टोल प्लाजा पर लगने वाला समय, सड़क संकेतक, सड़क चिन्ह, दुर्घटना की दर, किसी घटना से निपटने में लगने वाला समय, क्रैश बैरियर, रोशनी, उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली की उपलब्धता, स्वच्छता, वृक्षारोपण, और ग्राहक संतुष्टि जैसे कई महत्वपूर्ण मानदंडों पर भी विचार किया जाएगा।
- कॉरिडोर यानी गलियारों की रैंकिंग त्वरित रूप से परिवर्तनशील होगी। समस्त गलियारों की समग्र रैंकिंग के अलावा बीओटी (Build Operate transfer), एचएएम (The Hybrid Annuity Model) और ईपीसी परियोजनाओं के लिए भी अलग-अलग रैंकिंग की जाएगी।

सस्ते किराये की आवासीय परिसर उप-योजना

आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 31 जुलाई, 2020 को सस्ते किराये के आवासीय परिसर (Affordable Rental Housing Complexes-ARHC) नॉलेज पैक जारी किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः नॉलेज पैक में देश में शहरी प्रवासियों को रहने की आसानी प्रदान करने के लिए राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर शामिल हैं।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों को आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए 8 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 'सस्ते किराये की आवासीय परिसर उप-योजना' को मंजूरी प्रदान की थी।
- इस योजना को देश में दो मॉडलों के माध्यम से लागू किया जाएगा। पहले मॉडल के तहत मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली आवासीय परिसरों को 25 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा ARHC में परिवर्तित किया जाएगा।
- दूसरे मॉडल के तहत ARHC का निर्माण, संचालन और रखरखाव सार्वजनिक या निजी संस्थाओं द्वारा 25 वर्षों की अवधि के लिए अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर किया जाएगा।

मनोदर्पण' पहल

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने 21 जुलाई, 2020 को नई दिल्ली में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती के लिए मनो-सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 'मनोदर्पण' पहल शुरू की।

महत्वपूर्ण तथ्य: उन्होंनें' मनोदर्पण' पहल के हिस्से के रूप में एक राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन (8448440632), मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पोर्टल पर 'मनोदर्पण' का एक विशेष वेब पेज और 'मनोदर्पण' पर एक पुस्तिका का भी उद्घाटन किया।

- यह पहल छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को कठिन परिस्थिति में शक्ति, सुझाव और सहायता प्रदान करेगी।
- इस पहल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्म-निर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया है। शिक्षा क्षेत्र के लिए उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मानव पूंजी को मजबूत बनाने की कोशिश के रूप में इस अभियान में मनोदर्पण पहल को शामिल किया गया है। ■■

अंतरराष्ट्रीय

वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा 21 जुलाई, 2020 को जारी व्यापक 'वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020' के अनुसार एक दशक के दौरान वन क्षेत्र में इजाफा करने वाले दस देशों में भारत तीसरे स्थान पर है।

महत्वपूर्ण तथ्यः दुनिया में कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 31% है।

- 2010-2020 के दौरान जिन 10 देशों में वन क्षेत्र में औसतन सालाना इजाफा हुआ है, उनमें पहले स्थान पर चीन है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत, चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया शामिल हैं। पूरे विश्व के वन क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी 2 फीसदी है। एशियाई महाद्वीप ने 2010-20 में 1.17 मिलियन हेक्टेयर/ प्रतिवर्ष की वृद्धि दर से वन क्षेत्र में सबसे अधिक शुद्ध इजाफा किया।

भारत की स्थितिः एक दशक के दौरान, भारत में औसतन हर साल 0.38% वन क्षेत्र में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हालांकि, प्राकृतिक रूप से उपजने वाले वन क्षेत्र में इजाफा नहीं हो रहा है।

- भारत में स्थानीय निवासी, आदिवासी और स्वदेशी समुदायों द्वारा देखरेख किए जा रहे वन क्षेत्र वर्ष 1990 में शून्य थे, जो 2015 में बढ़ कर लगभग 2.5 करोड़ हेक्टेयर हो गए। वन क्षेत्रों की वजह से रोजगार पाने वाले लगभग 12.5 मिलियन लोगों में से 50 फीसदी यानी लगभग 6.23 मिलियन लोग भारत से हैं।

जीके फैक्ट

✧ 1990 के बाद से, एफएओ हर पांच साल में यह व्यापक आकलन जारी करता है। इस रिपोर्ट में सभी सदस्य देशों में जंगल की स्थिति और उनके प्रबंधन का आकलन किया जाता है।

यूएई परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला अरब देश

1 अगस्त, 2020 को बराकाह परमाणु संयंत्र की पहली इकाई के परिचालन में आने की घोषणा के साथ संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः अबू धाबी से 280 किमी दूर स्थित, इस परियोजना से देश की ऊर्जा जरूरतों का 25 प्रतिशत कवर करने की संभावना है। संयंत्र में कुल 5,600 मेगावाट क्षमता वाली चार इकाइयां शामिल होंगी।

- संयंत्र से हर साल 21 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को रोका जा सकता है, जो प्रति वर्ष सड़कों से 3.2 मिलियन कारों को हटाने के बराबर है।
- वर्तमान में, देश की लगभग सभी ऊर्जा जरूरतें गैस से चलने वाले बिजली संयंत्रों और सौर क्षेत्रों से पूरी होती है।
- यूएई अरब दुनिया का पहला देश और वैश्विक स्तर पर 33वां देश है, जिसने सुरक्षित, स्वच्छ और विश्वसनीय बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित किया है।
- यूएई ने 2008 में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं का खुलासा किया था।

जीके फैक्ट

✧ यूएई दुनिया के सबसे बड़े जीवाश्म ईंधन उत्पादकों में से एक है।

गांधी-किंग एक्सचेंज एक्ट

29 जुलाई, 2020 को एक महत्वपूर्ण अमेरिकी कांग्रेस समिति द्वारा नागरिक अधिकारों के पैरोकार जॉन लेविस द्वारा लिखित एक विधेयक 'गांधी-किंग एक्सचेंज एक्ट' पारित किया गया।

उद्देश्यः महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देना।

महत्वपूर्ण तथ्यः भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसी अमी बेरा द्वारा अनुमोदित इस विधेयक से अमेरिका के विदेश विभाग को भारत सरकार के साथ मिलकर दोनों देशों के शोधार्थियों हेतु मोहनदास करमचंद गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत पर केंद्रित वार्षिक शैक्षिक मंच स्थापित करने का अधिकार मिल जायेगा।

- विधेयक अहिंसा के सिद्धांतों के आधार पर संघर्ष समाधान पर एक पेशेवर विकास प्रशिक्षण पहल विकसित करेगा और भारत में सामाजिक, पर्यावरण, और स्वास्थ्य प्राथमिकताओं हेतु एक फाउंडेशन स्थापित करेगा।
- 2009 में, जॉन लेविस के नेतृत्व में एक कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने डॉ. किंग की भारत की तीर्थयात्रा की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत का दौरा किया था। उन्होंने इस यात्रा से प्रेरित होकर इस विधेयक को तैयार किया।

जीके फैक्ट

✧ जॉन लेविस न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में, बल्कि दुनिया भर में मानव अधिकारों, समानता और न्याय और सभी के लिए लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी। उनका 17 जुलाई को निधन हो गया था।

दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च

दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य संचार उपग्रह निजी ऑपरेटर 'स्पेसएक्स' द्वारा 22 जुलाई, 2020 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: सियोल के 'रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन' (DAPA) के अनुसार उपग्रह को एक फाल्कन-9 रॉकेट से फ्लोरिडा के केप कनवेरल सैन्य हवाई स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया।

- इस 'एएनएएसआईएस-II' (ANASIS-II) उपग्रह का उद्देश्य दक्षिण कोरिया द्वारा अपने चिर प्रतिद्वंदी परमाणु-सम्पन्न उत्तर कोरिया के खिलाफ अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाना है, जिसने 1950 में इस पर आक्रमण किया था।
- इस उपग्रह के दो सप्ताह में 36,000 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचने की संभावना है और परीक्षण के बाद अक्टूबर 2020 में दक्षिण कोरिया की सेना इसकी व्यवस्था का जिम्मा संभालेगी।

जीके फैक्ट

✧ इस लॉन्च के साथ दक्षिण कोरिया एक सैन्य संचार उपग्रह ताकत रखने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है, जो इसे स्थायी और सुरक्षित सैन्य संचार प्रदान करेगा।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापना रूपरेखा संशोधन लागू

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की स्थापना के रूपरेखा समझौते में संशोधन के 15 जुलाई, 2020 से लागू होने के बाद संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के आईएसए में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

उद्देश्य: सौर ऊर्जा के तीव्र प्रसार के जरिये पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने में योगदान करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: कटिबंधों से परे आईएसए की सदस्यता के सार्वभौमीकरण के लिये गठबंधन की महासभा की 3 अक्टूबर, 2018 को हुई पहली बैठक में रूपरेखा समझौते में संशोधन को अंगीकार किया गया था, ताकि सदस्यता के दायरे को बढ़ाया जाए और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसमें शामिल हो सकें।

- 30 जुलाई, 2020 तक 87 देशों ने आईएसए रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इनमें से 67 देशों ने अनुमोदन पत्र सौंपा है।
- आईएसए को नवंबर 2015 में पेरिस में कॉप-21 सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था।
- यह ऐसे 122 देशों का गठबंधन है, जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क और मकर उष्णकटिबंधों के बीच स्थित हैं।

जीके फैक्ट

✧ यह पहला समझौता आधारित अंतरराष्ट्रीय अंतरसरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय भारत में गुरुग्राम में स्थित है।

सतत विकास रिपोर्ट 2020

30 जून, 2020 को सतत विकास समाधान नेटवर्क (SDSN) और बर्टल्समैन स्टिफटंग (Bertelsmann Stiftung) द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2020 जारी की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, 2020 में 166 देशों को शामिल किया गया है।

- इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान (स्कोर-84.7) प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात डेनमार्क दूसरे, फिनलैंड तीसरे, फ्रांस चौथे तथा जर्मनी पांचवें स्थान पर रहा।
- इस सूचकांक में भारत को 117वां (स्कोर 61.9) स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के पड़ोसी देशों में भूटान को 80वां, श्रीलंका को 94वां, नेपाल को 96वां, बांग्लादेश को 109वां, तथा पाकिस्तान को 134वां स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सबसे अंतिम स्थान (166वें) पर है। दक्षिण सूडान 165वें, चाड 164वें तथा सोमालिया 163वें स्थान पर रहे।
- विभिन्न देशों को 17 वैश्विक लक्ष्यों के कार्यान्वयन के मामले में छह व्यापक परिवर्तनों- शिक्षा और कौशल, स्वास्थ्य और कल्याण, स्वच्छ ऊर्जा और उद्योग, सतत भूमि उपयोग, टिकाऊ शहरों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी गई है।

जीके फैक्ट

✧ सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में भारत 115वें तथा 2018 में 112वें स्थान पर था।

2064 में दुनिया की आबादी चरम पर: लांसेट अध्ययन

15 जुलाई, 2020 को लांसेट जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 2064 में दुनिया की आबादी 9.73 बिलियन हो जाएगी, जो आबादी का चरम होगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसके बाद अगले 36 सालों में यानी सदी के अंत तक (वर्ष 2100 तक) यह आबादी घटकर 8.79 बिलियन रह जाएगी।

- इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स और वाशिंगटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन में 2018-2100 की अवधि के लिए 195 देशों को शामिल किया गया।
- 2100 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी (1.09 बिलियन) वाला देश होगा। भारत के बाद नाइजीरिया दूसरे (791 मिलियन), चीन तीसरे (732 मिलियन), अमेरिका चौथे (336 मिलियन) और पाकिस्तान पांचवें स्थान (248 मिलियन) पर होगा।
- 2048 में भारत की जनसंख्या चरम पर (1.6 बिलियन) होगी, इसके बाद यह लगातार घटकर 2100 में 1.09 बिलियन हो जाएगी। सदी के अंत तक 2.37 बिलियन लोग 65 साल से अधिक उम्र के होंगे जबकि 20 साल से कम उम्र के युवाओं की आबादी 1.70 बिलियन होगी।

साइबर सुरक्षा पर भारत–इजरायल समझौता

कोरोना वायरस महामारी के कारण तेजी से डिजिटलीकरण के बीच साइबर खतरों से निपटने के लिए भारत और इजरायल ने सहयोग को और अधिक विस्तारित करने हेतु 15 जुलाई, 2020 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इकाई 'इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम' (CERT-In) और इजरायल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय (INCD) के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

- समझौता दोनों पक्षों के बीच परिचालन और क्षमता निर्माण में सहयोग को बढ़ाएगा। इसके अलावा समझौता सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने हेतु साइबर खतरों पर सूचनाओं तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का नियमित पारस्परिक आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

जीके फैक्ट

- भारत और इजरायल जनवरी 2018 से साइबर क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं, इसलिए एक नया समझौता दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहयोग प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करता है।

विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति 2020 रिपोर्ट

13 जुलाई, 2020 को जारी 'विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति 2020 रिपोर्ट' के अनुमान के अनुसार 2019 में वैश्विक स्तर पर लगभग 690 मिलियन लोग अल्पपोषित या भूखे थे, जो कि 2018 की तुलना में 10 मिलियन अधिक थे।

महत्वपूर्ण तथ्य: सम्पूर्ण विश्व में कोविड-19 महामारी 2020 के अंत तक 130 मिलियन से अधिक लोगों को गंभीर भुखमरी के कगार पर पहुंचा सकती है।

- दुनिया 2030 तक 'जीरो हंगर' लक्ष्य प्राप्ति की राह पर नहीं है। यदि हालिया रुझान जारी रहे, तो 2030 तक भूख से प्रभावित लोगों की संख्या 840 मिलियन को पार कर जाएगी।
- प्रतिशत के संदर्भ में, अफ्रीका सबसे बुरी तरह अल्पपोषण से प्रभावित क्षेत्र है, जहां 2014 में 17.6% की तुलना में 2019 में 19.1% लोग अल्पपोषित हैं।

भारत की स्थिति: भारत में अल्पपोषित लोगों की संख्या 2004-06 में 249.4 मिलियन से घटकर 2017-19 में 189.2 मिलियन हो गई है।

- प्रतिशत के संदर्भ में, भारत में कुल जनसंख्या में अल्पपोषण का प्रसार 2004-06 में 21.7% से घटकर 2017-19 में 14% हो गया है। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 'नाटेपन' (Stunting) का प्रसार 2012 में 62 मिलियन (47.8%) से घटकर 2019 में 40.3 मिलियन (34.7%) हो गया है।

जीके फैक्ट

- यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO), कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष (IFAD), यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है।

भारत – यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर बैठक

15 जुलाई, 2020 को भारत – यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर बैठक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने इस बैठक की सह-अध्यक्षता की।

- 2013 से निलंबित मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता को पुन: शुरू करने और 'द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते' (BTIA) को आगे बढ़ाने की एक नई पहल में, दोनों पक्षों ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त फिल होगन के बीच एक 'उच्च स्तरीय संवाद' की घोषणा की।
- दोनों पक्षों ने एक संयुक्त राजनीतिक वक्तव्य जारी किया, जिसमें 'भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी' के लिए पांच साल का रोडमैप, EURATOM और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच एक असैन्य परमाणु अनुसंधान और विकास सहयोग समझौता, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने के लिए 'संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था' पर एक घोषणा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते का पांच साल के लिए नवीनीकरण शामिल है।
- यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि भारत यूरोपीय संघ का नौवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

जीके फैक्ट

- भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहली शिखर वार्ता वर्ष 2000 में हुई थी।

मालदीव और श्रीलंका में खसरा तथा रूबेला उन्मूलन

मालदीव और श्रीलंका 8 जुलाई, 2020 को अपने 2023 के लक्ष्य से पहले ही खसरा और रूबेला उन्मूलन करने वाले डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में पहले दो देश बन गए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: एक देश को खसरा और रूबेला उन्मूलन के रूप में तब सत्यापित किया जाता है, जब एक अच्छी निगरानी प्रणाली की उपस्थिति में तीन साल से अधिक समय तक खसरा और रूबेला वायरस के स्थानिक संचरण का कोई मामला न आया हो।

- मालदीव ने 2009 में खसरा और अक्टूबर 2015 में रूबेला का अंतिम स्थानिक मामला दर्ज किया था, जबकि श्रीलंका ने मई 2016 में खसरा और मार्च 2017 में रूबेला के अंतिम स्थानिक मामले की सूचना दी थी।
- भूटान, डीपीआर कोरिया और तिमोर-लेस्ते इस क्षेत्र के अन्य देश हैं, जिन्होंने खसरे का उन्मूलन किया है।

खसरा और रूबेलाः खसरा और रूबेला एक संक्रामक वायरल बीमारी है, जो अक्सर बच्चों में होती है। यह खाँसने और छींकने से एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं। इन दोनों बीमारियों को खसरा, कण्ठमाला और रूबेला (Measles, Mumps and Rubella-MMR) टीके की दो खुराक से पूरी तरह से रोका जा सकता है।

जीके फैक्ट

✧ डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में 11 सदस्य देश हैं - बांग्लादेश, भूटान, डीपीआर कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड तथा तिमोर-लेस्ते।

आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना

6 जुलाई, 2020 को पाकिस्तान और चीन ने 700.7 मेगावाट की 'आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना' के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह परियोजना पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) के सुधनोती जिले में 'झेलम नदी' पर स्थापित की जा रही है। इस परियोजना की लागत राशि 1.5 अरब डॉलर है।

- इस परियोजना के 2024 तक चालू होने की संभावना है। इस परियोजना में 3.8 वर्ग किमी जलाशय के साथ 90 मीटर ऊंचा बांध शामिल होगा। चीन की 'बेल्ट एंड रोड' पहल के हिस्से के रूप में 'चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे' (सीपीईसी) के तहत पीओके में निर्माण की जाने वाली यह दूसरी परियोजना है।
- इससे पहले 1124 मेगावाट की 'कोहाला परियोजना' हेतु दोनों देशों के बीच 23 जून, 2020 को समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ था। 2.4 अरब डॉलर की कोहला परियोजना मुजफ्फराबाद के निकट झेलम नदी पर विकसित की जाएगी।

जीके फैक्ट

✧ आजाद पट्टन परियोजना पाकिस्तान की झेलम नदी की पांच जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। आजाद पट्टन से ऊपर की ओर महाल (डीस), कोहाला और चकोथी हट्टियन (Chakothi Hattian) परियोजनाएँ हैं, जबकि करोट नीचे की ओर अवस्थित है।

भारत यूनाइटेड किंगडम में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक

यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा 10 जुलाई, 2020 को जारी नए आंकड़ों के अनुसार 2019 में यूनाइटेड किंगडम में भारत दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः भारत ने यूनाइटेड किंगडम में 120 परियोजनाओं में निवेश किया है और 5,429 नए रोजगार सृजित कर वर्ष 2019 में यूनाइटेड किंगडम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना।

- भारत ने 2018-2019 में यूनाइटेड किंगडम के लिए कुल 4% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वृद्धि कर तीसरे से दूसरे पायदान पर छलांग लगाई है, जिसमें 2019-20 वित्तीय वर्ष में 1,852 नई आवक निवेश परियोजनाएं (inward investment projects) शामिल हैं।
- अमेरिका 462 परियोजनाओं में निवेश और 20,131 रोजगार सृजित कर यूनाइटेड किंगडम के लिए एफडीआई का नंबर एक स्रोत बना हुआ है। उसके बाद क्रमशः भारत, जर्मनी, फ्रांस और चीन और हांगकांग है।

जीके फैक्ट

✧ वर्ष 2018 में यूनाइटेड किंगडम में निवेश करने वाली भारतीय परियोजनाओं की संख्या 106 थी, जिसके परिणामस्वरूप 4,858 नए रोजगार का सृजन हुआ था।

भविष्य की महामारियों की रोकथाम पर यूएनईपी रिपोर्ट

6 जुलाई, 2020 को जारी 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (यूएनईपी) की एक रिपोर्ट के अनुसार भविष्य की महामारियों की रोकथाम हेतु जलवायु परिवर्तन पर अंकुश के साथ पर्यावरण की सुरक्षा करनी होगी।

रिपोर्ट का शीर्षकः 'अगली महामारी को रोकनाः पशुजनित (जूनोटिक) रोग और संचरण की श्रृंखला को कैसे तोड़ना है' (Preventing the Next Pandemic- Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission)।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान (आईएलआरआई) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है।

- भूमि क्षरण, वन्यजीव शिकार, सघन खेती और जलवायु परिवर्तन उन रोगों में वृद्धि का कारण बन रहे हैं, जो जानवरों से मनुष्यों में संचरित हो रहे हैं। जैसे- कि कोरोना वायरस।
- रिपोर्ट में ऐसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार सात प्रचलनों की पहचान की, जिन्हें जूनोटिक के रूप में जाना जाता है।
- ये सात प्रचलन हैं: पशु प्रोटीन की बढ़ती मांग; प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और शहरीकरण; गहन और सतत कृषि; वन्यजीवों का शिकार; यात्रा और परिवहन में वृद्धि; खाद्य आपूर्ति में परिवर्तन; तथा जलवायु परिवर्तन।

जीके फैक्ट

✧ मनुष्यों में 60% ज्ञात संक्रामक रोग और सभी उभरती संक्रामक बीमारियों में से 75% पशुजनित हैं।

विज्ञान–पर्यावरण

नासा 'मार्स 2020 पर्सिवेरेन्स रोवर मिशन'

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 30 जुलाई, 2020 को फ्लोरिडा के केप कनेरवल अंतरिक्ष स्टेशन से मंगल मिशन 'मार्स 2020 पर्सिवेरेन्स रोवर मिशन' लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः मिशन के तहत शक्तिशाली 'एटलस वी' रॉकेट के जरिये अब तक के सबसे बड़े कार के आकार वाले रोवर 'पर्सिवेरेन्स' (Perseverance) को मंगल ग्रह के लिए रवाना किया गया।

- कैमरे, माइक, ड्रिल और लेजर लाइट से लैस रोवर करीब 30 करोड़ मील की दूरी तय कर सात महीने बाद फरवरी 2021 में मंगल पर पहुंचेगा और प्राचीन जीवन के साक्ष्य तलाशेगा तथा वहां से चट्टानों और मिट्टी के नमूने धरती पर भेजेगा।
- रोवर के एस्ट्रोबायोलॉजी मिशन में मंगल पर पिछले सूक्ष्म जीवन के संकेतों की तलाश करना, इसके लैंडिंग स्थल जेजेरो क्रेटर के विविध भू-विज्ञान का पता लगाना और भविष्य के रोबोट और मानव अन्वेषण की तैयारी में मदद हेतु महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना शामिल है।
- नासा ने रोवर के साथ 'इनजिन्युटी' (Ingenuity) नामक एक छोटा हेलिकॉप्टर भी मंगल पर भेजा। रोवर इसे मंगल की सतह पर छोड़ेगा। इसका लक्ष्य अकेले उड़ान परीक्षण का है। इसमें कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं है।
- रोवर का वजन 2,260 पाउंड (1025 किग्रा.) तथा यह10 फीट लंबा है। इस मिशन की लागत 8 बिलियन डॉलर से अधिक की है।

जीके फैक्ट

- नासा द्वारा मंगल पर पूर्व में भेजे गए रोवर्स 'क्यूरियोसिटी' (Curiosity), 'ओपुर्च्युनिटी' (Opportunity) 'स्पिरिट' (Spirit) और 'सोजॉर्नर' (Sojourner) थे।

चीन का मंगल मिशन तिआनवेन–1

चीन ने कोरोना वायरस महामारी के बीच 23 जुलाई, 2020 को अपना पहला मंगल मिशन तिआनवेन-1 (Tianwen-1) सफलतापूर्वक लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः दक्षिणी चीन के द्वीप प्रांत हैनान के तट पर वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से 'लॉन्ग मार्च-5 रॉकेट' के जरिये इस मिशन को लॉन्च किया गया।

- तिआनवेन जिसका अर्थ है 'स्वर्गीय प्रश्न या स्वर्ग के प्रश्न' (Heavenly Questions or Questions to Heaven), चीन के जाने-माने कवि क्यू युआन द्वारा लिखी गई एक कविता है।
- इस मिशन के तीन वैज्ञानिक उद्देश्य हैं- व्यापक अवलोकन के लिए लाल ग्रह की परिक्रमा करना, मंगल गृह की धरती पर उतरना (लैंडिंग) और लैंडिंग स्थल पर घूमने के लिए रोवर भेजना।
- यह मंगल ग्रह की मिट्टी, भूगर्भीय संरचना, पर्यावरण, वातावरण और पानी की वैज्ञानिक जांच करेगा।
- पांच-टन वजनी यह अंतरिक्ष यान करीब 7 महीने की 55 मिलियन किलोमीटर की यात्रा के बाद फरवरी 2021 में मंगल ग्रह के गुरुवत्वाकर्षण वाले इलाके में प्रवेश करेगा।
- इससे पहले 2011 में, चीन ने एक रूसी अंतरिक्ष यान में यिंगहुओ-1 (Yinghuo-1) नामक अपना मिशन भेजने का प्रयास किया था। हालांकि यह अंतरिक्ष यान बाद में खो गया था।
- अब तक भारत, रूस, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश मंगल पर मिशन भेजने में सफल रहे हैं।

जीके फैक्ट

- भारत 2014 में मंगल ग्रह के ऑर्बिटर मिशन 'मंगलयान' के सफलतापूर्वक लॉन्च के साथ ऐसा पहला देश बना जिसने अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया।

दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 70 फीसदी से अधिक की गिरावट

28 जुलाई, 2020 को जारी संयुक्त राष्ट्र की नीति संबंधी रिपोर्ट 'कोविड-19 इन एन अर्बन वर्ल्ड' (COVID-19 in an Urban World) के अनुसार नई दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में 70% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तेजी से गिरावट आई है, लेकिन पर्यावरण संबंधी ये सुधार अस्थाई हो सकते हैं।

- अगर शहर वायु प्रदूषण को रोकने की नीतियां बनाए बिना लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे और कार्बन उत्सर्जन बढाएंगे तो स्थिति फिर से खराब हो सकती है।
- महामारी के मामलों में से करीब 90% शहरी इलाकों से हैं और ये इलाके महामारी का केन्द्र बने हैं। शहरो की जनसंख्या और विश्व तथा स्थानीय क्षेत्रों में संपर्क के बढने से भी कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा बढ जाता है।
- नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में चीन में शहरी क्षेत्रों में 40%, बेल्जियम और जर्मनी में 20% और अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में 19–40% की गिरावट दर्ज की गई।
- नये वैज्ञानिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि वायु प्रदूषण अधिक होने से कोविड–19 मामलों में मृत्यु दर भी बढ जाती है।
- नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 8% की बढ़ोतरी के चलते अमेरिका और नीदरलैंड में कोरोना से होने वाली मौतों में 21.4% का इजाफा हुआ है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 'ज्ञान संसाधन केंद्र नेटवर्क'

27 जुलाई, 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्थापना दिवस के अवसर पर भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का 'ज्ञान संसाधन केंद्र नेटवर्क' (Knowledge Resource Centre Network- KRCNet) लॉन्च किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः सूचना प्रौद्योगिकी के शानदार विकास को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पारंपरिक पुस्तकालयों को एक शीर्ष ज्ञान संसाधन केंद्रों में अपग्रेड किया जाएगा।

- इन ज्ञान संसाधन केन्द्रों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा और KRCNet पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बौद्धिक जगत को एक मंच प्रदान करेगा।
- KRCNet मंत्रालय के ज्ञान संसाधनों, इसके रखरखाव, आसान पुनर्प्राप्ति और प्रसार के दस्तावेजीकरण के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली स्थापित करेगा।
- यह मंत्रालय के मुख्यालय और उसके संस्थानों में उपलब्ध बौद्धिक संसाधनों, उत्पादों और परियोजना आउटपुट को इकट्ठा कर, उनका विश्लेषण, सूचकांक और संग्रहण करेगा।
- नीति निर्माण, रिपोर्ट तैयार करने और सूचना प्रसार के लिए सूचना विश्लेषणात्मक उपकरणों और तकनीकों जैसे कि बिब्लियोमेट्रिक्स (Bibliometrics), साइंटोमेट्रिक्स (scientometrics), बिग–डेटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया एनालिटिक्स आदि का अनुप्रयोग करेगा।

जीके फैक्ट

✧ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का गठन वर्ष 2006 में भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केंद्र, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Tropical Meteorology), पृथ्वी जोखिम मूल्यांकन केंद्र एवं समुद्र विकास मंत्रालय के विलय द्वारा किया गया था।

अरुणाचल हिमालय भूकम्प–आवृत्ति अध्ययन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार के स्वायत्त संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने भारत के सबसे पूर्वी हिस्से में अरुणाचल हिमालय की चट्टानों और भूकंपीयता के लोचदार गुणों का अध्ययन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः अध्ययन के अनुसार यह क्षेत्र दो अलग–अलग गहराई पर मध्यम स्तर का भूकंप पैदा कर रहा है। यह अध्ययन फरवरी 2020 में 'जर्नल ऑफ एशियन अर्थ साइंसेज' में प्रकाशित हुआ है।

- निम्न स्तर के भूकंप 1–15 किमी. की गहराई पर केंद्रित होते हैं और 4.0 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप ज्यादातर 25–35 किमी. गहराई से उत्पन्न होते हैं। मध्यवर्ती गहराई भूकंप सम्भावना से रहित है और द्रव/आंशिक पिघले हुए क्षेत्र (zone of fluid/kpartial melts) के समान है।
- इस क्षेत्र में भूमि की ऊपरी परत की मोटाई ब्रह्मपुत्र घाटी के नीचे 46.7 किमी. से लेकर अरुणाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्र के नीचे लगभग 55 किमी. है, यह संपर्क के स्थान पर थोडा ऊंचा है, जो ऊपरी परत (Crust) और मेंटल के बीच की सीमा को परिभाषित करता है, जिसे तकनीकी रूप से 'मोहो असंबद्धता' (Moho discontinuity) कहा जाता है।
- इससे 'ट्युटिंग-टिडिंग सुचर जोन' (Tuting-Tidding Suture Zone-TTSZ) में इंडियन प्लेट के अंडरथ्रस्टइंग तंत्र (एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट का जाना) का पता चलता है।
- अंडरथ्रस्टइंग प्रक्रिया प्रवाह (ड्रेनेज) पैटर्न और भू-संरचना में निरंतर परिवर्तन करती रहती है, जो हिमालय तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी भूकंपीय खतरा पैदा करने का मुख्य कारण है।

जीके फैक्ट

✧ ट्युटिंग-टिडिंग सुचर जोन पूर्वी हिमालय का एक प्रमुख हिस्सा है, जहाँ हिमालय एक तीव्र दक्षिण की ओर मुड़ता (sharp southward bend) है और इंडो-बर्मा रेंज से जुड़ता है।

भारत–रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी आकलन और त्वरित व्यावसायीकरण कार्यक्रम

24 जुलाई, 2020 को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) और 'रूस के लघु नवीन उद्योगों की सहायता के लिए फाउंडेशन' (एफएएसआईई) की साझेदारी के साथ 'भारत–रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी आकलन और त्वरित व्यावसायीकरण कार्यक्रम' शुरू किया।

उद्देश्यः विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित भारतीय और रूसी एसएमई और स्टार्ट-अप को प्रौद्योगिकी विकास और एक-दूसरे देश की प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए संयुक्त अनुसंधान एवं विकास हेतु आपस में जोड़ना।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस कार्यक्रम के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 15 करोड़ रुपए के फंड की शुरुआत की है।

- कार्यक्रम दो वार्षिक चक्रों के माध्यम से चलाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक चक्र के तहत पांच परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से देश में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन फिक्की करेगा।
- इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्रित परियोजनाएं चलाई जाएंगी, जिनमें आईटी एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, चिकित्सा एवं फार्मास्युटिकल्स, अक्षय ऊर्जा, एयरोस्पेस, वैकल्पिक प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, जैव प्रौद्योगिकी, नवीन सामग्री, रोबोटिक्स और ड्रोन शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- दो साल की अवधि में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग दस भारतीय एसएमई/स्टार्ट-अप को 15 करोड़ रुपये तक का फंड प्रदान करेगा और 'रूस के लघु नवीन उद्योगों की सहायता के लिए फाउंडेशन' (एफएएसआईई) भी रूसी परियोजनाओं को इतना ही फंड मुहैया कराएगा।

प्लास्टिक का सफाया करने वाली बीटल लार्वा की नई प्रजाति

20 जुलाई, 2020 को जर्नल 'एप्लाइड एंड एनवायर्नमेंटल माइक्रोबायोलॉजी' में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने कोरिया में एक नई बीटल लार्वा की प्रजाति को खोज निकला है, जो प्लास्टिक का सफाया कर सकती है। इससे जुड़ा शोध पोहांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है ।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह कीट वर्मपंखी कीट समूह 'कोलिऑप्टेरा' (Coleoptera) से संबंधित है। 'प्लेसिओफ्थोथलमस डेविडिस' (Plesiophthophthalmus davidis) नामक कीट का लार्वा पॉलीस्टायरीन का सफाया करने में सक्षम है।

- 2017 तक, दुनिया भर में 8.3 बिलियन टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन किया गया था, जिसमें से 9% से कम का पुनर्नवीनीकरण किया गया था। पॉलीस्टायरीन, जो कुल प्लास्टिक उत्पादन का लगभग 6% है, को इसकी अद्वितीय आणविक संरचना के कारण विघटित करना मुश्किल होता है।
- यह कीट कोरियाई प्रायद्वीप सहित पूर्वी एशिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। यह कीट पॉलीस्टायरीन को खत्म करने के साथ-साथ इसके द्रव्यमान और आणविक भार दोनों को कम कर सकता है। ऐसा इसकी आंत में मौजूद बैक्टीरिया 'सेराटिया' (Serratia) के कारण होता है।

जीके फैक्ट

✧ 'द ग्रेट पैसिफिक गारबेज पैच' उत्तरी प्रशांत महासागर में तैरता 1.3 करोड़ टन प्लास्टिक कचरे का ढेर है, जो आकार में कोरियाई प्रायद्वीप से करीब 7 गुना बड़ा है।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का युवा सलाहकार समूह

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 28 जुलाई, 2020 को 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का युवा सलाहकार समूह' गठित किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस समूह में भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को 6 अन्य जलवायु कार्यकर्ताओं के साथ नामित किया गया है।

- 18 से 28 आयु वर्ग का यह समूह बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए दृष्टिकोण और समाधान प्रस्तुत करेगा।
- यह पहल सितंबर 2018 में शुरू की गई 'संयुक्त राष्ट्र युवा रणनीति 2030' के विजन के अनुरूप है।
- सोरेंग पक्ष-समर्थन (Advocacy) और अनुसंधान में अनुभवी हैं, और वह स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक प्रथाओं के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं।

जीके फैक्ट

✧ 24 वर्षीय सोरेंग ओडिशा के आदिवासी बहुल सुंदरगढ़ जिले की मूल निवासी हैं।

'असम कीलबैक' साँप प्रजाति

26 जून, 2020 को जर्मनी की अंतरराष्ट्रीय पत्रिका 'वर्टीब्रेट जूलॉजी' (Vertebrate Zoology) में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के वैज्ञानिकों की टीम ने एक ऐसे सांप की प्रजाति की खोज की है, जिसे 129 साल पहले विलुप्त मान लिया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्यः असम-अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पोबा आरक्षित वन के पास 2018 में किए गए सर्वेक्षण में साँप की इस मादा प्रजाति को देखा गया।

- यह प्रजाति लगभग 60 सेमी लंबी होती है तथा इसका रंग भूरा एवं पेट एक पैटर्न की तरह होता है।
- 'असम कीलबैक' नाम के इस सांप को आखिरी बार वर्ष 1891 में देखा गया था, जब एक ब्रिटिश चाय बागान मालिक सैमुअल एडवर्ड पील ने असम के सिवसागर जिले से इसके दो नर नमूनों को पकड़ा था। इन्हीं के नाम पर तब इस प्रजाति का नाम 'हेबियस पेली' (Hebius pealii) रखा गया था।
- जब एडवर्ड पील ने इस सांप को खोजा था, तो उन्होंने इसे बड़े आकार वाली कीलबैक प्रजाति (हेबियस वंश) के रूप में वर्गीकृत किया था।
- लेकिन डीएनए अध्ययन के माध्यम से, टीम ने पाया कि यह साँप भारत के सामान्य कीलबैक साँप से संबंधित नहीं है,

बल्कि पूर्वी और पश्चिमी हिमालय, दक्षिण चीन और पूर्वोत्तर भारत में पाए जाने वाले चार प्रजातियों के एक छोटे समूह से संबंधित एक अद्वितीय वंश हेरपेटोरेस (Herpetoreas) से है।

जलवायु परिवर्तन के कारण 2100 तक ध्रुवीय भालू हो जाएंगे विलुप्त

20 जुलाई, 2020 को नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन ध्रुवीय भालुओं को भूख से मरने के लिए विवश कर रहा है, जिसके कारण ये मांसाहारी जीव वर्ष 2100 तक गायब हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: समुद्री बर्फ का समय से पहले पिघलने से बर्फ लगातार कम हो रही है जिससे भालू सीलों का शिकार नहीं कर पा रहे हैं।

- अध्ययन के अनुसार13 में से 12 ध्रुवीय भालू 80 वर्षों के भीतर आर्कटिक में तेजी से हो रहे परिवर्तन के कारण कम हो गए। आर्कटिक का तापमान दोगुनी गति से बढ़ रहा है।
- 2100 तक, कनाडा के आर्कटिक द्वीपसमूह में क्वीन एलिजाबेथ द्वीप की आबादी को छोड़कर, अन्य जगहों पर ध्रुवीय भालू का जन्म लेना लगभग असंभव हो जाएगा।
- शोधकर्ताओं के अनुसार आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ध्रुवीय भालू को 'अतिसंवेदनशील' श्रेणी में जगह दिया जाना सही नहीं है, जबकि ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं।
- आईयूसीएन द्वारा स्थापित श्रेणियां मुख्य रूप से 'अवैध शिकार' और 'आवास अतिक्रमण' जैसे खतरों पर आधारित हैं, जिन्हें स्थानीय आधार पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
- ऐसे में यदि पेरिस समझौते के लक्ष्यों से लगभग आधा डिग्री ऊपर 2.4 डिग्री सेंटी ग्रेड पर वैश्विक तापमान को नियंत्रित किया जाए, तो यह ध्रुवीय भालूओं को विलुप्त होने से बचा सकता है।

यूएई का पहला मंगल मिशन

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अपने पहले मंगल मिशन की ऐतिहासिक यात्रा 20 जुलाई, 2020 को जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक शुरू की।

महत्वपूर्ण तथ्य: 1.3 टन वजन के अंतरिक्ष यान 'अल-अमल' या 'होप प्रोब' (Hope Probe) को रॉकेट H2A से जापान के तनेगाशिमा अन्तरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। 'अल-अमल' अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है 'उम्मीद'।

- मंगल मिशन की लागत 200 मिलियन डॉलर है। मंगल ग्रह पर सात महीने की यात्रा के दौरान अन्तरिक्ष यान वहां परिक्रमा करेगा और वायुमंडल के बारे में डेटा भेजेगा।
- होप प्रोब के फरवरी 2021 तक मंगल तक पहुंचने की संभावना है, यह तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय संयुक्त अरब अमीरात के गठन की 50वीं सालगिरह भी है।
- वर्तमान में मंगल ग्रह की खोज करने वाले आठ सक्रिय मिशन हैं; कुछ ग्रह की परिक्रमा करते हैं और कुछ इसकी सतह पर उतरे हैं।
- यूएई की वर्ष 2117 तक मंगल पर एक मानव-बस्ती को बसाने की महत्वाकांक्षी योजना है।

जीके फैक्ट

- हजा अल-मंसूरी सितंबर 2019 में अंतरिक्ष में जाने वाले यूएई के पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे।

गोल्डन बर्डविंग भारत की सबसे बड़ी तितली

जुलाई 2020 में 'गोल्डन बर्डविंग' (Golden Birdwing) नामक एक हिमालयी तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह मादा प्रजाति 194 मिमी. के एक पंख के साथ 'दक्षिणी बर्डविंग' (190 मिमी.) की तुलना में मामूली रूप से बड़ी होती है, जिसे ब्रिटिश सैन्य अधिकारी और तितली प्रेमी ब्रिगेडियर विलियम हैरी इवांस द्वारा 1932 में रिकॉर्ड किया गया था।

- मादा गोल्डन बर्डविंग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट से दर्ज की गई, जबकि 106 मिमी. पंखों वाला सबसे बड़ा नर 'गोल्डन बर्डविंग' तितली शिलांग के वानखर तितली संग्रहालय में मौजूद है।
- 1932 में ब्रिगेडियर इवांस द्वारा दर्ज की गई सबसे बड़ी भारतीय तितली दक्षिणी बर्डविंग को तब 'कॉमन बर्डविंग' (Common Birdwing) की उप-प्रजाति माना जाता था।
- इसकी और तितलियों की 24 अन्य प्रजातियों की नई माप को सजीवों पर शोध के लिए एक त्रैमासिक समाचार पत्र 'बायनोट्स' के नवीनतम अंक में प्रकाशित किया गया था।
- उत्तराखंड के भीमताल स्थित 'तितली अनुसंधान केंद्र' के पीटर स्मेटसेक और युनान में चीनी विज्ञान अकादमी विश्वविद्यालय की श्रीस्टी पांथी अध्ययन के लेखक हैं।

गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड

अमेरिका की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने 13 जुलाई, 2020 को भारत के लिए 'गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड' (Google for India Digitization Fund) नामक कोष स्थापित करने की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसक माध्यम से वह अगले पांच से सात वर्षों में इक्विटी निवेश, भागीदारी, संचालन और बुनियादी ढांचे के मिश्रण से देश में 10 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा।

- यह निवेश डिजिटलीकरण के लिए महत्वपूर्ण चार क्षेत्रों पर आधारित होगा- प्रत्येक भारतीय के लिए अपनी भाषा में इन्टरनेट

तक सस्ती पहुंच और जानकारी को सक्षम करना; भारत की विशिष्ट जरूरतों के लिए अधिक प्रासंगिक उत्पादों का निर्माण और सेवाएं प्रदान करना; भारत की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में व्यवसायों (बिजनेस) को सहयोग देना; और सामाजिक कल्याण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमता (AI) को विकसित करना।

जीके फैक्ट

- कंपनी ने इससे पहले भी सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से भारतीय उद्यमों में निवेश किया है। जैसे रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई के लिए 'गूगल स्टेशन', गांवों में इंटरनेट जागरूकता फैलाने के लिए 'इंटरनेट साथी' तथा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली।

स्वदेश में विकसित पहली 'न्यूमोकोक्कल पॉलीसैकैराइड कंज्युगेट वैक्सीन' को मंजूरी

भारतीय औषध महानियंत्रक (Drug Controller General of India) ने 14 जुलाई, 2020 को पूरी तरह से स्वदेश में विकसित पहली 'न्यूमोकोक्कल पॉलीसैकैराइड कंज्युगेट वैक्सीन' (Pneumococcal Polysaccharide Conjugate Vaccine) को मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह वैक्सीन शिशुओं में 'स्ट्रेप्टोकोक्कस निमोनिया' (Streptococcus pneumonia) के कारण होने वाले रोग और निमोनिया के उपचार के लिए उपयोग की जाती है। यह वैक्सीन मांसपेशियों में इंजेक्शन के जरिए दी जाती है।

- यह वैक्सीन पुणे के 'भारतीय सीरम संस्थान प्राइवेट लिमिटेड' ने विकसित की है। इस संस्थान को वैक्सीन के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दी गई थी जो अब सम्पन्न हो गए हैं। संस्थान ने इस वैक्सीन का नैदानिक परीक्षण जांबिया में भी किया है।
- निमोनिया तीव्र श्वसन संक्रमण का एक रूप है, जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह मुख्य रूप से श्वसन बूंदों (respiratory droplets) के माध्यम से प्रेषित होता है। इसके अलावा, निमोनिया विशेष रूप से जन्म के समय और उसके तुरंत बाद रक्त के माध्यम से भी फैल सकता है।

जीके फैक्ट

- 2017 में विश्व में 5 साल से कम उम्र के 80,8694 बच्चों की मौत निमोनिया के कारण हुई थी, जो बच्चों की कुल मौत का 15% है।

वन उपज पारगमन हेतु राष्ट्रीय पास सिस्टम

देश के सभी राज्यों में वन उपज का निर्बाध पारगमन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने 23 जुलाई, 2020 को वर्चुअल माध्यम से 'राष्ट्रीय पास सिस्टम' (National Transit Pass System-NTPS) की पायलट परियोजना की शुरूआत की।

महत्वपूर्ण तथ्यः इसके अलावा उन्होंने टिम्बर (लकड़ी), बांस और अन्य वन उपज के राज्य के भीतर और अंतरराज्यीय पारगमन के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल भी लॉन्च किया।

- ऑनलाइन पंजीकरण हेतु यह सिस्टम डेस्कटॉप आधारित वेब पोर्टल के साथ-साथ मोबाइल एप्लिकेशन के रूप में भी उपलब्ध है।
- ज्ञात हो कि देश में लकड़ी, बांस और अन्य वन उपजों का पारगमन अलग-अलग राज्यों के विभिन्न कानूनों और नियमों पर आधारित है। एक राज्य में छूट प्राप्त वन प्रजाति को दूसरे राज्य में छूट नहीं है। ऐसे में वन उपज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में पास की जरूरत महसूस की गई।
- यह पूरा सिस्टम राज्य के विशिष्ट नियमों और विनियमन को बदले बिना स्वचालित प्रक्रिया प्रदान करेगा, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी।
- अभी फिलहाल इस पास सिस्टम को परीक्षण के तौर पर 'मध्य प्रदेश' और 'तेलंगाना' में संचालित किया जाएगा और फिर देश भर में लागू किया जाएगा।

भारत में नैनो आधारित कृषि-इनपुट और खाद्य उत्पादों के मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देश

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 7 जुलाई, 2020 को वीडियो लिंक के माध्यम से 'भारत में नैनो आधारित कृषि-इनपुट और खाद्य उत्पादों के मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देश' जारी किए।

उद्देश्यः नीति निर्माताओं और नियामकों को भारत के कृषि-इनपुट और खाद्य क्षेत्रों में भविष्य के नए नैनो-आधारित उत्पादों के लिए प्रभावी प्रावधान तैयार करने में मदद करना।

महत्वपूर्ण तथ्यः दिशा-निर्देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्यागिकी विभाग (DBT), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं।

- वर्तमान दिशा-निर्देश नैनो-कृषि-इनपुट उत्पादों (NAIPs) और नैनो-कृषि उत्पादों (NAPs) तथा नैनो-मटेरियल (Nano Material) से बने नैनो कंपोजिट और सेंसरों पर लागू होते हैं।

नैनो मेटेरियलः नैनो मेटेरियल (NM) एक ऐसी सामग्री है, जो कम से कम एक आयाम में आकार में 1 से 100 नैनोमीटर तक या आयामों के प्रभाव के कारण किसी भी सामग्री में सुधरा हुआ गुण या घटना (improved properties or phenomena) है।

नैनो-कृषि-इनपुट उत्पाद: नैनो-कृषि-इनपुट उत्पाद (NAIP) एक नैनो-मेटेरियल युक्त कृषि इनपुट तैयारी है, जिसमें खेती के उद्देश्य के लिए फसलों पर अनुप्रयोग (मिट्टी, बीज, पत्ते और फसलों में ड्रिप के माध्यम से और साथ ही अन्य तरीकों से) का प्रयोजन है।

नैनो-कृषि उत्पाद: नैनो-कृषि उत्पाद (NAP) एक नैनो-मेटेरियल युक्त कृषि तैयारी है, जिसमें भोजन और उनकी खुराक के साथ-साथ पौष्टिक औषधीय पदार्थ डिलीवरी में उपभोग या अनुप्रयोग का प्रयोजन है।

लाभ: फसलों में नैनो-पोषक तत्वों के उपयोग से जमीन और सतह के पानी में पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सकता है।

भारत की 2018 बाघ गणना ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

जुलाई 2020 में देश के लिए अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 के चौथे चक्र, जिसके परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में घोषित किए गए थे, ने 'दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण' होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रशस्ति पत्र के अनुसार '2018-19' में किए गए सर्वेक्षण की चौथी पुनरावृत्ति 'संसाधन और डेटा' दोनों के हिसाब से अब तक का सबसे व्यापक सर्वेक्षण रहा है।

- कैमरा ट्रैप को 141 विभिन्न साइटों में 26,838 स्थानों पर रखा गया था और 1,21,337 वर्ग किमी. (46,848 वर्ग मील) के प्रभावी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। कुल मिलाकर, कैमरा ट्रैप ने वन्यजीवों की 3,48,58,623 तस्वीरों को खींचा। इन तस्वीरों के माध्यम से 2,461 बाघों (शावकों को छोड़कर) की पहचान की गई।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान से तकनीकी सहयोग से राज्य वन विभागों द्वारा कार्यान्वित किए गए अखिल भारतीय बाघ आकलन को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा हर 4 वर्ष में संचालित किया जाता है।

जीके फैक्ट

- ✧ नवीनतम गणना के अनुसार, देश में बाघों की अनुमानित संख्या 2,967 है, जो कि वैश्विक संख्या का लगभग 75% है। भारत द्वारा 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों की संख्या दोगुनी करने वाले अपने संकल्प को निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2022 से बहुत पहले ही प्राप्त किया जा चुका है।

ग्रहों की सुरक्षा पर नासा और सेती संस्थान साझेदारी

नासा ने वर्तमान और भविष्य के ग्रह सुरक्षा मिशनों (Planetary protection missions) के सभी चरणों में सहयोग करने हेतु माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में स्थित सेती (SETI) संस्थान को जुलाई 2020 में अनुबंध प्रदान किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 4.7 मिलियन डॉलर का यह अनुबंध 1 जुलाई, 2020 से शुरू हो गया है और पांच साल की अवधि के लिए है।

- सेती संस्थान तकनीकी समीक्षा और सिफारिशें प्रदान करने, उड़ान परियोजनाओं पर जैविक स्वच्छता को मान्य करने, नासा और उसके भागीदारों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नासा के ग्रह सुरक्षा कार्यालय (Office of Planetary Protection) के साथ काम करेगा। अनुबंध के तहत नासा के जिन आगामी विज्ञान अभियानों को सहयोग दिया जाएगा, उनमें 'मंगल 2020', 'यूरोपा क्लिपर मिशन' शामिल हैं। इसके अलावा, नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत भविष्य के मानव अंतरिक्ष यान की खोज जैसे- मानव लैंडर प्रणाली तथा वाणिज्यिक चंद्र पेलोड सेवा (Commercial Lunar Payload Services) पहलें भी इस अनुबंध के तहत समर्थित होंगी।
- ग्रहों की सुरक्षा (Planetary protection) पर्यावरण के साथ ही साथ विज्ञान को संरक्षित करती है, जो पृथ्वी या उसके वायुमंडल से बाहर के जीवन (extra-terrestrial life) के लिए सत्यापन योग्य वैज्ञानिक अन्वेषण सुनिश्चित करती है।

जीके फैक्ट

- ✧ सेती संस्थान कई नासा मिशनों के लिए वैज्ञानिक टीमों में शामिल है, जिनमें हबल स्पेस टेलीस्कोप, क्यूरियोसिटी, न्यू होराइजंस, ओसिरिस रेक्स (OSIRIS-REx) तथा केपलर प्रमुख हैं।

नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत

दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने 22 जुलाई, 2020 को एझिमाला में भारतीय नौसेना अकादमी में तीन मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा हासिल करने के केंद्र सरकार के 'राष्ट्रीय सौर मिशन' के अनुरूप स्थापित यह संयंत्र नौसेना का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है, जिसका अनुमानित जीवन काल 25 वर्ष है।

- इस परियोजना को केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (केईएलटीआरओएन) द्वारा निष्पादित किया गया है।
- इसके सभी घटकों को स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है, जिसमें आधुनिक तकनीक से लैस 9180 अत्यधिक कुशल मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनल (Monocrystalline solar panels) शामिल हैं। सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में नौसेना स्टेशन एझिमाला की मदद करेगी। यह भारतीय नौसेना अकादमी द्वारा स्वच्छ और हरित वातावरण की दिशा में की गई विभिन्न पहलों में से एक है।

जीके फैक्ट

- ✧ मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनलों में सिलिकॉन के एकल क्रिस्टल से बने सौर सेल होते हैं।

BFSI बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा

प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स के अंतर्गत बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा से संबन्धित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस खंड की शुरुआत की गई है।

एयरटेल पेमेंट्स बैंक और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम साझेदारी

एयरटेल पेमेंट्स बैंक और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने 22 जुलाई, 2020 को ग्रामीण भारत में युवाओं के कौशल विकास के लिए एक साझेदारी की घोषणा की, ताकि उन्हें रोजगार खोजने और वित्तीय सेवा क्षेत्र में एक उद्यमी बनने में सक्षम बनाया जा सके। साझेदारी ग्रामीण युवाओं के लिए लक्षित कौशल विकास कार्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए एनएसडीसी के अनुभव, प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के उद्योग के साथ व्यापक नेटवर्क का उपयोग करेगी।

बैंक ऑफ बड़ौदा का 'इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट'

बैंक ऑफ बड़ौदा ने जुलाई 2020 में 'इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट' (Insta Click Savings Account) लॉन्च किया है, जो 100% पेपरलेस डिजिटल स्व-सहायता (self-assisted) ऑनलाइन बचत खाता है। यह खाता ग्राहक के डिजिटल केवाईसी के नए रूप और आधार-आधारित (Aadhar based) ओटीपी (एक बार व्यक्तिगत पहचान संख्या) का उपयोग करता है, जिसे मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप और पीसी के माध्यम से बैंक की वेबसाइट से संचालित किया जा सकता है। खाते को रियलटाइम में चालू किया जाता है तथा ग्राहक लेन-देन शुरू कर सकता है। उत्पाद ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई भुगतान और डेबिट कार्ड का विकल्प भी प्रदान करता है।

रमेश बाबू बोड्डु 'करूर वैश्य बैंक' के एमडी और सीईओ नियुक्त

रमेश बाबू बोड्डु ने 29 जुलाई, 2020 को तीन साल के लिए करूर वैश्य बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले वे भारतीय स्टेट बैंक के उप-प्रबंध निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी का पद संभाल चुके हैं। जनवरी 2020 में करूर वैश्य बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ पी. आर. शेषाद्री ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था।

'महामारी जोखिम पूल' की व्यवहार्यता हेतु एक कार्यदल गठित

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीआईए) ने जुलाई 2020 में 'महामारी जोखिम पूल' (Pandemic Risk Pool) की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। आईआरडीआईए के कार्यकारी निदेशक सुरेश माथुर 9-सदस्यीय कार्य समूह के अध्यक्ष होंगे, जबकि अन्य सदस्य इंडस्ट्री के प्रतिनिधि होंगे। 'जोखिम पूल' जैसे कि व्यापार में रुकावट के नुकसान और रोजगार के नुकसान जैसे कुछ जोखिमों के परिणामस्वरूप सरकार और बीमाकर्ताओं की क्षमता से बहुत अधिक नुकसान जैसी आवश्यकता का अध्ययन करने के अलावा समूह 'संरचना' और 'संचालन मॉडल' की भी सिफारिश करेगा।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने लॉन्च किया 'यूपी. आई ऑटो पे'

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने आवर्ती भुगतानों के लिए 22 जुलाई, 2020 को 'यूपीआई ऑटो पे' (UPI AutoPay) सुविधा की शुरुआत की। यूपीआई 2.0 के तहत इस नयी सुविधा की शुरुआत की गयी है। इसके तहत 2000 रुपए तक उपभोक्ता मोबाइल बिल, बिजली बिल, ईएमआई भुगतान, एंटरटेनमेंट / ओटीटी सब्सक्रिप्शन, बीमा, म्यूचुअल फंड, कर्ज भुगतान, आवागमन अथवा मेट्रो का भुगतान जैसे आवर्ती भुगतान किसी भी यूपीआई ऐप के जरिये किया जा सकेगा। 2000 रुपए से ऊपर की राशि के भुगतान के लिये हर बार पिन की आवश्यकता होगी।

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी 'कोरोना कवच'

10 जुलाई, 2020 को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने 30 सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लघु अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी 'कोरोना कवच' शुरू करने की अनुमति प्रदान की है। इस पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी पर चिकित्सा व्यय का भुगतान शामिल होगा। इसमें सभी बीमा कंपनियां एक समान पॉलिसी देंगी। इस पॉलिसी में बीमा की राशि 50,000 रुपए से 500,000 रूपये के बीच रखी गई है। 18 से 65 वर्ष की आयु के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। कोरोना कवच पॉलिसी स्वयं के लिए, पति/पत्नी, माता-पिता, सास-ससुर और पच्चीस वर्ष तक के आश्रित बच्चों के लिए ली जा सकती है। यह पॉलिसी साढ़े तीन महीने, साढ़े छह महीने और साढ़े नौ महीने की अवधि की है। किसी चिकित्सक की सलाह पर 14 दिन की अवधि के लिए घरों में ही इलाज पर होने वाला खर्च भी इस पॉलिसी के दायरे में आएगा।

तीन बीमा कंपनियों को पूंजी उपलब्ध करने को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई, 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र की तीन सामान्य बीमा कंपनियों- ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल), नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसीएल) की मदद के लिए कुल 12,450 करोड़ रुपए (वर्ष 2019-20 में दिए गए 2,500 करोड़ रुपए सहित) की पूंजी देने को मंजूरी प्रदान की। इस पूंजी प्रवाह से सार्वजनिक क्षेत्र की इन बीमा कंपनियों को अपनी वित्तीय और ऋण चुकाने की क्षमता में सुधार, अर्थव्यवस्था की बीमा जरूरतों को पूरा करने, संसाधन जुटाने की क्षमता बढ़ाने और जोखिम प्रबंधन में सुधार करने में मदद मिलेगी।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक राजकिरण राय का कार्यकाल विस्तारित

आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के साथ चल रही विलय प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय ने 30 जून, 2020 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ राजकिरण राय को दो साल के कार्यकाल विस्तार की मंजूरी प्रदान की। वे अब 31 मई, 2022 तक सेवा देंगे। राय को 3 वर्षों की अवधि के लिए जुलाई 2017 में यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1 अप्रैल, 2020 को, यूनियन बैंक को आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के साथ विलय कर दिया गया, लेकिन एकीकरण पूरी तरह से होना बाकी है। विलय के बाद यह बैंक अब भारत का पाँचवा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।

एचडीएफसी बैंक का 'ई-किसान धन' ऐप

निजी ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने 30 जून, 2020 को कृषि क्षेत्र और ग्रामीण परिप्रणाली में किसानों के लिए सूचना और ज्ञान अंतराल को दूर करने के लिए 'ई-किसान धन' ऐप लॉन्च किया है। किसान अपने मोबाइल ऐप पर कृषि और बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं। ऐप में मंडी में मूल्य वर्धित सेवाएं (Value added services), कृषि से जुड़ी खबरें और मौसम की भविष्यवाणी सहित खेती और बीज की किस्मों के बारे में अलग-अलग जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उपयोगकर्ता ऋण की खरीद करने में सक्षम होंगे तथा सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित होंगे।

आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के लिए दिशा-निर्देश

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 7 जुलाई, 2020 को आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के लिए बीमित राशि पर मानदंडों में छूट हेतु मानक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद के लिए नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की। वर्तमान दिशा-निर्देशों के तहत, सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ता बीमित राशि के लिए 1 लाख से 5 लाख रुपये के बीच की पॉलिसी पेश कर सकते हैं। संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत इस सीमा को हटा दिया गया है। बीमा कंपनियां न्यूनतम 1 लाख रुपये से कम की राशि और अधिकतम 5 लाख रुपये से ज्यादा की बीमा राशि पेश कर सकते हैं। बीमा की राशि का विकल्प 50,000 रुपये के गुणज (Multiple) में ही दिया जाएगा।

मुथूट फिनकॉर्प ने लॉन्च किया 'रीस्टार्टइंडिया' पोर्टल

केरल स्थित एनबीएफसी, मुथूट फिनकॉर्प ने 23 जुलाई, 2020 को देश भर में व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम' (MSME) क्षेत्र की मदद करने के लिए एक निःशुल्क मेंटरिंग प्लेटफॉर्म 'रीस्टार्टइंडिया' (Restartindia) नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल को एमएसएमई क्षेत्र की आवश्यकताओं, विशेष रूप से नैनो और सूक्ष्म उद्यमों और बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए तैयार किया गया है। इस पोर्टल का उद्घाटन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया।

एसबीएम बैंक इंडिया ने लॉन्च किया 'एसबीएम एनकैश रूपे बिजनेस कार्ड'

'एसबीएम बैंक इंडिया' (SBM bank) ने 23 जुलाई, 2020 को एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स के लिए फिनटेक कंपनी 'एनकैश' (EnKash) और एपीआई अवसंरचना कंपनी 'याप' (Yap) के साथ सहयोग से रूपे (RuPay) नेटवर्क पर सह-ब्रांड बिजनेस क्रेडिट कार्ड 'एसबीएम एनकैश रूपे बिजनेस कार्ड' (SBM EnKash RuPay Business Card) लॉन्च किया। यह कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड किसी भी एसबीएम बैंक से डिजिटल और पेपरलेस माध्यम से तत्काल जारी किया जा सकेगा।

इस कार्ड को 30 दिवसीय क्रेडिट अवधि के माध्यम से व्यवसाय व्यय और वित्त को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से बिल भुगतान, यात्रा व्यय, स्वचालित जीएसटी, किराया भुगतान, सॉफ्टवेयर की ऑनलाइन खरीद आदि किया जा सकेगा। मॉरीशस तथा अन्य देशों में फैले एसबीएम समूह का यह विदेशी बैंक 'एसबीएम बैंक इंडिया' नाम से 2018 में एक नए भारतीय बैंक के रूप में काम करने वाला पहला विदेशी बैंक है।

जिन लीकुन फिर चुने गए एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के निदेशक मंडल ने 28 जुलाई, 2020 को जिन लीकुन को बैंक के अध्यक्ष (प्रेसीडेंट) के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना है। उनका दूसरा पांच साल का कार्यकाल 16 जनवरी, 2021 से शुरू होगा। लीकुन की अगुवाई में बीजिंग मुख्यालय वाले बहुराष्ट्रीय वित्त पोषण संस्थान के सदस्यों की संख्या 57 संस्थापक सदस्य देशों से बढ़कर 100 से अधिक हो गयी है। ■■

B बिजनेस और सार्वजनिक उपक्रम PSUs

प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स के अंतर्गत बिजनेस और सार्वजनिक उपक्रम से संबन्धित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस खंड की शुरुआत की गई है।

एनटीपीसी को सीआईआई–आईटीसी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019

जुलाई 2020 में नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) ने कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित 'सीआईआई-आईटीसी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019' जीता। एनटीपीसी के प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम 'बालिका सशक्तिकरण' मिशन के तहत स्कूल जाने वाली लड़कियों को उनके समग्र विकास में सहायता के लिए एनटीपीसी अपने पावर स्टेशनों के आसपास के क्षेत्र में चार सप्ताह के आवासीय कार्यक्रम संचालित करता है। 2006 में सीईएसडी (CII-ITC Centre ofExcellence for Sustainable Development) द्वारा स्थापित यह पुरस्कार उन व्यवसायों में उत्कृष्टता को पहचानते हैं और उन्हें पुरस्कृत करते हैं, जो अपनी गतिविधियों में अधिक टिकाऊ और समावेशी होने के तरीके तलाश रहे हैं।

रक्षा मंत्रालय का बीईएमएल के साथ करार

सरकार के 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय की खरीद इकाई ने 557 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से टैंक 'टी-90 एस/एसके' (T-90 S/kSK) के लिए बारूदी सुरंग हटाने वाले 1,512 उपकरणों की खरीद के लिए 20 जुलाई, 2020 को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध की खरीद और निर्माण शर्तों के तहत इन उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले 50% कलपुर्जे स्वदेशी होने चाहिए। बारूदी सुरंग हटाने वाले इन उपकरणों को सेना के बख्तरबंद कोर के टी-90 टैंकों में फिट किया जाएगा। बारूदी सुरंग हटाने वाले इन 1,512 उपकरणों को हासिल करने का काम 2027 तक पूरा करने की योजना है।

जूम खेलेगा बेंगलुरु में नया प्रौद्योगिकी केंद्र

अमेरिकी संचार प्रौद्योगिकी कंपनी 'जूम वीडियो कम्युनिकेशंस' ने 21 जुलाई, 2020 को बेंगलुरू में एक नया प्रौद्योगिकी केंद्र खोलने की घोषणा की। जूम की यह पहल देश में एक बढ़ते रणनीतिक निवेश का हिस्सा है, जूम का पहले से ही मुंबई में एक कार्यालय है तथा मुंबई और हैदराबाद में दो डेटा सेंटर हैं। भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार करते हुए वह अगले कुछ वर्षों में प्रमुख प्रतिभाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। एरिक युआन ने 2011 में जूम की स्थापना की। इसका मुख्यालय सैन जोस, कैलिफोर्निया में स्थित है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा हेतु भारती एयरटेल और वेरिजोन की साझेदारी

भारती एयरटेल ने 14 जुलाई, 2020 को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इंटरनेट बाजार भारत में कारोबार के उद्देश्य से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिका स्थित दूरसंचार कंपनी वेरिजोन के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के हिस्से के रूप में, एयरटेल भारत में उद्यम ग्राहकों को ब्रांड नाम 'एयरटेल ब्लूजीन्स' (Airtel BlueJeans) के तहत सुरक्षित उद्यम-ग्रेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान प्रदान करेगा। वेरिजोन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा ब्लूजीन्स को मोबाइल फोन, डेस्कटॉप ब्राउजर और कॉन्फ्रेंस रूम में एक्सेस किया जा सकता है। वेरिजोन कंपनी की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी।

कोल इंडिया की 'आयात स्थानापन्न के लिये विशेष हाजिर ई–नीलामी योजना 2020'

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने जुलाई 2020 में सिर्फ कोयला आयातकों के लिये 'हाजिर ई-नीलामी' की एक नयी श्रेणी शुरू की है। इसका उद्देश्य घरेलू आपूर्ति की मदद से विदेश से 15 करोड़ टन कोयले के आयात को कम करना है। 'आयात स्थानापन्न के लिये विशेष हाजिर ई-नीलामी योजना 2020' (Special spot e-auction scheme 2020 for import substitution) के तहत खरीदा गया कोयला देश के भीतर उपयोग के लिये होगा। नया कार्यक्रम ई-नीलामी की मौजूदा चार श्रेणियों के अतिरिक्त है। भारतीय खरीदार, जिन्होंने मौजूदा वित्त वर्ष या पिछले दो वित्त वर्षों में किसी में भी कोयला आयात किया हो, ई-नीलामी के इस नये संस्करण में भाग लेने के पात्र हैं।

फ्लिपकार्ट डिजिटल मार्केटप्लेस 'फ्लिपकार्ट होलसेल'

भारत के घरेलू ई-कॉमर्स समूह फ्लिपकार्ट ने 23 जुलाई, 2020 को एक नए डिजिटल मार्केटप्लेस 'फ्लिपकार्ट होलसेल' (Flipkart Wholesale) लॉन्च करने की घोषणा की, जो अत्याधुनिक और स्थानीय रूप से विकसित तकनीक का लाभ उठाकर भारत में किराना रिटेल इकोसिस्टम को बदलने में मदद करेगा। साथ ही कंपनी ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी भी खरीदी है। हालांकि फ्लिपकार्ट ने अधिग्रहण सौदे के मूल्य का खुलासा नहीं किया है। वॉलमार्ट इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा कारोबार कंपनियों में से एक वॉलमार्ट के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है।■

राज्य समाचार

जम्मू-कश्मीर

स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को 25 लाख रुपये का जीवन बीमा

उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में 18 जुलाई, 2020 को जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने केंद्र-शासित प्रदेश में स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को 25 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया है।

उद्देश्यः आतंकवादियों से लगातार खतरे का सामना करने वाले स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों को सुरक्षा की भावना प्रदान कर जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करना।

- यह बीमा कवर आतंकवाद से संबंधित घटना के कारण मृत्यु के मामले में केंद्र -शासित प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचित सदस्यों पर लागू होगा, जिसमें खंड विकास परिषद (बीडीसी) के अध्यक्ष, सरपंच, पंच आदि शामिल होंगे।

उत्तर प्रदेश

गैंगस्टर विकास दुबे मामले हेतु जांच आयोग गठित

21 जुलाई, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे मुठभेड़ मामले की जांच हेतु सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी.एस.चौहान की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया है।

- आयोग में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी के. एल. गुप्ता को शामिल किया गया है। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल भी इसमें बने रहेंगे।
- आयोग 2 जुलाई और 3 जुलाई की रात को विकास दुबे और उनके सहयोगियों द्वारा कानपुर के चौबेपुर क्षेत्र के अंतर्गत 'बिकरू गाँव' में की गई घटना तथा 10 जुलाई की उस घटना की भी गहराई से जांच करेगा, जिसमें विकास दुबे पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था।
- आयोग का मुख्यालय कानपुर में होगा। आयोग दो महीने की अवधि के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा।
- ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकास दुबे मामले की जांच के लिए 12 जुलाई, 2020 को गठित सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल (एकल सदस्यीय) आयोग के स्वरूप में बदलाव करने को कहा था।

नवीन रोजगार छतरी योजना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 जुलाई, 2020 को अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए 'नवीन रोजगार छतरी योजना' का शुभारंभ किया।

- इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के 3,484 लाभार्थियों के खातों में 17 करोड़ 42 लाख रुपये ऑनलाइन हस्तांतरित किए गए। मुख्यमंत्री ने रायबरेली, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, आजमगढ़ और मुरादाबाद के लाभार्थियों से संवाद भी किया।
- लाभार्थी इस राशि का उपयोग परचून की दुकान, जनरेटर सेट, लॉन्ड्री व ड्राई क्लीनिंग, साइबर कैफे, टेलरिंग, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, टेंट हाउस, गौ-पालन आदि के लिए करेंगे।

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020

- राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 8 जुलाई, 2020 को 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2020' को मंजूरी प्रदान की गई।
- इस नई स्टार्टअप नीति के अंतर्गत प्रदेश को देश के शीर्ष तीन स्टार्टअप अनुकूल राज्यों में शामिल करने, प्रदेश में 100 इन्क्यूबेटर्स (Incubators) तथा राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक इन्क्यूबेटर्स की स्थापना, राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप की स्थापना के अनुकूल माहौल तैयार करने तथा स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है।
- यह नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों के लिए लागू होगी। इस नीति के तहत भारत के सबसे बड़े इन्क्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में की जाएगी।
- अब तक, स्टार्टअप्स को यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप नीति 2017 के तहत शासित किया गया था, जो मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र के लिए केंद्रित था।
- इस नीति से प्रदेश में लगभग 50,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एव 1 लाख व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है।

जीके फैक्ट

- स्टार्टअप इन्क्यूबेटर्स वे संस्थान है, जो उद्यमियों को शुरुआती चरणों में अपने व्यवसाय को विकसित करने में मदद करते है।

उत्तराखंड

'भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र' के जोनल मास्टर प्लान को मंजूरी

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 16 जुलाई, 2020 को 'भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र' के जोनल मास्टर प्लान को मंजूरी प्रदान कर दी गई।

- जोनल मास्टर प्लान (जेडएमपी) उत्तराखंड सरकार द्वारा तैयार किया गया और केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय द्वारा इसका मूल्यांकन किया गया।
- मास्टर प्लान वाटरशेड दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें वन एवं वन्यजीव, जल प्रबंधन, सिंचाई, ऊर्जा, पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सड़क अवसंरचना आदि के क्षेत्र में गवर्नेंस भी शामिल हैं।
- केंद्र सरकार ने वर्ष 2012 में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गोमुख से उत्तरकाशी तक के करीब 4179.59 वर्ग किमी. क्षेत्र को कवर करने वाले क्षेत्र को 'भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित' किया था तथा क्षेत्र के विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार से जोनल मास्टर प्लान तैयार करने को कहा था।

छत्तीसगढ़

गोधन न्याय योजना

राज्य में, देश में अपनी तरह की पहली योजना 'गोधन न्याय योजना' 20 जुलाई, 2020 से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतीकात्मक रूप से हरेली पर्व के अवसर पर गोबर की खरीद कर इस योजना का राजधानी रायपुर में उद्घाटन किया।

- गोधन न्याय योजना के तहत, छत्तीसगढ़ सरकार पशुधन मालिकों से 2 रुपये प्रति किग्रा. की दर से गोबर की खरीद करेगी तथा इसका उपयोग जैविक खाद तैयार करने के लिए करेगी।
- महिला स्व-सहायता समूह इस योजना के तहत खरीदे गए गोबर का उपयोग करके वर्मी-कम्पोस्ट तैयार करेंगे, जिसे 8 रुपये प्रति किग्रा. की दर से बेचा जाएगा। राज्य सरकार चरणों में सभी 20 हजार गांवों में गौशालाओं का निर्माण भी करेगी।

हरियाणा

20,000 करोड़ रुपये की नई आर्थिक गलियारा परियोजनाओं का शुभारम्भ

केन्द्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने 14 जुलाई, 2020 को हरियाणा में 'नए आर्थिक गलियारे' के तहत लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की लागत की 11 राजमार्ग परियोजनाओं का वेबकास्ट के माध्यम से शुभारम्भ और शिलान्यास किया।

- शुरू की गई 3 परियोजनाओं में 1183 करोड़ रुपये की लागत से एनएच 334बी के रोहना/हसनगढ़ से झज्जर खंड तक 35.45 किमी. लंबे 4-लेन मार्ग, 857 करोड़ रुपये की लागत से एनएच 71 के पंजाब-हरियाणा सीमा से जींद खंड तक 70 किलोमीटर लंबे मार्ग को 4-लेन किया जाना और 200 करोड़ रुपये की लागत से एनएच 709 पर 85.36 किमी. के 2-लेन जींद-करनाल मार्ग का निर्माण शामिल है।
- इसके अलावा 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया।
- हरियाणा में चार बड़े गलियारे विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें दो ब्राउनफील्ड परियोजनाएं जींद-गोहाना-सोनीपत और यूपी/हरियाणा सीमा-रोहना-झज्जर शामिल हैं। अन्य दो ग्रीनफील्ड परियोजनाएं- 304 किलोमीटर की अंबाला-कोटपुतली और 132 किलोमीटर की गुरुग्राम-रेवाड़ी-नारनौल-राजस्थान सीमा परियोजनाएं शामिल हैं।

मध्य प्रदेश

रोको-टोको अभियान

12 जुलाई, 2020 को कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के खिलाफ अपनी लड़ाई में, राज्य सरकार ने आगामी दिनों में 'रोको-टोको' नाम से एक अभियान शुरू करने की घोषणा की। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा, जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं।

- इसके तहत जिले के कलेक्टर द्वारा चयनित स्वैच्छिक संगठन उन लोगों को मास्क प्रदान करेंगे, जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं और उनसे प्रति मास्क 20 रुपये की राशि वसूलेंगे।
- चयनित संगठनों को 'जीवन शक्ति योजना' के तहत बनाए गए 100 मास्क क्रेडिट पर प्रदान किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना

28 जुलाई, 2020 को राज्य मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता (Street Vendor) ऋण योजना को मंजूरी प्रदान की।

- योजना के तहत 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के पात्र व्यक्तियों को व्यवसाय के लिए 10 हजार रूपये तक की कार्यशील पूंजी बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
- जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक लागू होने वाली इस योजना में एक लाख ग्रामीण गरीबों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। योजना से लगभग 14 करोड़ रूपये का वार्षिक वित्तीय भार आएगा।

'चंबल एक्सप्रेस-वे' का नाम अब 'चंबल प्रोग्रेस-वे'

28 जुलाई, 2020 को राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक में 'चंबल एक्सप्रेस-वे' का नाम बदलकर 'चंबल प्रोग्रेस-वे' करने का निर्णय लिया गया।

- साथ ही भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत चंबल प्रोग्रेस-वे के निर्माण की भी स्वीकृति दी गयी। योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश-राजस्थान सीमा से मुरैना होते हुए भिण्ड जिले तक 309 किलोमीटर की 4-लेन ग्रीन फील्ड सड़क के निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया गया।
- परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाएगी। अर्जित की जाने वाली निजी भूमि को यथासंभव शासकीय भूमि से अदला-बदली की जाएगी।

आंध्र प्रदेश

नए जिलों के गठन के तौर-तरीकों के अध्ययन हेतु उच्च-स्तरीय समिति

राज्य सरकार ने 15 जुलाई, 2020 को राज्य में नए जिलों के गठन के तौर-तरीकों का अध्ययन करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया।

- समिति नए जिलों के गठन और कम व्यय से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी।
- ज्ञात हो कि सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस ने पिछले साल चुनावों की पूर्व संध्या पर, मौजूदा 13 जिलों को विभाजित करके प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र को एक जिला बनाने का वादा किया था। योजना के अनुसार, पुनर्गठन होने के बाद राज्य में 25 जिले होंगे।
- समिति अध्ययन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद 31 मार्च, 2021 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

कर्नाटक

'कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन' के गठन को मंजूरी

राज्य मंत्रिमंडल ने 23 जुलाई, 2020 को 'कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन' के गठन को मंजूरी दी।

उद्देश्यः राज्य में 7,000 से अधिक स्टार्ट-अप, ई-कॉमर्स और अन्य अनुबंधित श्रमिक वाली कंपनियों को बढ़ावा देना।

- मिशन या नई कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत शुरू किया जाएगा, जिसमें कर्नाटक सरकार की 49% और उद्योगों एवं अन्य हितधारकों द्वारा 51% की हिस्सेदारी होगी।
- इससे पहले, स्टार्ट-अप, ई-कॉमर्स और अन्य अनुबंधित श्रमिक कंपनियां 'प्रौद्योगिकी मिशन' के तहत राज्य में काम कर रही थीं और तीन से चार सरकारी एजेंसियों या विभागों द्वारा शासित थीं। अब वे एक ही कंपनी अंतर्गत आएंगे।

जीके फैक्ट

- राज्य को एक आदर्श निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए, 2016 में कर्नाटक सरकार द्वारा एक कंपनी का गठन किया गया, जिसे 'इन्वेस्ट कर्नाटक' नाम दिया गया था।

मणिपुर

मणिपुर में जल आपूर्ति परियोजना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 23 जुलाई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 'मणिपुर में जल आपूर्ति परियोजना' की आधारशिला रखी।

- मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना को केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत 3054.58 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ चलाया जाएगा। इस मिशन के तहत, केंद्र सरकार ने 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में 'हर घर जल' के उद्देश्य के साथ सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- 40 जल आपूर्ति योजनाओं से युक्त इस परियोजना का निर्माण 25 शहरों में किया जाएगा और 22 जलाशय, 20 ओवरहेड टैंक, 6 नदी अंतर्ग्रहण (River intakes) का निर्माण 'इंफाल योजना क्षेत्र' (Imphal Planning Area) में भी किया जाएगा।
- इसके अलावा, 1231 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण 1731 बस्तियों में किया जाएगा। परियोजना के पूरा होने का लक्ष्य 2024 तक है।

तमिलनाडु

कोविड-19 पर बीसीजी के प्रभाव के अध्ययन हेतु मंजूरी

राज्य सरकार ने 15 जुलाई, 2020 को कोविड-19 की तीव्रता को कम करने में बीसीजी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों में बीसीजी के टीके के परीक्षण को मंजूरी दी है।

- इस अध्ययन का समन्वय चेन्नई स्थित 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस' द्वारा किया जाएगा।
- बीसीजी वैक्सीन मूल रूप से शिशुओं के लिए है। इसका उद्देश्य तपेदिक पैदा करने वाले बैक्टीरिया को दूर करना है।
- हालांकि, कुछ प्रारंभिक अध्ययनों के अंतिम परिणामों से पता चलता है कि अपने बच्चों को बीसीजी टीकाकरण करने वाले देशों को कोविड-19 महामारी से निपटने में दूसरे देशों की तुलना में अधिक लाभ हुआ है।

दिल्ली

मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना

दिल्ली सरकार द्वारा 21 जुलाई, 2020 को घर-घर तक राशन पहुँचाने के लिए 'मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना' को मंजूरी प्रदान की गई। योजना को 6-7 महीनों के भीतर लागू किया जाएगा।

- वे लोग जो सरकारी राशन की दुकान (PDS) से राशन लेते हैं, इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
- लाभार्थियों को दुकानों से राशन लेने या इसे उनके घरों तक पहुंचाने का विकल्प दिया जाएगा। योजना के तहत गेहूं की जगह आटा उपलब्ध कराया जाएगा। दुकान से राशन लेने पर गेहूं मिलेगा, जबकि होम डिलीवरी में आटा। इसके तहत आटे, चीनी और चावल के पैकेट बनाकर उन्हें लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। ■

खेल

चर्चित खेल व्यक्तित्व

रमेश टीकाराम

भारत के दिग्गज पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी और पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का 16 जुलाई, 2020 को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बेंगलुरु में निधन हो गया। वे 51 वर्ष के थे।

- वर्ष 2000 में रमेश ने दिव्यांगों के लिए पैरा-बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। उन्होंने देश में पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।
- रमेश ने 2001 (स्पेन) में विश्व पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप में भाग लिया था। वर्ष 2002 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- 1994 में, वह फ्रांस में विश्व कप के लिए भारतीय पावरलिफ्टिंग टीम का हिस्सा भी थे।

लिन डैन

चीन के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और दो बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डैन ने 4 जुलाई, 2020 को संन्यास की घोषणा की।

- दो बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और पांच बार के विश्व चैंपियन लिन डैन को बैडमिंटन के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने 2008 में बीजिंग और 2012 में लंदन ओलंपिक में एकल स्वर्ण पदक जीता था।
- उन्होंने अपने 20 साल के करिअर के दौरान बैडमिंटन के 9 प्रमुख खिताब जीते। 2019 में लिन डैन ने अपने करियर का दूसरा मलेशिया ओपन खिताब जीता था।

एवर्टन वीक्स

वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज सर एवर्टन वीक्स का 1 जुलाई, 2020 को 95 साल की उम्र में निधन हो गया।

- उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 48 टेस्टों मैचों में, 58.61 के औसत से 4,455 रन बनाए। उन्हें कैरेबियाई क्षेत्र में खेलों का 'जनक' भी कहा जाता है।
- वीक्स वेस्ट इंडीज के तीन डब्ल्यूज (Ws) का हिस्सा थे। वे क्लाइड वॉलकॉट और फ्रैंक वॉरेल के साथ बारबेडोस में जन्मे खिलाड़ी थे।

जीके फैक्ट

- वीक्स ने सर क्लाइड वाल्कॉट और सर फ्रैंक वारेल के साथ मिलकर पचास के दशक में विश्व क्रिकेट का सबसे मजबूत बल्लेबाजी क्रम तैयार किया था। ब्रिजटाउन का राष्ट्रीय स्टेडियम इन तीनों के नाम पर 'थ्री डब्ल्यूज ओवल' (Three Ws Oval) के नाम से जाना जाता है।

जैक चार्लटन

इंग्लैंड के 1966 फुटबॉल विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे महान फुटबॉलर जैक चार्लटन का 11 जुलाई, 2020 को निधन हो गया है। वे 85 वर्ष के थे।

- चार्लटन महान डॉन रेवी प्रबंधित 'लीड्स यूनाइटेड' का एक अभिन्न हिस्सा थे, जिसने 1969 के लीग खिताब और 1972 के एफए कप जीते थे।
- चार्लटन ने रक्षापंक्ति के एक महान खिलाड़ी के रूप में 23 साल की अवधि में लीड्स यूनाइटेड के लिए 773 मैच खेलकर क्लब रिकॉर्ड बनाया।

जी. आकाश

तमिलनाडु के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी जी. आकाश जुलाई 2020 में भारत के 66वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। आकाश के ग्रैंड मास्टर खिताब की पुष्टि वर्ष 2020 के अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (एफआईडीई) की दूसरी परिषद बैठक में की गई। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने वर्ष 2012 में राष्ट्रीय खिताब जीता था।

हेमांग अमीन

13 जुलाई, 2020 को इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी हेमांग अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। उन्होंने राहुल जौहरी का स्थान लिया, जिन्होंने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था।

बैरी जर्मन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट विकेटकीपर और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व मैच रेफरी बैरी जर्मन का 17 जुलाई, 2020 को एडिलेड में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। कुल मिलाकर जर्मन ने 19 टेस्ट खेले और 400 रन बनाए।

राजीव रिसोडकर

जुलाई 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अंपायर राजीव रिसोडकर ने क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद किया है।

- मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के क्रिकेट के कानून (2017 कोड द्वितीय संस्करण 2019) का हिंदी अनुवाद अब इस प्रतिष्ठित क्लब की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। क्रिकेट नियमों का संरक्षक एमसीसी है।
- 58 वर्षीय रिसोडकर ने 1997 से 2016 तक बीसीसीआई अंपायर के रूप में कार्य किया है।

ब्रेट ली

14 जुलाई, 2020 को क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी के लिए भारतीय समाचार और सूचना वेबसाइट स्पोर्ट्सअड्डा (SportsAdda) ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज और क्रिकेट के दिग्गज ब्रेट ली को अपना ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। ब्रेट प्रतियोगिता, क्विज और बॉलिंग मास्टरक्लास सहित कई मजेदार गतिविधियों का आयोजन करेंगे, जो विशेष रूप से स्पोर्ट्सअड्डा ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर उपलब्ध होंगे।

रजत भाटिया

घरेलू क्रिकेट के अनुभवी ऑलराउंडर रजत भाटिया ने 29 जुलाई, 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की।

- उन्होंने घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड की टीम से खेला। उन्होंने 112 प्रथम श्रेणी मैचों में 6,482 रन बनाए और 137 विकेट लिए।
- इंडियन प्रीमियर लीग में, वह दिल्ली डेयरडेविल्स, राजस्थान रॉयल्स और राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए खेलने के अलावा, 2012 की आईपीएल विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा थे।

क्रिकेट

आईसीसी ने की एकदिवसीय सुपर लीग की शुरुआत

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 27 जुलाई, 2020 को एकदिवसीय सुपर लीग शुरू की, जो भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप का क्वॉलिफायर है। इसका लक्ष्य 50 ओवर के प्रारूप को अधिक प्रासंगिक बनाना है।

- सुपर लीग की शुरुआत विश्व चैंपियन इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच साउथम्पटन में 30 जुलाई से खेली गई एकदिवसीय सीरीज के साथ हुई।
- सुपर लीग में 13 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें आईसीसी के 12 पूर्ण सदस्य और नीदरलैंड शामिल है। नीदरलैंड ने विश्व क्रिकेट सुपर लीग 2015-17 जीतकर सुपर लीग में जगह बनाई है।
- सुपर लीग में प्रत्येक टीम तीन मैचों की चार श्रृंखलाएं स्वदेश और चार विदेशी सरजमीं पर खेलेंगी।
- मेजबान भारत और सुपर लीग में शीर्ष पर रहने वाली अगली सात टीमें सीधे विश्व कप के लिए क्वॉलिफाइ करेंगी।
- जो पांच टीमें सुपर लीग से सीधे क्वॉलिफाइ करने में विफल रहेंगी वे क्वॉलिफायर 2023 में पांच असोसिएट टीमों के साथ चुनौती पेश करेंगी और इनमें से दो टीमें भारत में होने वाले 10 टीमों के विश्व कप 2023 के लिए क्वॉलिफाइ करेंगी।

इंग्लैंड ने 2-1 से वेस्टइंडीज से जीती टेस्ट सीरीज

28 जुलाई, 2020 को ओल्ड ट्रैफर्ड में तीसरे और अंतिम टेस्ट में वेस्टइंडीज पर 269 रन की शानदार जीत के साथ इंग्लैंड ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। कोविड-19 महामारी के बाद यह पहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज थी।

- मैच में 10 विकेट लेने और 62 रन की पारी खेलने वाले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड 'मैन ऑफ द मैच' चुने गए। जबकि ब्रॉड को वेस्टइंडीज के रोस्टन चेस के साथ 'मैन ऑफ द सीरीज' भी चुना गया।
- इस मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट हासिल करने वाले विश्व के सातवें गेंदबाज बन गए। उनसे पहले यह कारनामा मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका), शेन वार्न (ऑस्ट्रेलिया), अनिल कुंबले (भारत), जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड), ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया) और कोर्टनी वॉल्श (वेस्टइंडीज) कर चुके हैं।
- सीरीज का पहला मैच वेस्टइंडीज ने 4 विकेट से जीता, जबकि दूसरा मैच इंग्लैंड ने 113 रन से जीता था।

इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण होगा यूएई में

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को 19 सितंबर से 10 नवंबर, 2020 तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करने का फैसला किया है।

- सभी आठ टीमों में प्रत्येक टीम में अधिकतम 24 खिलाड़ी ही शामिल होंगे।
- ज्ञात हो कि कोविड-19 महामारी के कारण लीग का 13वां संस्करण पहले स्थगित कर दिया गया था।
- यूएई दूसरी बार आईपीएल की मेजबानी करेगा। 2014 में लोक सभा चुनाव के समय टूर्नामेंट के पहले 20 मैच यूएई में खेले गए थे। 2009 में भी लोक सभा चुनाव के कारण आईपीएल दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था।

टी-20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 स्थगित

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 20 जुलाई, 2020 को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण ऑस्ट्रेलिया में इस साल अक्टूबर-नवम्बर में आयोजित होने वाला टी-20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट स्थगित कर दिया है।

- पुरुषों का टी-20 विश्व कप अब अक्टूबर-नवंबर 2021 में होगा। वहीं 2022 में होने वाला पुरुष टी-20 विश्व कप अक्टूबर-नवंबर 2022 में खेला जाएगा।

- आईसीसी ने यह भी घोषणा की है कि पुरुषों का 50 ओवरों का विश्व कप टूर्नामेंट अक्टूबर-नवंबर 2023 में भारत में आयोजित होगा।

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020

4 जुलाई, 2020 को दक्षिण अफ्रीका के सीमित ओवर क्रिकेट टीम के कप्तान क्विंटन डी कॉक को क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (CSA) के वार्षिक पुरस्कार 2020 समारोह में 'पुरुष क्रिकेटर ऑफ द इयर' और 'टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द इयर' से सम्मानित किया गया।

- जबकि युवा सलामी बल्लेबाज लौरा वोल्वार्ड्ट ने 'महिला क्रिकेटर ऑफ द इयर' और 'एकदिवसीय महिला क्रिकेटर ऑफ द इयर' का पुरस्कार अपने नाम किया।
- तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को 'पुरुष एकदिवसीय और टी 20 प्लेयर ऑफ द इयर' नामित किया गया, जबकि डेविड मिलर को 'प्रशंसकों का पसंदीदा' खिलाड़ी चुना गया।
- तेज गेंदबाज एनरिक नार्जे, जिन्होंने भारत में अपना टेस्ट डेब्यू किया, को 'वर्ष का नवागंतुक खिलाड़ी' चुना गया।

फुटबॉल

'मोहन बागान' नैस्डेक बिलबोर्ड पर आने वाला देश का पहला फुटबॉल क्लब

29 जुलाई, 2020 को 'मोहन बागान दिवस' के अवसर पर भारत का प्राचीन फुटबॉल क्लब 'मोहन बागान' न्यूयार्क के टाइम्स स्क्वैयर पर नैस्डेक बिलबोर्ड पर आने वाला देश का पहला फुटबॉल क्लब बना।

- मोहन बागान द्वारा 1911 में ईस्ट यार्कशायर रेजीमेंट को हराकर मशहूर आईएफए शील्ड खिताबी जीत का जश्न मनाने के उपलक्ष्य में 29 जुलाई को हर साल 'मोहन बागान दिवस' मनाया जाता है। इस तरह मोहन बागान 2-1 से मिली जीत से टूर्नामेंट में ब्रिटिश दबदबे को खत्म करने वाला पहला भारतीय क्लब बना था। मोहन बागान फुटबॉल क्लब को 1889 में स्थापित किया गया था।

बैलोन डी ओर पुरस्कार 2020 रद्द

फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका द्वारा हर साल दिया जाने वाला प्रतिष्ठित 'बैलोन डी ओर' (Ballon d'Or) पुरस्कार इस साल किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से नहीं खेले जा रहे फुटबॉल टूर्नामेंटों की वजह से यह फैसला लिया गया है।

- 1956 में इस पुरस्कार के शुरू होने के बाद यह पहला मौका होगा, जब किसी भी खिलाड़ी को यह खिताब नहीं दिया जाएगा।

जीके फैक्ट

✧ लियोनेल मेसी ने इसे रिकॉर्ड छः बार जीता है, वहीं उनके प्रतिद्वंद्वी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी इस खिताब पर पांच बार कब्जा किया है।

रियाल मैड्रिड ने जीता अपना '34वां ला लीगा' खिताब

स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियाल मैड्रिड ने 16 जुलाई, 2020 को अपना '34वां ला लीगा' खिताब जीत लिया है।

- स्पेनिश लीग में खेले गए एक अहम मुकाबले में रियाल मैड्रिड ने विलारियल को 2-1 से हराकर खिताबी ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।
- रियाल मैड्रिड ने मौजूदा सत्र 2019-20 में एक मैच बाकी रहते ही बार्सिलोना को सात अंकों से पछाड़कर चौंपियनशिप अपने नाम की।

जीके फैक्ट

✧ ला लीगा एक वैश्विक, अभिनव और सामाजिक रूप से जिम्मेदार एक निजी खेल संघ है, जिसमें 20 क्लब शामिल हैं। इसका मुख्यालय मैड्रिड में है। ला लीगा स्पैनिश लीग की शुरुआत 1929 में हुई थी।

विविध

चौथे 'खेलो इंडिया' युवा खेलों की मेजबानी करेगा हरियाणा

केन्द्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्री किरेन रिजिजू और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 25 जुलाई, 2020 को चौथे 'खेलो इंडिया' युवा खेलों का आयोजन हरियाणा में किए जाने कि घोषणा की।

- इन खेलों का आयोजन 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद होगा। ये खेल हरियाणा के पंचकूला में आयोजित होंगे। पिछले संस्करणों की तरह, इस बार भी 'स्टार स्पोर्ट्स' खेलो इंडिया युवा खेलों का आधिकारिक प्रसारण भागीदार होगा।

डकार युवा ओलंपिक 2026 तक स्थगित

कोरोना वायरस महामारी के कारण 2022 में सेनेगल की राजधानी डकार में होने वाले युवा ओलंपिक को 15 जुलाई, 2020 को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक फरवरी 2022 में आयोजित होंगे।

हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020

17 से19 जुलाई, 2020 तक मोग्योरोद, हंगरी में संपन्न फॉर्मूला 1 सत्र, 2020 की तीसरी रेस हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, 2020 मर्सिडीज टीम के ब्रिटिश चालक लुईस हैमिल्टन ने जीत ली।

- हैमिल्टन ने लगातार तीसरी बार और कुल आठवीं बार यह रेस जीती है। हैमिल्टन ने एक ट्रैक पर सर्वाधिक रेस जीतने के जर्मनी के माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। शूमाकर ने वर्ष 2006 में आठवीं बार फ्रांसीसी ग्रैंड प्रिक्स जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। हैमिल्टन की यह इस सत्र की दूसरी और करियर की 86वीं जीत है।
- इस रेस में रेड बुल टीम के नीदरलैंड के चालक मैक्स वर्सटाप्पेन दूसरे स्थान पर रहे। ■■

सार-संक्षेप

चर्चित व्यक्ति

राहुल बजाज

प्रतिष्ठित उद्योगपति राहुल बजाज ने तीन दशक से अधिक समय तक कंपनी के शीर्ष पद पर रहने के बाद 31 जुलाई, 2020 को बजाज फाइनेंस के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपना पद छोड़ दिया। बजाज फाइनेंस के उपाध्यक्ष संजीव बजाज ने उनका स्थान लिया।

- राहुल बजाज 1987 में कंपनी की शुरुआत से ही इसकी बागडोर संभालते आ रहे हैं। उत्तराधिकार योजना के तहत उन्होंने अपना पद छोड़ने का फैसला किया है।
- पद छोड़ने के बाद भी वे बतौर गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र निदेशक के रूप में कंपनी का मार्गदर्शन करते रहेंगे।

चंद्रिका प्रसाद 'चान' संतोखी

16 जुलाई, 2020 को भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद 'चान' संतोखी ने दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया।

- इस पद पर उन्होंने पूर्व तानशाह 'डेसी बॉउटर्स' का स्थान लिया। पूर्व पुलिस कमिश्नर और प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के संतोखी ने 25 मई को हुए चुनाव में 51 सीटों वाली नेशनल असेंबली में 20 सीटें जीतीं थी।

चर्चित स्थल

आनंद

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी) के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा आनंद, गुजरात में स्थापित 'भारत की विश्वस्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला' का 24 जुलाई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारम्भ किया।

- एनडीडीबी ने FSSAI द्वारा निर्धारित मानदंडों पर आधारित इस विश्वस्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना की है। इसमें सभी सुविधाएं हैं और परीक्षण विधियां/प्रोटोकॉल विकसित किए गए हैं।
- छोटे किसानों के कृषि-बिजनेस सहायता संघ (एसएफएसी) ने वर्ष 2000 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड का पुनर्गठन अध्यक्ष के रूप में सचिव के साथ जून 2006 में किया गया था।

लेह स्थित प्रयोगशाला 'उच्च उन्नतांश अनुसंधान रक्षा संस्थान'

डीआरडीओ ने केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना मामलों की पहचान के उद्देश्य से परीक्षण की दर को बढ़ाने के लिए लेह स्थित प्रयोगशाला 'उच्च उन्नतांश अनुसंधान रक्षा संस्थान' (Defence Institute of High Altitude Research-DIHAR) में कोविड -19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर. के.माथुर ने 22 जुलाई, 2020 को इस सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया।

- परीक्षण सुविधा प्रति दिन 50 नमूनों की जांच करने में सक्षम है तथा इसके अलावा यह सुविधा 'संक्रमित व्यक्तियों पर निगरानी', 'भविष्य के जैव-खतरों से निपटने' और कृषि उपयोग वाले पशुओं की बीमारियों के लिए आर एंड डी गतिविधियों को पूरा करने में भी मदद करेगी।

जीके फैक्ट

- DIHAR डीआरडीओ की जीवन-विज्ञान प्रयोगशालाओं में से एक है, जो 'ठंडे शुष्क कृषि-पशु प्रौद्योगिकियों' (Cold arid agro-animal technologies) तथा 'अधिक ऊंचाई और ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों' के लिए ग्रीनहाउस प्रौद्योगिकियों पर काम कर रही है।

दिल्ली

केंद्रीय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह ने 20 जुलाई, 2020 को दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया।

- एनडीएमसी के सहयोग से उर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) ने मध्य दिल्ली में भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा स्थापित किया है। इसमें पांच विभिन्न विशिष्टताओं वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं।
- भारत में ई-मोबिलिटी को सर्वव्यापी और सुविधाजनक बनाने के लिए 'ईवी चार्जिंग प्लाजा' एक नई पहल है।

मिजोरम

खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 20 जुलाई, 2020 को वर्चुअल माध्यम से मिजोरम में 'जोरम मेगा फूड पार्क' का उद्घाटन किया, जिसे 75 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है।

- मिजोरम के कोलासिब जिले के खमरंग गाँव में स्थित 55 एकड़ के फूड पार्क को जोरम मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह राज्य में संचालित पहला मेगा फूड पार्क है।

- इससे 25,000 किसानों को लाभ होगा और साथ ही 5,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

जीके फैक्ट

¤ मेगा फूड पार्क योजना के तहत, भारत सरकार 50 करोड़ रुपये प्रति मेगा फूड पार्क परियोजना की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

हागिया सोफिया संग्रहालय

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप एर्दोगन ने 10 जुलाई, 2020 को तुर्की की शीर्ष अदालत के फैसले के बाद इस्तांबुल के हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद के रूप में खोलने की घोषणा की।

- इसे 1500 वर्ष पूर्व एक परंपरावादी ईसाई गिरजाघर के रूप में निर्मित किया गया था। इसका निर्माण बेजनटाइन साम्राज्य के सम्राट जस्टीनियन प्रथम के काल में 537 ईस्वी में हुआ था।
- 1453 ईस्वी में इसे उस्मानियाई शासकों (Ottoman ruler) ने एक मस्जिद में बदल दिया था। वर्ष 1934 में तुर्की गणराज्य के संस्थापक और धर्मनिरपेक्ष शासक कमाल अतातुर्क ने हागिया सोफिया को संग्रहालय में बदल दिया था।
- 'हागिया सोफिया' को 1985 में 'इस्तांबुल के ऐतिहासिक क्षेत्र' के अंतर्गत यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया ।

दिल्ली

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने 16 जुलाई, 2020 को चमड़ा कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली में अपनी तरह के पहले फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया।

- इस केंद्र को एमएसएमई मंत्रालय की इकाई केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान, आगरा के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर स्थापित किया गया है।
- दिल्ली में गांधी दर्शन, राजघाट स्थित 'फुटवियर प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र' उच्च गुणवत्ता वाले फुटवियर बनाने के लिए चमड़ा कारीगरों को 2 महीने का एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम मुहैया करायेगा। कारीगरों को 5000 रुपये का टूल किट भी मुहैया कराया जाएगा।

निधन

रेन सोनम शेरिंग लेपचा

लोक संगीतकार और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित रेन सोनम शेरिंग लेपचा का 30 जुलाई, 2020 को कलिम्पोंग में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे।

- सोनम 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर प्रस्तुति देने वाले लेपचा समुदाय के पहले व्यक्ति थे। उन्हें लेपचा संस्कृति को बढ़ावा देने और पुनर्जीवित करने के लिए भी जाना जाता था।
- उन्हें लोक संगीत में उनके योगदान के लिए 1995 में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2007 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।

कुमकुम

दिग्गज अभिनेत्री कुमकुम का 28 जुलाई, 2020 को मुंबई में निधन हो गया। वे 86 वर्ष की थीं।

- उन्होंने 100 से अधिक हिंदी फिल्मों और लोकप्रिय गीत जैसे 'कभी आर - कभी पार' और 'मेरे महबूब कयामत होगी' में अभिनय किया था। उनका असली नाम 'जैबुन्निसा' था।
- उनकी सबसे यादगार फिल्मों में 'मिस्टर एक्स इन बॉम्बे', 'मदर इंडिया', 'कोहिनूर', 'उजाला' और 'नया दौर' शामिल हैं।

ओलिविया डी हैविलैंड

हॉलीवुड अभिनेत्री और दो बार ऑस्कर पुरस्कार विजेता रही ओलिविया डी हैविलैंड (Olivia de Havilland) का 26 जुलाई, 2020 को निधन हो गया। वे 104 वर्ष की थीं।

- हैविलैंड ने 1939 में फिल्म 'गॉन विद द विंड' (Gone With the Wind) में अपनी छाप छोड़ी थी। उन्हें 1946 की फिल्म 'टू ईच हिज ओन' (To Each His Own) और 1949 की फिल्म 'द एयरेस' (The Heiress) में शानदार अभिनय के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

जॉन सेक्सन

अमेरिकी अभिनेता और मार्शल आर्ट्स कलाकार जॉन सेक्सन का 25 जुलाई, 2020 को निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे।

- 60 वर्ष के करिअर में जॉन ने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। सेक्सन को पश्चिमी और डरावनी फिल्मों में उनके शानदार अभिनय के लिए जाना जाता है। वह इन फिल्मों में अक्सर पुलिस अधिकारी और जासूसों की भूमिका निभाते थे।
- उन्होंने ब्रुस ली के साथ 'एंटर द ड्रैगन' में अभिनय किया और 1984 में 'ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट' (A Nightmare on Elm Street) में शानदार अभिनय से लोगों का मनोरंजन किया। उन्होंने 1958 में सबसे होनहार नवागंतुक पुरुष के लिए एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था।

अमला शंकर

प्रख्यात नृत्यांगना और कोरियोग्राफर अमला शंकर का 24 जुलाई, 2020 को कोलकाता में निधन हो गया। वे 101 वर्ष की थी।

- कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 में उन्हें 'बंग विभूषण' से सम्मानित किया था।

लालजी टंडन

मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 21 जुलाई, 2020 को निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे।

- लालजी टंडन दो बार उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के सदस्य और तीन बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने राज्य सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया ।
- इसके अलावा, वह 2009 में लखनऊ निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोक सभा के लिए चुने गए और बाद में बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए।
- उनकी अनुपस्थिति में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस महीने की शुरुआत में मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभाला।

बिजॉय मोहंती

मशहूर उड़िया फिल्म अभिनेता बिजॉय मोहंती का 20 जुलाई, 2020 को भुवनेश्वर में निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे।

- वे 'नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा' के पूर्व छात्र थे तथा बॉलीवुड अभिनेता ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह के समकालीन थे। उन्होंने 350 से अधिक उड़िया, बंगाली और दक्षिण भारतीय फिल्मों में अभिनय किया था।
- उन्होंने 1977 में उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म 'चिलिका तीरे' से अपने करियर की शुरुआत की थी तथा उस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था।
- 'अरती', 'सहरी बघा', 'ममता मागे मुला', 'अए आमा संसारा', और 'सुना पंजुरी' उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं।

जॉन लेविस

अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के अग्रणी और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लंबे समय से सदस्य जॉन लेविस का 17 जुलाई, 2020 को निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे।

- लेविस नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले 'शीर्ष छः' (Big six) कार्यकर्ताओं में शामिल थे। इस आंदोलनकारी समूह का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। लेविस अटलांटा से प्रतिनिधि सभा के सदस्य थे।

सी.एस. शेषाद्रि

विख्यात गणितज्ञ सी.एस. शेषाद्रि का 17 जुलाई, 2020 को चेन्नई में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे।

- उन्होंने देश में गणित के क्षेत्र में सक्रिय अनुसंधान का माहौल तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। शेषाद्रि द्वारा 'बीजगणितीय ज्यामिति' (Algebraic geometry) में की गई बेमिसाल खोजें गणित की बुनियाद मानी जाती हैं।
- उन्होंने अपने करिअर की शुरुआत 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च' से की थी।
- 1984 में वह चेन्नई स्थित 'इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस' से जुड़ गए थे। 1989 में उन्होंने 'एसपीआईसी साइंस फाउंडेशन' (SPIC Science Foundation) के तहत 'स्कूल ऑफ मैथेमेटिक्स' की शुरुआत की। आज यह 'चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट' (Chennai Mathematical Institute) के नाम से प्रसिद्ध है।
- उन्हें 1988 में रॉयल सोसाइटी का फेलो और 2010 में 'नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, यूएसए' का विदेशी एसोसिएट चुना गया था। उन्हें 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

नीला सत्यनारायण

महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का 16 जुलाई, 2020 को मुम्बई में निधन हो गया। वे 72 वर्ष की थीं।

- उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद 2009 से 2014 तक बतौर चुनाव आयुक्त राज्य में अपनी सेवाएं दी थी।
- 1972 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रहीं सत्यनारायण ने उपन्यासों की 17 और कविता की 10 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया था। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लड़के की माँ के रूप में उनके अनुभवों पर आधारित उनके आत्मकथात्मक कार्य 'वन फुल, वन हाफ' को साहित्य जगत में व्यापक रूप से सराहा गया।

नगीनदास सांघवी

गुजराती के वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नगीनदास सांघवी का 12 जुलाई, 2020 को सूरत में निधन हो गया। वे 100 वर्ष के थे। संघवी को 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने महात्मा गांधी, गुजरात और अन्य विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं।

ज्योत्सना भट्ट

भारत की सबसे प्रसिद्ध सिरेमिक (मिट्टी के बर्तन) कलाकारों में से एक ज्योत्सना भट्ट का 11 जुलाई, 2020 को वडोदरा में निधन हो गया। वे 80 वर्ष की थी।

- उन्होंने यूएसए के ब्रोकलीन म्यूजियम आर्ट स्कूल में विश्व के प्रसिद्ध शिल्पकार प्रोफेसर जोलियन हॉफस्टेड से इस कला में महारत हासिल की थी। उन्होंने 1972 से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा में सिरामिक कला सिखाने का काम शुरू किया था।

अवध बिन हसन जामी

जाने-माने कार्टूनिस्ट अवध बिन हसन जामी, जिन्हें 'जामी' के नाम से जाना जाता है, का 11 जुलाई, 2020 को जामनगर में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे।

- उनके कार्टून नियमित रूप से दो दशक से अधिक समय तक प्रमुख गुजराती दैनिक समाचार पत्रों और समाचार पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। जामी केन्द्रीय विद्यालय, जामनगर में एक ड्राइंग शिक्षक थे।

जगदीप

वरिष्ठ अभिनेता एवं कॉमेडियन जगदीप का 8 जुलाई, 2020 का मुंबई में निधन हो गया वे 81 वर्ष के थे।

- इनका असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था और शोले में 'सूरमा भोपाली' के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे।
- जगदीप ने लगभग 400 फिल्मों में काम किया था। अपने लंबे करिअर में, जगदीप ने 'खिलौना', 'ब्रह्मचारी', 'पुराना मंदिर' और 'अंदाज अपना अपना' और 'फूल और कांटे' में यादगार भूमिकाएँ निभाईं।

नियुक्ति

राजेश भूषण

24 जुलाई, 2020 को बिहार कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश भूषण को स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे स्वास्थ्य मंत्रालय में ओ एस डी के पद पर थे।

- उन्होंने प्रीति सूदन का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त हो गया। सूदन को इस साल अप्रैल में तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया था।

रोशनी नाडर मल्होत्रा

17 जुलाई, 2020 को देश की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर मल्होत्रा ने देश की प्रमुख आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया।

- वह एक सूचीबद्ध भारतीय आईटी कंपनी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई। इस पद के साथ वह एचसीएल कॉर्पोरेशन (सभी समूह संस्थाओं के लिए होल्डिंग कंपनी) की सीईओ बनीं रहेंगी।
- इस पद पर इन्होंने अपने पिता शिव नाडर का स्थान लिया। हालांकि, शिव नाडर मुख्य रणनीति अधिकारी के रूप में कंपनी के प्रबंध निदेशक बने रहेंगे।
- वह वर्ष 2013 में एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बोर्ड में शामिल हुई थी और कंपनी की उपाध्यक्ष भी रही।
- नवीनतम हुरुन अमीर सूची के अनुसार, रोशनी 36,800 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिला है। 2019 में, वह फोर्ब्स की 'विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची' में 54वें स्थान पर रहीं।

अशोक लवासा

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 15 जुलाई, 2020 को निजी क्षेत्र के संचालन और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को अपना उपाध्यक्ष (V-P) नियुक्त करने की घोषणा की।

- वे दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त, 2020 को समाप्त होगा। हरियाणा कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। लवासा का भारत के निर्वाचन आयोग में अभी भी दो वर्ष से अधिक का कार्यकाल शेष है।
- केंद्र सरकार को ऐसी सभी नियुक्तियों पर अपनी सहमति देनी होती है, इसलिए लवासा की वर्तमान नियुक्ति सरकार द्वारा अनुशंसित है।
- चुनाव आयोग के इतिहास में ऐसा दूसरी बार होगा, जब कोई अपने कार्यकाल से पहले ही पद छोड़ेगा। इससे पहले 1973 में मुख्य चुनाव आयुक्त नागेंद्र सिंह ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए चुनाव आयोग में अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था।

पी. अमुधा

तमिलनाडु कैडर की 1994 बैच की आईएएस अधिकारी पी. अमुधा को 20 जुलाई, 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

- वे वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), मसूरी में बतौर प्रोफेसर कार्यरत हैं।

इंजेती श्रीनिवास

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 6 जुलाई, 2020 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के अध्यक्ष के रूप में इंजेती श्रीनिवास की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की।

- पूर्व कॉर्पोरेट मामलों के सचिव और ओडिशा कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी श्रीनिवास तीन साल की अवधि के लिए IFSCA के अध्यक्ष होंगे।
- IFSCA को वित्त मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2020 में देश में 'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों' में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात में है।
- प्राधिकरण का मुख्य कार्य बीमा, वित्तीय सेवाओं, और वित्तीय संस्थानों के प्रतिभूतियों, जमा या अनुबंध जैसे वित्तीय उत्पादों को विनियमित करना होगा, जिन्हें उचित नियामकों द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

इंद्रमणि पांडे

1 जुलाई, 2020 को केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। वे जिनेवा स्थित अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भी भारत के स्थायी प्रतिनिधि होंगे।

- वे 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इस पद पर वे राजीव के. चंदर का स्थान लेंगे।

पुरस्कार/सम्मान

सिंगापुर में भारतीय मूल की नर्स कला नारायणसामी को राष्ट्रपति पुरस्कार

22 जुलाई, 2020 को सिंगापुर में 59 वर्षीय भारतीय मूल की नर्स कला नारायणसामी को कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंटलाइन पर सेवा देने के लिए 'नर्सों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। उनके अलावा 4 अन्य नर्सों को भी यह सम्मान दिया गया।

- नारायणसामी, जो 'वुडलैंड्स हेल्थ कैंपस' में नर्सिंग की उप-निदेशक हैं, को मौजूदा महामारी में 'संक्रमण नियंत्रण प्रक्रियाओं' (Infection control practices) का उपयोग करने के लिए सम्मानित किया गया, जिसका उन्हें 2003 के गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम (SARS) प्रकोप के दौरान अनुभव हुआ था।
- प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को ट्रॉफी, राष्ट्रपति हलिमाह याकूब द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और 10,000 सिंगापुर डॉलर (7,228 अमेरिकी डॉलर) से सम्मानित किया गया।

जीके फैक्ट

¤ वर्ष 2000 में स्थापित नर्सों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार उन नर्सों को मान्यता देता है, जिन्होंने रोगी देखभाल, शिक्षा, अनुसंधान और प्रशासन में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान दिया हो।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार

29 जुलाई, 2020 को पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किए गए।

- **लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कारः** प्रोफेसर अशोक साहनी को जियोलॉजी, कशेरुकी जंतु विज्ञान तथा बायोस्ट्रेटीग्राफी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए।
- **समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः** विशाखापट्टनम के सीएसआईआर-राष्ट्रीय समुद्रशास्त्र संस्थान के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉ. वी. वी. एस. एस. शर्मा (हिन्द महासागर के जैव-भूरसायन की समझ में उल्लेखनीय योगदान के लिए) तथा गोवा के राष्ट्रीय ध्रुवीय केंद्र एवं समुद्र अनुसंधान के निदेशक डॉ. एम रविचंद्रन (इंडियन आर्गो प्रोजेक्ट के प्रतिपादन एवं निष्पादन के लिए)।
- **वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः** डॉ. एस. सुरेश बाबू (वातावरण की स्थिरता एवं जलवायु पर ब्लैक कार्बन एयरोसोल के विकिरण प्रभावों को समझने की दिशा में असाधारण योगदान के लिए)।
- **भू-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः** बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग के एन. वी. चलापति राव [डीपर मैंटल पेट्रोलॉजी (deeper mantle petrology) तथा भू-रसायन पर स्थायी अनुसंधान के लिए]।
- **समुद्र प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः** चेन्नई के राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉ. एम. ए. आत्मानंद (गहरे समुद्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवर्तक कार्य के लिए)।
- **महिला वैज्ञानिक का डॉ. अन्ना मणि राष्ट्रीय पुरस्कारः** गोवा के सीएसआईआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. लिदिता डी. एस. खांडेपारकर (जलीय सूक्ष्म-जीव पारिस्थितिकी, मैरीन बायोफिल्म तथा महासागरों में उनकी प्रासंगिकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए)।
- **यंग रिसर्चर अवार्डः** आईआईटी कानपुर के डॉ. इंद्र शेखर सेन तथा अहमदाबाद के भौतिकी अनुसन्धान प्रयोगशाला के डॉ. अरविंद सिंह (पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए)।

जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड

30 जुलाई, 2020 को जनजातीय कार्य मंत्रालय को मंत्रालय के छात्रवृत्ति प्रभाग की आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तीकरण के लिए एसकेओसीएच (स्कॉच) गोल्ड अवॉर्ड दिया गया।

- 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता का शीर्षक 'डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड का मुकाबला कर रहा भारत' था।
- स्कॉच पुरस्कार वर्ष 2003 में स्थापित किया गया था। स्कॉच समूह समावेशी विकास पर ध्यान देने के साथ ही सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से संबंधित भारत का अग्रणी थिंक टैंक है।

फ्रीया ठकराल को 2020 का डायना पुरस्कार

ब्रिटिश स्कूल, नई दिल्ली की एक 13 वर्षीय छात्रा, फ्रीया ठकराल को 1 जुलाई, 2020 को दिवंगत राजकुमारी डायना की जयंती पर अन्य चेंजमेकर्स के साथ डायना पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया।

- ठकराल को उनके 'रिसाइक्लर ऐप' (Recycler App) के लिए चुना गया है, जो उपयोगकर्ताओं को अपशिष्ट-संचालकों से जोड़ने के लिए एक वेब-आधारित मोबाइल एप्लिकेशन है।
- यह डोर-टू-डोर सेवा उन लोगों के लिए पुनः प्रयोज्य कचरे के आसान निपटान में मदद करती है, जिनके पास अपने कचरे के निपटान का साधन या समय नहीं है।
- डायना पुरस्कार की स्थापना 1999 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दुनिया भर में युवाओं के सामाजिक कार्यों और मानवीय प्रयासों को पहचानने के लिए राजकुमारी डायना की स्मृति में की गई थी, जिनकी 1997 में कार दुर्घटना में मौत हो गई थी।

सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी '2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स' ऑनरीज से सम्मानित

संयुक्त राज्य अमेरिका में, दो प्रसिद्ध भारतीय-अमेरिकी जिन्होंने कोविड-19 स्वास्थ्य संकट को कम करने के प्रयासों में योगदान दिया है, को इस वर्ष अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले 1 जुलाई, 2020 को एक प्रतिष्ठित अमेरिकी फाउंडेशन द्वारा सम्मानित गया है।

- पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और कैंसर रोग विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने '2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स' ऑनरीज (2020 Great Immigrants' honorees) के तौर पर सम्मानित किया है।
- सिद्धार्थ वर्ष 2009 से कोलंबिया विश्वविद्यालय संकाय में सेवारत हैं, जहां वे एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं।

अभियान / सम्मेलन / आयोजन

वायु सेना के कमांडरों का सम्मेलन

वायु सेना के कमांडरों का सम्मेलन 22 से 24 जुलाई, 2020 तक वायु सेना मुख्यालय (वायु भवन), नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

सम्मेलन का विषय: 'अगले दशक में भारतीय वायुसेना'।

- वायु सेना प्रमुख (सीएएस), एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया इस सम्मेलन की अध्यक्षता की।
- तीन दिवसीय सम्मेलन में वर्तमान सैन्य तैयारियों और तैनाती का जायजा लिया गया तथा अगले दशक में भारतीय वायुसेना की सैन्य परिचालन क्षमता बढ़ाने की कार्य योजना विजन 2030 पर भी चर्चा की गई।

एससीओ में शामिल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की डिजिटल बैठक

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 24 जुलाई, 2020 को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में शामिल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की डिजिटल बैठक में हिस्सा लिया।

- बैठक की अध्यक्षता रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने की। इस बैठक में चर्चा का प्रमुख विषय दुनिया भर में जारी कोविड संकट था।
- भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2014-2023 को पूरा करने के लिए एससीओ स्वास्थ्य मंत्रियों की मौजूदा संस्थागत बैठकों के तहत 'पारंपरिक चिकित्सा पर एक उप-समूह स्थापित करने' का प्रस्ताव रखा।

जी20 डिजिटल अर्थव्यवस्था के मंत्रियों की बैठक

जी20 की अध्यक्षता कर रहे सऊदी अरब की मेजबानी में जी20 डिजिटल अर्थव्यवस्था के मंत्रियों की 22 जुलाई, 2020 को एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई।

- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस वर्चुअल बैठक के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- बैठक में भारत ने डिजिटल प्लेटफॉर्मों को 'रक्षा, गोपनीयता और नागरिकों की सुरक्षा सहित देशों की संप्रभु चिंताओं' के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होने पर जोर दिया। साथ ही भारत ने समाज में बदलाव हेतु एक मजबूत 'कृत्रिम बुद्धिमता प्रणाली' तैयार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

'नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स ऑन कोविड-19' कार्यक्रम

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली ने 22 जुलाई, 2020 को एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में 'नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स ऑन कोविड-19' (National Clinical Grand Rounds on Covid-19) कार्यक्रम का पहला सत्र आयोजित किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य: कोविड-19 रोगियों में मृत्यु दर को एक प्रतिशत से कम करना।

- अपने अनुभव को साझा करने और कोविड-19 से संबंधित आम मुद्दों के प्रबंधन पर चर्चा शुरू करने के प्रयास में, नीति आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयोजन में एम्स दिल्ली ने यह कार्यक्रम लॉन्च किया है।
- सत्र का उद्देश्य कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर चर्चा को सुविधाजनक बनाना था। पहले सत्र में गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण वाले रोगियों को प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

प्लाज्मा दान अभियान

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 19 जुलाई, 2020 को दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत की।

- इस कार्यक्रम की सह-आयोजक दिल्ली पुलिस थी। इस अवसर पर कोविड-19 से स्वस्थ हुए दिल्ली पुलिस के 26 पुलिसकर्मियों ने अपनी स्वेच्छा से प्लाज्मा दान किया।
- कोविड-19 से ठीक हुए रोगियों से प्राप्त प्लाज्मा सार्स-सीओवी-2 वायरस के लिए सुरक्षात्मक एंटीबॉडी होती है। इसके संभावित लाभ को ध्यान में रखते हुए, उन रोगियों को प्लाज्मा थैरेपी प्रदान की जाती है जो पारंपरिक उपचार से ठीक नहीं हो पा रहे हैं।

एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर 5वां सम्मेलन

रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने 15 जुलाई, 2020 को एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर 5वें सम्मेलन का शुभारम्भ किया।

- सम्मेलन में भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2025 तक 26 अरब डॉलर के रक्षा उत्पादन को हासिल करने का आह्वान किया गया।

सार-संक्षेप

- रक्षा क्षेत्र में 2008 से 2016 के बीच 9.7% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर दर) से वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2017-18 में 42.83 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। भारत में एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग 2030 तक 70 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- भारत का नागरिक उड्डयन बाजार हर साल पर्यटकों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी के साथ दुनिया के सबसे तेजी से उभरते बाजारों में से एक है और 2026 तक हवाई अड्डा आधारभूत ढांचे के विकास में लगभग 1.83 अरब डॉलर के निवेश की योजना है।
- सम्मेलन तमिलनाडु डेवलपमेंट एंड प्रमोशन सेंटर (TNDPC), सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (SIDM) और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।

'वर्चुअल कोविड-19 डेमो दिवस' श्रृंखला

नीति आयोग के प्रमुख कार्यक्रम अटल नवाचार मिशन ने 14 जुलाई, 2020 को कोविड-19 समाधान हेतु स्टार्ट अप्स की सहायता करने के लिए 'वर्चुअल कोविड-19 डेमो दिवसों' (Virtual Covid-19 demo days) की एक श्रृंखला का समन्वय तथा समापन किया।

- 'वर्चुअल कोविड-19 डेमो दिवस' संभावित कोविड -19 नवाचारों के साथ भरोसेमंद स्टार्ट-अप्स की पहचान करने और उनके सोल्यूशन्स को देश भर में तैनात करने और विस्तारित करने में मदद करने हेतु एक पहल है।
- यह पहल भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. विजय राघवन एवं नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद पॉल के निर्देशन के तहत अन्य मंत्रालयों तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा अन्य सरकारी निकायों की साझीदारी में लॉन्च की गई।

'वज्रपात एवं आकाशीय बिजली' पर वेबिनार

14 जुलाई, 2020 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वेबिनार 'वज्रपात एवं आकाशीय बिजली' के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की।

उद्देश्य: 'वज्रपात एवं आकाशीय बिजली' के जोखिम आकलन, पूर्वानुमान, तैयारी और शमन के साथ-साथ समय पर प्रतिक्रिया और बचाव कार्य के लिए तकनीकी ज्ञान और उपलब्ध संसाधनों के बारे में जागरूक करना।

- एक दिवसीय वेबिनार का केंद्र-बिंदु वज्रपात एवं आकाशीय बिजली के जोखिमों की बेहतर समझ के संदर्भ में मानव क्षमता को विकसित करना तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेंडे और सेंडाइ फ्रेमवर्क को लागू करके प्रभावी सहयोगात्मक कार्रवाई करना था।

युद्धाभ्यास/सैन्य अभियान

भारत-अमेरिका द्वारा 'पासएक्स' अभ्यास का आयोजन

20 जुलाई, 2020 को अमेरिकी नौसेना के वाहकपोत 'यूएसएस निमित्ज' (USS Nimitz) ने अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के नजदीक भारतीय युद्धपोतों के साथ समुद्री अभ्यास 'पासएक्स' (PASSEX) में हिस्सा लिया।

- यूएसएस निमित्ज दक्षिण चीन सागर से अपनी यात्रा पर था। नौसैनिक वाहक ने हाल ही में यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित सैन्य अभ्यास में भाग लिया।
- भारतीय नौसेना ने जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और फ्रांसीसी नौसेना के साथ इसी तरह का 'पासएक्स' संचालित किया है। 'पासएक्स' एक पासेज अभ्यास (Passage Exercise) है।
- भारतीय नौसेना चीनी नौसेना के जहाजों के हिन्द महासागर क्षेत्र में गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनकी उपस्थिति समुद्री जहाजों पर हमलों के खिलाफ गश्ती के नाम पर पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है।

जीके फैक्ट

¤ 2017 में, चीन ने 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' में जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा खोला। 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया के देशों वाले क्षेत्र को संदर्भित करता है।

समझौते/संधि

भारत तथा जिम्बाब्वे समझौता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई, 2020 को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन को पूर्व-स्वीकृति प्रदान की है। समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 30 नवंबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।

उद्देश्य: समानता और आपसी लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, बढ़ावा देना और विकसित करना।

- एमओयू में सहयोग के निम्न प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है:
  1. शिक्षण, अभ्यास और औषधि तथा बिना औषधि के रोगों के इलाज को बढ़ावा देना;
  2. निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रदर्शन और संदर्भ के लिए सभी आवश्यक औषधि सामग्री और दस्तावेजों की आपूर्ति करना;
  3. तथा चिकित्सकों, चिकित्सा सहायकों, वैज्ञानिकों, शिक्षण पेशेवरों और छात्रों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करना।

ट्राइफेड और आईआईटी दिल्ली साझेदारी

जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ट्राइफेड द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम 'उन्नत भारत अभियान' (यूबीए) के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ 24 जुलाई, 2020 को साझेदारी की गई।

- ट्राइफेड, आईआईटी दिल्ली और विज्ञान भारती (विभा, एक स्वदेशी विज्ञान आंदोलन) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- ट्राइफेड के वन धन कार्यक्रम के अंतर्गत, जनजातीय उद्यमियों को अब उन्नत भारत अभियान (यूबीए) के अंतर्गत 2600 से अधिक शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के पूरे नेटवर्क की विशेषज्ञता प्राप्त हो सकेगी।
- इसके अलावा आदिवासियों को नई प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, उत्पाद नवाचार, मेंटरशिप और परिवर्तनकारी डिजिटल प्रणाली से अवगत कराया जाएगा।

जीके फैक्ट

¤ 2014 में शुरू उन्नत भारत अभियान एक समावेशी भारत के निर्माण करने में मदद करने के लिए ज्ञान संस्थानों का लाभ उठाकर ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तन की कल्पना करता है।

भारत और मालदीव

भारत और मालदीव ने मालदीव की राजधानी माले में 'आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं' की स्थापना के लिए 21 जुलाई, 2020 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- यह परियोजना कई छोटी और मध्यम परियोजनाओं में से एक है, जिसे भारत द्वारा पड़ोसी देश के लिए लगभग 20 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्तपोषित किया जा रहा है।
- 'आपातकालीन चिकित्सा सेवा इकाई' गुणवत्तापरक आपातकालीन देखभाल के लिए समय पर पहुंच को सुनिश्चित करेगी।

एनटीपीसी और एनआईआईएफ

भारत में व्यापार अवसरों का पता लगाने के लिए एनटीपीसी और राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) के बीच 16 जुलाई, 2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

उद्देश्यः देश में चिरस्थायी और मजबूत ऊर्जा अवसंरचना का निर्माण करने वाले भारत के दृष्टिकोण में सहयोग प्रदान करना।

- इस समझौते के माध्यम से एनटीपीसी की तकनीकी विशेषज्ञता और एनआईआईएफ की पूंजी जुटाने की क्षमता को एक साथ लाया जाएगा और व्यापार अवसरों का पता लगाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का प्रयास किया जायेगा।

- एनआईआईएफ लिमिटेड अपने तीन फंडों- मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स और स्ट्रैटेजिक फंड (Strategic Fund) में 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा इक्विटी पूंजी प्रतिबद्धताओं का प्रबंधन करता है।
- एनआईआईएफ मास्टर फंड देश का सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा वाला फंड है तथा परिवहन और उर्जा जैसे मुख्य बुनियादी ढ़ांचा वाले क्षेत्रों में निवेश करता है।

ईईएसएल और नोएडा प्राधिकरण

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों के एक संयुक्त उद्यम 'एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड' (ईईएसएल) ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों और उससे संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) के साथ 9 जुलाई, 2020 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- ईईएसएल कुशल जनशक्ति के माध्यम से सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना का संचालन और रख रखाव के साथ-साथ समझौते से संबंधित सेवाओं पर अग्रिम निवेश करेगा। जबकि नोएडा प्राधिकरण चार्जिंग अवसंरचना के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगा।
- इस पहल से, प्रति वर्ष प्रति ई-कार से 3.7 टन से ज्यादा कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन कम होने का अनुमान है।

सीबीडीटी और सेबी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डेटा- साझा करने के उदेश्य से 8 जुलाई, 2020 को एक औपचारिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

- डेटा के नियमित आदान-प्रदान के अलावा, सेबी और सीबीडीटी विभिन्न कानूनों के तहत अपने कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से, अनुरोध पर या अपने आप डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी का आदान-प्रदान भी करेंगे।

वेब पोर्टल/ऐप

मोबाइल ऐप 'मौसम' लॉन्च

27 जुलाई, 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संस्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लिए मोबाइल ऐप 'मौसम' लॉन्च किया गया।

- इसकी सहायता से उपयोगकर्ता मौसम के पूर्वानुमान, रडार से लिए गए चित्र और विषम मौसम संबंधी बाधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

- इस ऐप में 5 सेवाएं उपलब्ध हैं:
- **वर्तमान मौसम** (Current Weather)- 200 शहरों के लिए वर्तमान तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और दिशा का दिन में 8 बार अपडेट;
- **नाउकास्ट** (Nowcast)- स्थानीय मौसम संबंधी घटनाओं की तीन घंटे की चेतावनी और 800 स्टेशनों और जिलों के लिए जारी की गई उनकी तीव्रता।
- **शहर का पूर्वानुमान** - पिछले 24 घंटे और भारत के 450 शहरों में मौसम की स्थिति का 7 दिन का पूर्वानुमान।
- **चेतावनी**- खतरनाक मौसम के प्रति नागरिकों को चेतावनी देने के लिए कलर कोड (रेड, ऑरेंज और येलो) अलर्ट।
- **रडार उत्पादः** नवीनतम स्टेशन के हिसाब से रडार उत्पाद हर 10 मिनट में अपडेट।

मोबाइल ऐप 'बीआईएस-केयर'

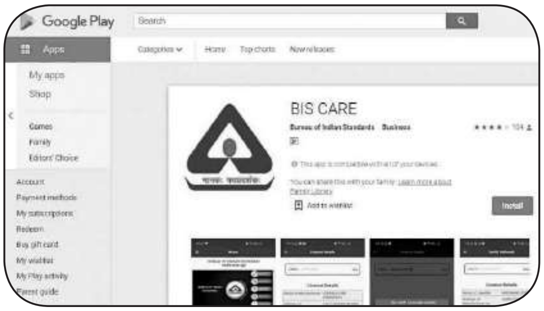

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने 27 जुलाई, 2020 को उपभोक्ताओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप 'बीआईएस-केयर' और www.manakonline.in पर तीन पोर्टलों- मानकीकरण, अनुरूपता आकलन (Conformity Assessment) तथा ई-बीआईएस का प्रशिक्षण (Training of e-BIS) को लॉन्च किया।

- मोबाइल ऐप बीआईएस-केयर को किसी भी एंड्रायड फोन पर संचालित किया जा सकता है। यह ऐप हिन्दी तथा अंग्रेजी में संचालन में है।
- उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग करके आईएसआई चिन्हित एवं हॉलमार्क्ड उत्पादों की प्रमाणिकता की जांच कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

मोबाइल ऐप 'कूर्मा'

कछुओं के संरक्षण के उद्देश्य से 'भारतीय कछुआ संरक्षण कार्रवाई नेटवर्क' (ITCAN) पहल द्वारा विकसित मोबाइल ऐप 'कूर्मा' को विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर 23 मई, 2020 को लॉन्च किया गया ।

- ऐप को टर्टल सर्वाइवल एलायंस इंडिया (Turtle Survival Alliance India) और वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी-इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया।
- यह न केवल उपयोगकर्ताओं को एक प्रजाति की पहचान करने के लिए एक डेटाबेस प्रदान करता है, बल्कि देश भर में कछुओं के लिए निकटतम बचाव केंद्र का स्थान भी प्रदान करता है।

'पीएम स्वनिधि' मोबाइल ऐप

रेहड़ी-पटरी और फेरी लगाने वाले दुकानदारों को घर पर लघु ऋण सुविधा देने के लिए 'पीएम स्वनिधि' मोबाइल ऐप 17 जुलाई, 2020 को नई दिल्ली में जारी किया गया।

उद्देश्यः छोटे दुकानदारों के लिए ऋण की आवेदन प्रक्रिया आसान बनाना और संबंधित संस्थानों तक आसान पहुंच बनाना।

- ऐप ऋण प्रदाता संस्थानों और उनके फील्ड कार्यकर्ताओं को अनुकूल डिजिटल इंटरफेस प्रदान करेगा।
- रेहड़ी-पटरी और फेरी लगाने वाले दुकानदारों को पूंजीगत ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना' (PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi-PMSVANidhi) को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 जून, 2020 को शुरू किया गया था।

'एटीएल ऐप' डेवलपमेंट मॉडयूल

नीति आयोग ने 11 जुलाई, 2020 को अटल नवाचार मिशन (एआईएम) के तहत देशभर में स्कूली बच्चों के लिए 'एटीएल ऐप' डेवलपमेंट मॉडयूल शुरू किया ।

उद्देश्यः एआईएम के प्रमुख कार्यक्रम अटल टिंकरिंग लैब्स के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करना और उन्हें ऐप उपयोगकर्ता से ऐप निर्माणकर्ता बनाना।

- भारतीय स्टार्टअप प्लेज्मो के सहयोग से एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है।
- एटीएल ऐप एक निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। छह परियोजना-आधारित शिक्षण मॉड्यूल और ऑनलाइन परामर्श सत्रों के माध्यम से युवा विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाना सीख सकते हैं और अपनी प्रतिभा उजागर कर सकते हैं।
- ऐप बनाने के लिए स्कूल शिक्षकों में क्षमता और कौशल निर्माण के लिए 'एआईएम ऐप डेवलपमेंट पाठयक्रम' पर सावधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे।
- अब तक, पूरे देश के 660 से अधिक जिलों में अटल इनोवेशन मिशन द्वारा 5100 से अधिक एटीएल स्थापित किए गए हैं।

'असीम' पोर्टल

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 10 जुलाई, 2020 को विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की मांग-आपूर्ति की खाई को पाटने के लिए कृत्रिम बुद्धिमता- आधारित 'असीम' (Aatmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping- ASEEM) पोर्टल (डिजिटल प्लेटफॉर्म) की शुरुआत की।

- यह पोर्टल विभिन्न सेक्टर और स्थानीय उद्योग की मांगों के आधार पर श्रमिकों के विवरणों का मैपिंग करेगा और कुशल श्रमिक बल की मांग और आपूर्ति के बीच सेतु का कार्य करेगा।
- भारतीय राज्यों के प्रवासी श्रमिकों और 'वंदे भारत' मिशन के तहत विदेशों से भारत लौटे नागरिकों का डेटाबेस और 'स्वदेस पहल' के तहत भरे गए 'स्वदेश स्किल कार्ड' को असीम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

उद्यम पंजीकरण पोर्टल

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विकसित 'उद्यम पंजीकरण पोर्टल' 1 जुलाई, 2020 से शुरू हो गया है। उद्यमों के 'वर्गीकरण' और 'पंजीकरण' की नई प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

- देश में अब सभी लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम इकाइयों की विशिष्ट पहचान संख्या होगी। वहीं साथ ही इन इकाइयों को 'उद्यम' के नाम से जाना जायेगा। नई या पुरानी सभी इकाइयों को इस पोर्टलपर पंजीकृत करना होगा।
- पंजीकरण पूरा होने के बाद एक ऑनलाइन 'उद्यम' रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। साथ ही पंजीकरण के नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

आपदा/दुर्घटनायें

हरिकेन 'हन्ना'

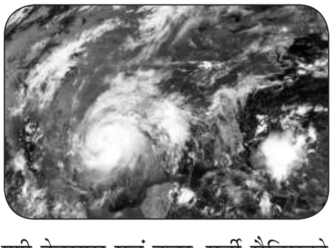

25 जुलाई, 2020 को हरिकेन 'हन्ना' (Hurricane Hanna) 90 मील प्रति घंटे तक की हवा की गति से संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास से टकराया, जिससे दक्षिणी टेक्सास एवं उत्तर-पूर्वी मैक्सिको के कुछ हिस्सों में भारी बारिशतथा बाढ़ के हालत पैदा हो गए।

- हवा की गति के आधार पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की पांच श्रेणियां हैं। हन्ना 'श्रेणी एक' (category one) का उष्णकटिबंधीय चक्रवात था।
- जब घूर्णन प्रणालियों (rotating systems) में हवाएं 39 मील प्रति घंटे की गति से चलती हैं, तो तूफान को 'उष्णकटिबंधीय तूफान' (tropical storm) कहा जाता है और जब इनकी गति 74 मील प्रति घंटे तक हो जाती है, तो इसे 'उष्णकटिबंधीय चक्रवात' या 'हरिकेन' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और इसे एक नाम भी दिया जाता है।

जीके फैक्ट

- 1953 से, अटलांटिक उष्णकटिबंधीय तूफानों का नाम राष्ट्रीय हरिकेन केंद्र (NHC) द्वारा सूचियों के अनुसार रखा जाता था। लेकिन 1978 में, यह निर्णय लिया गया था कि NHC 1975 में ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान ब्यूरो द्वारा अपनाई गई पद्धति की तर्ज पर पुरुषों और महिलाओं के नामों का उपयोग करेगा।

विविध

प्रधानमंत्री द्वारा तीन कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारम्भ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जुलाई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेहद तेज गति से काम करने वाली तीन कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारम्भ किया।

- इन तीन तेज परीक्षण सुविधाओं की स्थापना रणनीतिक रूप से नोएडा स्थित आईसीएमआर- राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान; मुंबई स्थित आईसीएमआर- राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान; और कोलकाता स्थित आईसीएमआर- राष्ट्रीय कॉलरा और आंत्र रोग संस्थान, में की गई है।
- इनमें एक दिन में 10,000 से ज्यादा नमूनों की जांच हो सकेगी। ज्यादा संख्या में जांच से बीमारी के जल्दी पता लगाने और उपचार में सहायता मिलेगी।
- ये प्रयोगशालाएं कोविड-19 के अलावा दूसरी बीमारियों का परीक्षण करने में भी सक्षम हैं और महामारी के दौर के बाद इनमें हेपेटाइटिस बी और सी, एचआईवी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साइटोमेगालोवायरस (cytomegalovirus), क्लैमाइडिया (chlamydia), नेसिरिया (Neisseria) डेंगू आदि के परीक्षण हो सकेंगे।

नवाचार प्रतियोगिता 'डेयर टू ड्रीम 2.0'

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 27 जुलाई, 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और विख्यात वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर अपनी नवाचार प्रतियोगिता 'डेयर टू ड्रीम 2.0' (Dare to Dream 2.0) शुरू की।

- प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के आह्वान के बाद देश में रक्षा और एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में नवाचार के लिए व्यक्ति-विशेष और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए योजना शुरू की जा रही है।
- 'डेयर टू ड्रीम 2.0' देश के नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक ओपन चौलेंज प्रतियोगिता है। विजेताओं को पुरस्कार राशि, स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपये और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।

माईगव प्लेटफॉर्म ने पूरे किए छः साल

माईगव (MyGov) प्लेटफॉर्म ने 26 जुलाई, 2020 को सहभागी गवर्नेंस के छः साल पूरे किए।

- माईगव प्लेटफॉर्म का शुभारंभ 26 जुलाई, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था।

- माईगव प्लेटफॉर्म सरकारी विभागों, नीति निर्माताओं और कार्यान्वयनकर्ताओं के साथ सीधे संपर्क द्वारा सभी चरणों में प्रमुख गवर्नेंस या शासन संबंधी मुद्दों पर अपने विचार साझा करने के लिए दुनिया भर के नागरिकों और सभी हितधारकों को एक अवसर प्रदान करता है।

डब्ल्यूटीओ ने दिया तुर्कमेनिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जनरल काउंसिल द्वारा 22 जुलाई, 2020 को तुर्कमेनिस्तान को पर्यवेक्षक (Observer) का दर्जा दिया गया है।

- तुर्कमेनिस्तान डब्ल्यूटीओ के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है।
- इसके पड़ोसी मध्य एशियाई देश - कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश हैं, जबकि उज्बेकिस्तान 1994 के बाद से विश्व व्यापार संगठन में सदस्यता के लिए बातचीत कर रहा है।

पोर्टेबल अस्पताल 'मेडिकैब'

जुलाई 2020 में आईआईटी, मद्रास में एक स्टार्टअप 'मॉड्यूलस हाउसिंग' (Modulus Housing) द्वारा एक पोर्टेबल अस्पताल 'मेडिकैब' (MediCab) विकसित किया गया है।

- मेडिकैब एक 15 बेड का सूक्ष्म अस्पताल है, जिसमें आईसीयू के अलावा डॉक्टरों, आइसोलेशन और चिकित्सा जांच के लिए अलग-अलग कमरे हैं।
- इसे केवल चार लोगों द्वारा 8 घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इसका उपयोग दूरस्थ स्थानों पर भी कोविड-19 रोगियों की जांच, आइसोलेट करने और उपचार के लिए किया जा सकता है।
- पोर्टेबल अस्पताल की पायलट परियोजना को हाल ही में केरल के 'वायनाड' जिले में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है।
- 'मॉड्यूलस हाउसिंग' को 2018 में 'आईआईटी मद्रास इनक्यूबेशन प्रकोष्ठ' (IIT Madras Incubation Cell) के सहयोग से दो पूर्व आईआईटी के छात्रों द्वारा स्थापित किया गया था।

सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट 'कोरोश्योर'

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने 15 जुलाई, 2020 को नई दिल्ली में आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित की गई सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट 'कोरोश्योर' (Corosure) को डिजिटल माध्यम से लॉन्च किया।

- आरटी-पीसीआर पर आधारित इस डायग्नोस्टिक किट को आईसीएमआर और डीसीजीआई द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा इसका आधार मूल्य 399 रुपये है।

भारत का पहला 'डायलिसिस ऑन व्हील्स' कार्यक्रम

जुलाई 2020 में भारत के सबसे बड़े डायलिसिस नेटवर्क 'नेफ्रोप्लस' ने भारत का पहला 'डायलिसिस ऑन व्हील्स' कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें एक मरीज एम्बुलेंस के अंदर ही डायलिसिस करवा सकता है तथा एम्बुलेंस उसके घर तक आ सकती है।

उद्देश्यः कोविड-19 के कारण डायलिसिस करा रहे रोगियों को बार-बार अस्पताल के जोखिम भरे माहौल और इम्युनिटी से समझौता करने वाली स्थिति से बचाना।

- भारत में पहली बार, मोबाइल वैन की यह प्रायोगिक पहल दिल्ली, गुरूग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा के मरीजों को उपलब्ध होगी।

'पोस्ट कोविड कोच' विकसित

जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई रेल कोच फैक्ट्री (कपूरथला) ने एक 'पोस्ट कोविड कोच' (Post-COVID Coach) विकसित किया है।

- 'कोरोना काल के बाद के इस विशेष कोच' की डिजाइनिंग को बेहतरीन करते हुए कोच में 'हैंड्सफ्री सुविधाएं' जैसे कि पैर से संचालित नल एवं साबुन निकालने की मशीन, पैर से संचालित शौचालय द्वार; 'तांबा कोटिंग युक्त रेलिंग व चिटकनी', क्योंकि तांबे के संपर्क में आने वाला वायरस कुछ ही घंटों में निष्क्रिय हो जाता है; 'प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर' के अलावा 'टाइटेनियम डाई-ऑक्साइड कोटिंग' जो कि पर्यावरण अनुकूल जल-आधारित कोटिंग है जो वायरस, बैक्टीरिया, फफूंदी एवं फंगस को नष्ट कर इन्हें पनपने नहीं देती है, शामिल हैं।

पराबैंगनी सैनिटाइजिंग उत्पाद 'शुद्ध'

जुलाई 2020 में आईआईटी कानपुर के 'इमेजिनीयरिंग प्रयोगशाला विभाग' (Imagineering Laboratory department) ने 'शुद्ध' (Smartphone operated Handy Ultraviolet Disinfection Helper- SHUDH) नामक एक पराबैंगनी (UV) सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है।

- इस उपकरण में 15 वॉट की छह यूवी लाइट वाले बल्ब हैं, जिन्हें दूर बैठकर चलाया जा सकता है।
- इस उपकरण से दस बाई दस (10 X 10) के एक कमरे को कोरोना वायरस से मुक्त करने में महज 15 मिनट का समय लगता है। इस उपकरण की स्पीड और स्थान को अपने स्मार्टफोन से ब्लूटूथ के जरिये बदला जा सकता है।
- 'शुद्ध' अस्पताल, होटल, मॉल, कार्यालय और स्कूलों जैसे अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कोरोना वायरस के प्रसार को खत्म करने में सहायता कर सकता है।

डब्ल्यूएचओ द्वारा महामारी की प्रतिक्रिया की समीक्षा हेतु पैनल गठित

कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए अमेरिका की आलोचना झेल रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 9 जुलाई, 2020 को महामारी की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया है।

- इस पैनल का नेतृत्व न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधान मंत्री हेलेन क्लार्क और पूर्व लाइबेरियाई राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सरलीफ करेंगे।
- 2014 के इबोला संकट पर डब्ल्यूएचओ की प्रतिक्रिया की भी व्यापक रूप से आलोचना हुई थी। इस महामारी में लगभग 11,000 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से ज्यादातर पश्चिमी अफ्रीकी देशों गिनी, लाइबेरिया और सिएरा लियोन से थे।

'ई-आईसीयू' कार्यक्रम

कोविड-19 से होने वाली मौतों में यथासंभव कमी सुनिश्चित करने हेतु एम्स नई दिल्ली ने 8 जुलाई, 2020 को देश भर के आईसीयू डॉक्टरों के साथ एक वीडियो-परामर्श कार्यक्रम 'ई-आईसीयू' शुरू किया है।

उद्देश्यः उन डॉक्टरों के बीच मरीजों के समुचित उपचार से संबंधित चर्चाएं सुनिश्चित करना, जो देश भर के अस्पतालों और कोविड केंद्रों में कोविड-19 रोगियों के इलाज में सबसे आगे हैं।

- कोविड-19 रोगियों का उपचार करने वाले डॉक्टरों के साथ-साथ आईसीयू में कार्यरत डॉक्टर भी इस वीडियो प्लेटफॉर्म पर एम्स, नई दिल्ली के अन्य चिकित्सकों और विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं तथा अपने-अपने अनुभवों को प्रस्तुत कर सकते हैं।

चर्चित पुस्तक

- 'ए सांग ऑफ इंडिया' (A Song of India) **-रस्किन बॉन्ड**
- 'सेव यूथ सेव नेशन' (Save Youth Save Nation) **-सीमा हिंगोनिया**
- 'ओवरड्राफ्टः सेविंग द इंडियन सेवर' (Overdraft: Saving the Indian Saver) **-उर्जित पटेल**
- 'सूरज कदे मरदा नहीं' (Sun Never Dies) **- बलदेव सिंह सदकनामा**
- 'इफ इट ब्लीड्स' (If It Bleeds) **-स्टीफन किंग**
- 'मेरा युद्ध, कैंसर विरुद्ध' (Mera yudh cancer virudh) **-डॉ. जसवंत राठी**
- 'मोहिनीः द एनचेन्ट्रेस' (Mohini: The Enchantress) **-अनुजा चन्द्रमौलि**
- 'पोखरण' (Pokhran) **-उदय सिंह**

चर्चित दिवस

दिनांक	दिवस/सप्ताह/ माह	2020 का विषय/ अभियान/नारा	महत्वपूर्ण तथ्य
1 जुलाई	राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस	--	इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान देना है। पहली बार यह दिवस 1991 में मनाया गया था। 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि है।
4 जुलाई	अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस	'जलवायु कार्रवाई के लिए सहकारिता' (Cooperatives for Climate Action)	यह दिवस 1923 से जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
6 जुलाई	विश्व पशु-जनित संक्रामक रोग दिवस	--	यह दिवस फ्रांसीसी जीव-विज्ञानी लुई पाश्चर के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने 6 जुलाई, 1885 को सफलतापूर्वक रेबीज (एक पशुजनित रोग) के खिलाफ पहला टीका विकसित किया था।
10 जुलाई	राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस	--	यह दिवस दो वैज्ञानिकों डॉ. के.एच. एलिकुन्ही और डॉ. एच. एल. चौधरी की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 10 जुलाई, 1957 को ओडिशा के कटक में CIFRI के पूर्ववर्ती 'ताल मत्स्यपालन प्रभाग' (वर्तमान में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर (CIFA), भुवनेश्वर) में मछली में प्रेरित प्रजनन 'हाइपोफिजेशन' (Hypophysation) तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था।
11 जुलाई	विश्व जनसंख्या दिवस	'कोविड-19 पर रोक लगानाः अब महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा कैसे करें'	यह दिवस जनसंख्या मुद्दों की तात्कालिकता और महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन गवर्निंग काउंसिल द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई थी।

12 जुलाई	मलाला दिवस	--	12 जुलाई को मलाला युसुफजई के जन्म दिवस को संयुक्त राष्ट्र ने इस युवा कार्यकर्ता के सम्मान में 'मलाला दिवस' के रूप में घोषित किया है। मलाला यूसुफजई लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़ाई का एक अंतरराष्ट्रीय प्रतीक है। वे दिसंबर 2014 में सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता (17 वर्ष की आयु में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता) बनी थी।
15 जुलाई	विश्व युवा कौशल दिवस	'स्किल्स फॉर ए रेजिलिएंट यूथ' (Skills for a Resilient Youth)	रोजगार, सभ्य काम और उद्यमिता के लिए कौशल के साथ युवाओं को लैस करने के रणनीतिक महत्व का जश्न मनाने के लिए 2014 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जुलाई को 'विश्व युवा कौशल दिवस' के रूप में घोषित किया।
16 जुलाई	विश्व सर्प दिवस	--	विभिन्न प्रकार की साँप प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विश्व सर्प दिवस हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है। दुनिया में सांपों की 3,500 से अधिक प्रजातियां हैं।
18 जुलाई	नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस	--	यह दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के योगदान की याद में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2009 में 18 जुलाई को इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव अपनाया था।
20 जुलाई	विश्व शतरंज दिवस	--	संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर, 2019 को वर्ष 1924 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 20 जुलाई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इस अवसर पर विश्वभर के शीर्ष शतरंज खिलाड़ियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित उच्च-स्तरीय ऑनलाइन इवेंट 'चेस फॉर रिकवरिंग बैटर' (Chess for Recovering Better) में हिस्सा लिया।
23 जुलाई	राष्ट्रीय प्रसारण दिवस	--	23 जुलाई, 1927 को देश में पहली बार रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी 'इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी' के तहत बॉम्बे स्टेशन से किया गया। 8 जून, 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा 'ऑल इंडिया रेडियो' बन गई थी।
28 जुलाई	विश्व हेपेटाइटिस दिवस	'हेपेटाइटिस-मुक्त भविष्य'	इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में हेपेटाइटिस की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिवस 28 जुलाई को प्रोफेसर बरूच ब्लूमबर्ग के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रोफेसर बरुच ने हेपेटाइटिस बी वायरस तथा पहले हेपेटाइटिस बी टीके की खोज की थी।
28 जुलाई	विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस	--	इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान देना और सतत विकास योजनाओं को ज्यादा महत्व देना है।
29 जुलाई	अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस	'उनका अस्तित्व हमारे हाथ में है' (Their survival is in our hands)	इस दिवस को 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग बाघ शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। यह दिवस जंगली बाघों की संख्या में भारी गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है।
30 जुलाई	मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस	'कमिटेड टू द कॉज - वर्किंग ऑन द फ्रंटलाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग' (Committed to the Cause - Working on the Frontline to End Human Trafficking)	मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह दिवस मनाया जाता है।

पत्र-पत्रिका संपादकीय

इस अंक में विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित लेखों के आधार पर संपादकीय तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी छात्रों को प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा से संबंधित विश्लेषणात्मक प्रश्नों की तैयारी में मदद करना है।

भारतीय परमाणु प्रौद्योगिकी के लिए बड़ी उपलब्धि

गुजरात के काकरापार स्थित परमाणु विद्युत परियोजना (केएपीपी) की इकाई-3 ने 22 जुलाई को प्रथम 'क्रांतिकता' (Criticality) हासिल कर ली अर्थात यह सामान्य परिचालन स्थिति में आ गया है। घरेलू डिजाइन पर आधारित 700 मेगावाट का यह रिएक्टर 'मेक इन इंडिया' का चमकता उदाहरण है। यह 'प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स' (PHWR) का सबसे बड़ा स्वदेशी संस्करण है। इसके परिचालन योग्य स्थिति में आने के बाद भारत उन देशों की कतार में खड़ा हो गया है, जिनके पास परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी है।

भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का मुख्य आधार PHWRs है, जो ईंधन के रूप में गैर- संवर्धित प्राकृतिक यूरेनियम और एक मंदक एवं शीतलक के रूप में भारी जल का उपयोग करेगा। यह पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों के विपरीत महंगे यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं का उपयोग नहीं करता है तथा यह ऊष्मीय रूप से अधिक कुशल भी है। संवर्धित यूरेनियम के लिए बड़े पैमाने पर वैश्विक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका उपयोग रणनीतिक उद्देश्यों और परमाणु भंडार के लिए आसानी से किया जा सकता है, लेकिन PHWRs पूरी तरह से संवर्धन की सिरदर्दी से बचाता है। मौजूदा सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संचालन के साथ अमेरिका को, निश्चित रूप से PHWRs में भी सबसे शक्तिशाली बनना होगा, जो उसके हित में होगा। दशकों से गैर-विस्तार के बाद परमाणु शक्ति में अमेरिकी विशेषज्ञता में नयापन नहीं दिख रहा है। अमेरिका और भारत को परमाणु संयंत्रों के लिए समय-सीमा को व्यवस्थित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम की आवश्यकता है। 2008 के भारत-अमेरिका परमाणु समझौते से दो-तरफा परमाणु व्यापार के लिए शायद ही इसकी क्षमता का दोहन किया गया है।

मानक परमाणु संयंत्रों के लिए इस्तेमाल किए गए ईंधन के भंडारण की लागत अधिक है। भारत ने 'क्लोज्ड फ्यूल साइकल' (closed nuclear fuel cycle) पर आधारित एक तीन चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम विकसित किया है, जहां एक चरण में इस्तेमाल हुए ईंधन को पुनः संसाधित करके अगले चरण के लिए ईंधन तैयार किया जाता है। **स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स**

एक लंबा रास्ताः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 21वीं सदी की भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली को बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक संघीय प्रणाली में, किसी भी शैक्षणिक सुधार को केवल राज्यों के समर्थन से लागू किया जा सकता है। नीति का उद्देश्य शिक्षाशास्त्र की समस्याओं, संरचनात्मक असमानताओं, पहुंच विषमताओं और बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण की समस्याओं को समाप्त करना है। नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति के बाद पहली सर्वव्यापी नीति है। प्राथमिक स्कूल का चौंकाने वाला खराब साक्षरता रिकॉर्ड एवं गणना कौशल, माध्यमिक स्कूलों और हाई स्कूलों में ड्रॉपआउट स्तर जग-जाहिर है। साथ ही उच्च शिक्षा प्रणाली आमतौर पर बहु-विषयक कार्यक्रमों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। संरचनात्मक शब्दों में शिक्षा नीति, 3 साल की उम्र से बचपन की शिक्षा शुरू करने, वर्ष में दो बार स्कूल बोर्ड परीक्षा द्वारा प्रदर्शन में सुधार करने, सभी के लिए गणितीय कौशल बढ़ाने, चार साल की स्नातक डिग्री प्रणाली तथा एक उच्च शिक्षा आयोग का गठन बड़े बदलावों का प्रतिनिधित्व करती है। शिक्षा में इन बदलावों द्वारा प्रगति महत्वपूर्ण रूप से शिक्षा पर प्रस्तावित सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी के 6% कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। नीति के अनुसार जहां भी संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक लेकिन अधिमानतः कक्षा 8 और उससे आगे तक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम गृह भाषा या मातृ भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। हालांकि एक बड़े और विविधता वाले देश में जहां गतिशीलता अधिक है, छात्र के पास उस भाषा में अध्ययन करने का विकल्प होना चाहिए, जो राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरण को सक्षम कर सके। ऐतिहासिक कारणों से अंग्रेजी ने वह भूमिका निभाई है।

सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित तबके के बच्चों की शिक्षा में मदद करने हेतु 'समावेशी निधियों' की स्थापना एक और अन्य उपाय है। हालांकि, शिक्षा के अधिकार की सफलता के लिए विशिष्ट उपायों की आवश्यकता है। शीर्ष नियामक संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद का विचार तथा योग्यता परीक्षणों के लिए एक राष्ट्रीय निकाय की खूबियों के बारे में राज्यों को राजी करना होगा। 2025 तक सार्वभौमिक साक्षरता और गणना कौशल हासिल करने की समय सीमा एक लक्ष्य के रूप में सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, जो उच्च स्तर पर प्रगति को महत्वपूर्ण रूप से निर्धारित करेगी। **स्रोत- द हिंदू**

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदा अधिसूचना

महामारी के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने असामान्य माहौल में प्रतिगामी पर्यावरणीय निर्णयों को आगे बढ़ाने का काम किया है। मंत्रालय अब जल्द ही एक नई पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना के माध्यम से, परियोजना अनुमोदन की प्रक्रिया

में एक मौलिक बदलाव करना चाहता है। अब मसौदे में 2006 के मौजूदा ईआईए अधिसूचना को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। प्रस्तावित मसौदे में मंत्रालय ने पर्यावरणीय अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया से सार्वजनिक भागीदारी तथा स्वतंत्र विशेषज्ञ की राय को कम करने या यहां तक कि हटाने, उल्लंघन की सार्वजनिक रिपोर्टिंग का संज्ञान न लेने जैसे प्रावधान किए हैं। धारा 26 उन परियोजनाओं की एक सूची प्रदान करता है, जिनमें पर्यावरणीय मंजूरी या अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जिनमें कोयला खनन तथा मीथेन, शेल गैस और तेल के लिए भूकंपीय सर्वेक्षण शामिल हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के मामले में जहां से बुनियादी ढाँचा गुजरेगा, संबंधित जिलों की सार्वजनिक भागीदारी के दायरे को सीमित करता है। इसके अलावा, इसमें यह खंड बरकरार रखा गया है, कि यदि कोई सार्वजनिक एजेंसी या प्राधिकरण स्थानीय स्थिति को नागरिकों द्वारा भागीदारी के लिए अनुकूल नहीं मानता है, तो सार्वजनिक परामर्श को सार्वजनिक सुनवाई में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

अपने प्रस्तावित प्रावधानों की दूरगामी प्रभावों के बावजूद, केंद्र ने इसमें जल्दबाजी दिखाई है। कोविड-19 ने मानव जाति के कल्याण के लिए प्रकृति की भूमिका को शक्तिशाली रूप से उजागर किया है; वनों का विनाश और वन्यजीवों का शिकार वायरस को मनुष्यों के करीब ला रहा है तथा प्रदूषित वायु से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन प्रस्तावित ईआईए प्रणाली में से अधिकांश केवल चीजों को बदतर बना सकता है, इसके माध्यम से इन चीजों को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। **स्रोत- द हिंदू**

बाढ़ नियंत्रण रणनीतियों में बदलाव की आवश्यकता

एक बार फिर असम और बिहार में बाढ़ के सैलाब ने हजारों लोगों को विस्थापित करने के साथ ही बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया और समृद्ध, पीढ़ियों-पुरानी जैव विविधता को मिटा दिया है। असम में, सरकार के पास काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के जंगली जानवरों को बचाने तथा भोजन और पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी है, जिनमें से 85% जलमग्न है। जब भी बाढ़ की घटनाएं होती हैं मानसून को दोष देना, क्षति की सीमा का आकलन करना, केंद्र से वित्तीय और राहत सामग्री की मदद मांगना और बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे की घोषणा करना एक चला आ रहा पैटर्न है।

एशियाई विकास बैंक के एक अध्ययन के अनुसार देश में जलवायु संबंधी सभी आपदाओं में बाढ़ का कम से कम आधा योगदान पहले से ही है। अत्यधिक वर्षा और अनिश्चित मानसून पैटर्न का चलन इस चुनौती को और बढ़ा देगा। भारत को अपनी बाढ़-नियंत्रण रणनीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। पहला दोष बाढ़ के विनाशकारी रूप की आधिकारिक समझ और आकलन में है, जिसके लिए निर्माण- आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक रूप से, बाढ़ नदी के आस-पास के लोगों के जीवन का हिस्सा रही है, क्योंकि वे एक क्षेत्र की जल प्रणालियों में गाद, वनस्पति और मछलियाँ लाते हैं। उन्हें नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश काल से शुरू किए गए इंजीनियरिंग समाधान जैसे तटबंधों, बैराज और बांधों का डिजाइन केवल एक 'खतरा' बन कर रह गए हैं। इन उपायों ने नदियों के मुक्त प्रवाह को प्रतिबंधित कर दिया; गाद, जो आमतौर पर बाढ़ के मैदानों के निर्माण के लिए एक विशाल क्षेत्र पर फैलती है, अब नदी तल को ऊपर उठाते हुए एक बहुत छोटे क्षेत्र तक सीमित है। लोगों ने बाढ़ के मैदानों का अतिक्रमण करना, शहरी जल निकासी प्रणालियों को अवरुद्ध करना, हरे भरे स्थानों पर सड़क निर्माण तथा तालाबों और झीलों को नष्ट करना शुरू कर दिया है।

भारत के नीति-नियंताओं को तटबंध समर्थन की रणनीति को बदलना होगा तथा बाढ़ का सबसे अच्छा उपयोग करने वाली कृषि प्रथाओं को बहाल करना होगा साथ ही सूखे जल-स्रोतों को पुनर्जीवित करने और वर्षा जल का अधिक से अधिक अन्तःस्रवण (percolation) सुनिश्चित करना होगा। **स्रोत- हिंदुस्तान टाइम्स**

गैर-व्यक्तिगत डेटा गवर्नेंस मसौदा रिपोर्ट

यह वास्तव में स्वागत योग्य है कि कुछ दिनों पहले जारी गैर-व्यक्तिगत डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट ने भारत के डेटा गोपनीयता संबंधित विवादास्पद मुद्दों के लिए कुछ स्पष्टता लाने की कोशिश की है। पैनल ने गैर-व्यक्तिगत डेटा को परिभाषित करने की कोशिश की है। यह एक रचनात्मक और समतावादी प्रौद्योगिकी संरचना निर्माण के साथ, भारत के विशाल और उभरते डेटा विस्तार (Data space) का प्रबंधन करने के लिए एक 'गैर-व्यक्तिगत डेटा नियामक प्राधिकरण' स्थापित करने का सुझाव देता है। हालाँकि, रिपोर्ट इस विषय पर पहले के नीतिगत पत्रों में निहित अस्पष्टताओं से मुक्त नहीं है, जिसमें अति महत्वपूर्ण निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 शामिल है, जो दीर्घकालिक चिंताओं को जन्म देता है।

नई रिपोर्ट से उत्पन्न एक बड़ी चिंता स्पष्टता की कमी है कि यह गैर-व्यक्तिगत डेटा को कैसे परिभाषित करता है। गैर-व्यक्तिगत डेटा उसे माना जाता है जो किसी पहचाने गए या पहचाने जाने योग्य व्यक्ति से संबंधित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, इसमें मौसम की स्थिति, औद्योगिक मशीनों पर स्थापित सेंसर से संबंधित डेटा, सार्वजनिक अवसंरचना से संबंधित डेटा शामिल होगा। गैर-व्यक्तिगत डेटा की एक और श्रेणी जानकारी से संबंधित हो सकती है, जो शुरू में व्यक्तिगत डेटा थी लेकिन बाद में नाम रहित (anonymous) बना दी गई।

गैर-व्यक्तिगत डेटा को उनके स्वामित्व और सृजन की उत्पत्ति के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है- सार्वजनिक, सामुदायिक और निजी। पैनल के सुझाव गैर-व्यक्तिगत डेटा को परिभाषित एवं निर्धारित करने और अपने हितों के लिए उपयोग करने के लिए राज्य को अत्यधिक अधिकार देने का काम करते हैं। यह व्यावसायिक हितों को चोट पहुँचाने के अलावा, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। डिजिटल नियंत्रण राज के एक नए रूप से बचा जाना चाहिए। डेटा उपयोग में पारदर्शिता लाना समय की जरूरत है। **स्रोत- द हिंदू बिजनेसलाइन** ■■

समसामयिक प्रश्न

इस खंड के अंतर्गत इस माह की समसामयिक घटनाओं पर आधारित संभावित प्रश्नों को संकलित किया गया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी छात्रों को समसामयिक प्रश्नों की तैयारी में मदद करना है।

1. जुलाई 2020 में 'गोल्डन बर्डविंग' (Golden Birdwing) नामक एक हिमालयी तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा दिया गया है। यह मादा तितली उत्तराखंड में कहाँ दर्ज की गई?
(a) गोपेश्वर (चमोली)
(b) डीडीहाट (पिथौरागढ़)
(c) अस्कोट (पिथौरागढ़)
(d) मसूरी (देहारादून)

2. 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी जी. आकाश जुलाई 2020 में भारत के 66वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। वे किस राज्य से हैं?
(a) केरल (b) आंध्र प्रदेश
(c) तेलंगाना (d) तमिलनाडु

3. अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है?
(a) 2 जुलाई (b) 3 जुलाई
(c) 4 जुलाई (d) 5 जुलाई

4. विश्व बैंक और भारत सरकार ने 6 जुलाई को 'एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम' के लिए कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए?
(a) 750 मिलियन डॉलर
(b) 800 मिलियन डॉलर
(c) 850 मिलियन डॉलर
(d) 950 मिलियन डॉलर

5. 'राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन' को किस वर्ष लॉन्च किया गया था?
(a) 2000 (b) 2001
(c) 2002 (d) 2003

6. रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को पूरी तरह हरित ऊर्जा से संचालित करने और 'शून्य कार्बन उत्सर्जन' हासिल करने का लक्ष्य रखा है?
(a) 2022 (b) 2025
(c) 2029 (d) 2030

7. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 6 जुलाई, 2020 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के अध्यक्ष के रूप में इंजेती श्रीनिवास की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की। IFSCA का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
(a) जामनगर (b) अहमदाबाद
(c) गांधीनगर (d) सूरत

8. हाल में किसने कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित 'सीआईआई-आईटीसी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019' जीता?
(a) ओएनजीसी (b) एनटीपीसी
(c) इंडियन ऑयल (d) एनएचपीसी

9. जुलाई 2020 में किस राज्य द्वारा भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया?
(a) महाराष्ट्र (b) मध्य प्रदेश
(c) छत्तीसगढ़ (d) गुजरात

10. डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में अपने 2023 के लक्ष्य से पहले ही किन दो देशों ने खसरा और रूबेला का उन्मूलन कर लिया है?
(a) मालदीव और श्रीलंका
(b) म्यांमार और नेपाल
(c) भारत और बांग्लादेश
(d) बांग्लादेश और थाईलैंड

11. भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2025 तक कितने अरब डॉलर के रक्षा उत्पादन को हासिल करने का आह्वान किया गया है?
(a) 26 अरब डॉलर (b) 28 अरब डॉलर
(c) 30 अरब डॉलर (d) 32 अरब डॉलर

12. वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार, भारत वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में किस स्थान पर है?
(a) पहले स्थान (b) दूसरे स्थान
(c) तीसरे स्थान (d) चौथे स्थान

13. हाल में क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (CSA) के वार्षिक पुरस्कार 2020 समारोह में किस क्रिकेटर को 'पुरुष क्रिकेटर ऑफ द इयर' से सम्मानित किया गया?
(a) फाफ डू प्लेसिस (b) डेविड मिलर
(c) क्विंटन डी कॉक (d) केगिसो रबादा

14. संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) 'लक्ष्य 3.1' का उद्देश्य वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को प्रति 100,000 जीवित जन्मों में कितने से कम करना है?
(a) 60 से (b) 70 से
(c) 80 से (d) 100 से

15. भारत सरकार ने केन्द्र और राज्य सरकारों के जिलों/संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को मान्यता देने के लिए किस वर्ष 'प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार योजना' की शुरुआत की थी?

(a) 2004 (b) 2005
(c) 2006 (d) 2007

16. जुलाई 2020 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में अमेरिका लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना रहा। 2019-20 में, अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितने बिलियन डॉलर था?

(a) 87.96 बिलियन डॉलर (b) 88.75 बिलियन डॉलर
(c) 90 बिलियन डॉलर (d) 95 बिलियन डॉलर

17. सतत विकास समाधान नेटवर्क (SDSN) और बर्टल्समैन स्टिफटंग (Bertelsmann Stiftung) द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ?

(a) फ्रांस (b) जर्मनी
(c) स्वीडन (d) भारत

18. भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद 'चान' संतोखी ने जुलाई 2020 में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया?

(a) सूरीनाम (b) फिजी
(c) त्रिनिदाद एवं टोबैगो (d) मॉरीशस

19. 'वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020' के अनुसार भारत ने 10 वर्षों (2005/06 - 2015/16) में राष्ट्रीय स्तर पर कितने मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है?

(a) 250 मिलियन (b) 273 मिलियन
(c) 290 मिलियन (d) 293 मिलियन

20. किस देश ने जुलाई 2020 में अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह 'एएनएएसआईएस-II' सफलतापूर्वक लॉन्च किया?

(a) दक्षिण कोरिया (b) बांग्लादेश
(c) दक्षिण अफ्रीका (d) जॉर्डन

21. स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और दो बार के ओलंपिक बैडमिंटन चौंपियन लिन डैन ने 4 जुलाई, 2020 को संन्यास की घोषणा की। वे किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी थे?

(a) इन्डोनेशिया (b) फिलीपींस
(c) चीन (d) दक्षिण कोरिया

22. बिजॉय मोहंती का जुलाई 2020 में भुवनेश्वर में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबन्धित थे?

(a) फिल्म (b) खेल
(c) विज्ञान (d) राजनीति

23. जुलाई 2020 में पाकिस्तान और चीन ने 700.7 मेगावाट की 'आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना' के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना किस नदी पर स्थापित की जा रही है?

(a) सिंधु (b) रावी
(c) झेलम (d) चिनाव

24. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जुलाई 2020 में किस देश के केन्द्रीय बैंक के साथ 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला-बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?

(a) श्रीलंका (b) अफगानिस्तान
(c) मॉरीशस (d) मालदीव

25. किस संस्थान ने 27 जुलाई, 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और विख्यात वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अपनी नवाचार प्रतियोगिता 'डेयर टू ड्रीम 2.0' (Dare to Dream 2.0) शुरू की?

(a) इसरो (b) नीति आयोग
(c) डीआरडीओ (d) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

उत्तरमाला

1. (b)	2. (d)	3. (c)	4. (a)	5. (d)
6. (d)	7. (c)	8. (b)	9. (c)	10. (a)
11. (a)	12. (c)	13. (c)	14. (b)	15. (c)
16. (b)	17. (c)	18. (a)	19. (b)	20. (a)
21. (c)	22. (a)	23. (c)	24. (a)	25. (c)

❖❖❖❖❖❖❖

संस्थान–संगठन

प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्थान - संगठन से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए इस खंड की शुरुआत की गई है।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जुलाई 2020 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में 'संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद' (ECOSOC) सत्र के इस साल के उच्च स्तरीय खंड में वर्चुअल रूप से मुख्य संबोधन दिया।

विषय (Theme): 'कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद: 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस प्रकार के संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है'।

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने **1945** में संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से एक आर्थिक और सामाजिक परिषद की स्थापना की। सतत विकास के तीन आयामों - **आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण** - को आगे बढ़ाने के लिए यह परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के केंद्र में स्थित है। यह **वार्ता और अभिनव सोच** को बढ़ावा देने, आगे बढ़ने के तरीकों पर आम सहमति बनाने और **अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को हासिल करने के** प्रयासों के समन्वय के लिए केंद्रीय मंच है।

अंतरराष्ट्रीय रेल संघ

रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार को जुलाई 2022 से जुलाई 2024 तक अंतरराष्ट्रीय रेल संघ के सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। भारतीय रेलवे इस सुरक्षा मंच का सक्रिय सदस्य है।

- यह दुनिया भर में रेलवे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वालों और रेल परिवहन को बढ़ावा देने वालों का पेशेवर संघ है। इसकी स्थापना **1922** में की गई थी। इसका मुख्यालय **पेरिस** में स्थित है। इसका उद्देश्य **गतिशीलता** और **सतत विकास** की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के साथ विश्व स्तर पर **रेल परिवहन को बढ़ावा** देना है। अंतरराष्ट्रीय रेल संघ की गतिविधियां दुनिया भर में रेलवे समुदाय के हित में विकसित किए जाने वाले 5 प्रमुख क्षेत्रों **पर्यावरण, बचाव और सुरक्षा, सिग्नलिंग, मालभाड़ा / फ्रेट कॉरिडोर तथा मानकीकरण** पर केन्द्रित हैं।

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

1 जुलाई, 2020 को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई (Institute of Chartered Accountants of India-ICAI) के स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स दिवस मनाया गया।

- आईसीएआई की स्थापना देश में **चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे** को **विनियमित** करने के लिए **1 जुलाई, 1949** को संसद द्वारा पारित चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के तहत हुई। संस्थान, भारत सरकार के **कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय** के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। यह दुनिया में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का दूसरा सबसे बड़ा पेशेवर निकाय है। आईसीएआई के मुख्य कार्य अकाउंटेंसी के पेशे को विनियमित करना, **चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम की शिक्षा और परीक्षा** तथा **लेखा मानकों का नियमन** करना है। आईसीएआई के मामलों का प्रबंधन एक परिषद द्वारा किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन

28 जुलाई, 2020 को अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन (ITER) द्वारा फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े परमाणु 'संलयन डिवाइस' को एसेंबल किये जाने की शुरूआत की गई।

- ITER एक **प्रयोगात्मक परमाणु संलयन रिएक्टर** है, जिसे दक्षिणी फ्रांस में बनाया जा रहा है। पहली बार 1985 में शुरू संलयन में एक अंतरराष्ट्रीय संयुक्त प्रयोग के विचार के बाद से हजारों इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने ITER के डिजाइन में योगदान दिया है। ITER संगठन आधिकारिक तौर पर **24 अक्टूबर, 2007** को स्थापित किया गया था ITER संगठन सदस्य- **चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका** हैं।

भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान

जुलाई 2020 में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में एक ऐसे हरी मिर्च पाउडर पर शोध कर इसका पेटेंट कराया गया है, जिसकी गुणवत्ता और स्वाद में कोई कमी नहीं आती है।

- सब्जियों के महत्व को देखते हुए **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद** (ICAR) ने देश में व्यवस्थित सब्जी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए **1999** में **वाराणसी** में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (IIVR) की स्थापना की। सब्जी फसलों की **उत्पादकता बढ़ाने** और **गुणवत्ता निगरानी** के लिए बुनियादी, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान; सब्जी फसलों, आनुवंशिक संसाधनों और वैज्ञानिक जानकारी का भंडार तथा **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण** इसके प्रमुख कार्य हैं। वर्तमान में संस्थान में कुल मिलाकर 42 सब्जियों पर शोध कार्यक्रम चल रहे हैं। ■■

लोक सभा | राज्य सभा प्रश्नोत्तर–सार

इस अंक में संसद के बजट सत्र में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का तथ्य सार दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी छात्रों को सरकार की कार्य-योजनाओं की प्रगति और भविष्य की कार्य-योजनाओं से अवगत कराना है।

लोक सभा

- **विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम योजना:** वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में **'विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम योजना'** के संबंध में की गई घोषणाओं को लागू करने के लिए **विद्या लक्ष्मी पोर्टल** को एकल विंडो के रूप में **अगस्त 2015** में **शैक्षिक ऋण योजनों के संबंध में सूचना** प्राप्त करने हेतु विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन समाधान के साथ-साथ **शैक्षिक ऋण के लिए बैंकों में आवेदन** करने के लिए स्थापित किया गया था। यह पोर्टल सरकारी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की सुविधा भी प्रदान करता है। 12 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, 36 बैंकों ने पोर्टल पर पंजीकरण किया है, और **90 शैक्षिक ऋण योजनाएं** पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
- **कृत्रिम बौद्धिकता में अनुसंधान:** सरकार ने कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने की दृष्टि से **6 दिसम्बर, 2018** को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले **'राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर भौतिक प्रणाली मिशन'** {National Mission on Inter-disciplinary Cyber Physical system (NM-ICPS)} के प्रवर्तन को **पाँच वर्ष** की अवधि के लिए **3660 करोड़ रुपए** के कुल परिव्यय से अनुमोदित किया गया है। इसमें **मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास संवर्द्धन** और **एआई में स्टार्ट-अप** शामिल है। यह मिशन देश भर में **एआई एवं संबंधित प्रौद्योगिकियों** के अध्ययन एवं निर्माण के लिए प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानों में 25 प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन हब का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा नीति आयोग ने **जून 2018** में 'भारत के लिए राष्ट्रीय कृत्रिम बौद्धिकता कार्यनीति' जारी की।
- **पाषाण शिल्प ग्राम:** वर्ष **2014-15** के दौरान **ओडिशा** के पाषाण (Stone) शिल्प कार्य को विकसित करने के लिए **पुरी जिले के रघुराजपुर** में सरकार ने पहले ही पाषाण शिल्प ग्राम को मंजूरी दे दी है। सरकार अब तक **'अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास योजना'** के घटक के तहत रघुराजपुर में शिल्प ग्राम की स्थापना के लिए **6 करोड़ रुपए** निर्मुक्त कर चुकी है। अभी तक निष्पादित किए गए प्रमुख कार्य गृह-सह-कार्यस्थल उन्नयन, मौजूदा सोसाइटी भवन का नवीनीकरण, गेस्ट हाउस, कैफेटेरिया तथा शौचालय आदि निर्माण शामिल हैं।

राज्य सभा

- **भारतीय रेल में जैविक शौचालय:** पूर्ववर्ती ओपन डिस्चार्ज शौचालय प्रणाली को खत्म करने के लिए भारतीय रेल के सवारी डिब्बों के लिए **संवातन** (ventilation) के साथ **जीरो डिस्चार्ज जैव-शौचालय प्रणाली** को अपनाया गया है। वर्ष 2006 के दौरान इसकी संकल्पना की गई थी। इसके अलावा, पर्याप्त परीक्षणों के बाद डीआरडीई (रक्षा अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान) के साथ डिजाइन विकसित किया गया है। दुर्गंध को खत्म करने के लिए, सवारी डिब्बों के शौचालयों में वेंचुरी (Venturi) किस्म की **शौचालय संवातन प्रणाली** की व्यवस्था की जा रही है। **रेल मदद पोर्टल** के माध्यम से प्राप्त जैव-शौचालय से संबंधित शिकायतों का समय पर समाधान किया जा रहा है। भारतीय रेल में **88 रेलवे स्टेशनों** पर जैव-शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं।
- **वन्यजीव सर्किट विकास योजनाएं:** पर्यटन मंत्रालय ने **स्वदेश दर्शन योजना** के तहत विकास के लिए वन्यजीव सर्किट की पहचान **पन्द्रह विषयगत सर्किटों** में से एक के रूप में की है। वन्यजीव सर्किट के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है**: मध्य प्रदेश** में **2015-16** में **92.22 करोड़ रुपए** की राशि से **पन्ना - मुकुंदपुर- संजय- डुबरी- बांध वगढ़- कान्हा- मुक्की- पेंच** का विकास। **2015-16** में **95. 67 करोड़ रुपए** की राशि से **असम** में **मानस- पोबितोरा- नामेरी- काजीरंगा- डिब्रू- सैखोवा** का विकास।
- **भारत में जैविक कपास की खेती:** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत 'राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय' **जैविक उत्पादन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम** (एनपीओपी) की व्यवस्था और संचालन करता है। प्रत्यायन क्रियाकलापों को संचालित करने हेतु **कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)** सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है। **जैविक कपास खेती** के उत्पादन की **औसत लागत** पारंपरिक तथा बीटी कपास उत्पादन से **कम** है, जो कि मुख्य रूप से देशी कपास बीज की कम लागत तथा जैविक उर्वरक के प्रयोग के कारण है। कृषि मंत्रालय वर्ष **2015-16** से **पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन** तथा **परंपरागत कृषि विकास योजना** नामक विशेष योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है। ■■

इन्हें भी जानें

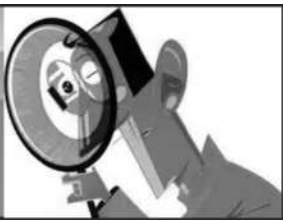

इस अंक में विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित लेखों में प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों की जानकारी प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के शब्दों से आने वाले संभावित प्रश्नों की तैयारी में मदद करना है।

- **'ब्लैकरॉक' मैलवेयरः** सिक्योरिटी फर्म 'थ्रेटफेब्रिक' (ThreatFabric) ने 'ब्लैकरॉक' नामक एक नए मैलवेयर के बारे में सावधान किया है, जो अमेजन, फेसबुक, जीमेल और टिंडर सहित लगभग 377 स्मार्टफोन एप्लिकेशन से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की जानकारी चोरी कर सकता है। ब्लैकरॉक और अन्य एंड्रॉइड ट्रोजन के बीच एकमात्र बड़ा अंतर यह है कि यह पूर्व मैलवेयर की तुलना में अधिक ऐप को निशाना बना सकता है। एक बार एक फोन पर इंस्टॉल होने के बाद, यह लक्षित ऐप पर नजर रखता है तथा उपयोगकर्ता द्वारा लॉगिन और/ या क्रेडिट कार्ड के विवरण प्रविष्ट करने पर एक सर्वर को सूचना भेजता है। ब्लैकरॉक फोन की 'एक्सेसिबिलिटी सुविधा' (Accessibility feature) का उपयोग करता है, और फिर अन्य अनुमतियों तक पहुंच के लिए एंड्रॉइड डीपीसी (device policy controller) का उपयोग करता है।
- **फोर्स मेजरः** 'फोर्स मेजर' (Force majeure) एक फ्रांसीसी शब्द है। यह एक ऐसी असाधारण घटनाओं और परिस्थितियों को संदर्भित करता है, जो मानव नियंत्रण से परे हों। फोर्स मेजर एक समझौते या अनुबंध में एक खंड है, जो पार्टियों को असाधारण परिस्थितियों में अपने वादों को पूरा न करने की अनुमति देता है। इस खंड का अर्थ है कि मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा नहीं किया जा सकता है, और इसलिए पार्टियों को अनुबंध की शर्तों को पूरा न कर पाने की स्थिति में कानूनी प्रावधानों से छूट दी जानी चाहिए। इस तरह की घटनाओं के सामान्य उदाहरण प्राकृतिक आपदा, आग, युद्ध और महामारी हैं।
- **सीरोलॉजिकल सर्वेक्षणः** कोरोना संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात को समझने के लिए दिल्ली में किए गए एक सीरो सर्वेक्षण से पता चला है कि 23.48% प्रतिशत लोग कोरोना वायरस के कारण प्रभावित हैं तथा बड़ी संख्या में संक्रमित व्यक्ति बिना लक्षण वाले हैं। यह अध्ययन दिल्ली सरकार के सहयोग से 'राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र' द्वारा किया गया है। सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण का उद्देश्य वायरस के खिलाफ विशिष्ट एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाकर आबादी में बीमारी की व्यापकता का आकलन करना होता है। संक्रमण और स्व-प्रतिरक्षित (autoimmune) बीमारियों के निदान के लिए एक सीरोलॉजिकल परीक्षण किया जाता है। किसी व्यक्ति ने कुछ बीमारियों के लिए प्रतिरक्षा विकसित की है, यह जांच करने के लिए भी परीक्षण किया जा सकता है।
- **रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्टः** रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) एक कंपनी है, जो निवेशकों के लिए नियमित रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए आय-उत्पादक संपत्तियों के पोर्टफोलियो का स्वामित्व, संचालन और वित्त प्रबंधन करती है। ये अचल संपत्ति से जुड़ी प्रतिभूतियाँ हैं और अधिकांश आरईआईटी को सार्वजनिक रूप से स्टॉक की तरह कारोबार किया जाता है, जो उन्हें अत्यधिक तरल बनाता है। बाजार नियामक सेबी द्वारा विनियमित, एक आरईआईटी के पास त्रि-स्तरीय संरचना है। एक प्रायोजक, जो REIT की स्थापना के लिए जिम्मेदार है; फंड प्रबंधन कंपनी, जो संपत्तियों के चयन और संचालन के लिए जिम्मेदार है; और ट्रस्टी, जो यह सुनिश्चित करता है कि पैसा यूनिट-धारकों के हित में प्रबंधित है। आरईआईटी अपार्टमेंट इमारतों, डेटा सेंटर, होटलों, चिकित्सा सुविधाओं, कार्यालयों और गोदामों सहित अधिकांश अचल संपत्ति प्रकारों में निवेश करते हैं।
- **सिस्टोसोमियासिसः** 'लांसेट प्लानेटरी हेल्थ' में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार फसलों के लिए कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से 'सिस्टोसोमियासिस' (schistosomiasis) या 'स्नेल फीवर' नामक बीमारी के फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। यह बीमारी 'सिस्टोसोमा' नामक परजीवी के कारण होती है। जिससे किडनी और लीवर तक खराब हो सकते हैं। यह परजीवी आमतौर पर उप-सहारा अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और कैरेबियन देशों में पाया जाता है, जहां ताजे जल में यह परजीवी आसानी से पनप सकता है। यह परजीवी त्वचा से होता हुआ रक्त में पहुंच जाता है। बुखार, ठंड लगना, खांसी, सिरदर्द, पेट दर्द, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द इसके सामान्य लक्षण है।
- **हवाई बीजारोपणः** हरियाणा वन विभाग ने जुलाई 2020 में अरावली क्षेत्र में हरित आवरण हेतु हवाई बीजारोपण (Aerial seeding) शुरू किया है। हवाई बीजारोपण रोपण की एक तकनीक है, जिसमें मिट्टी, खाद, चारकोल और अन्य घटकों के मिश्रण से ढ़के हुए बीज को गेंद का रूप देकर हवाई जहाज, हेलिकॉप्टर या ड्रोन आदि हवाई उपकरणों का उपयोग करके जमीन पर छिड़काव किया जाता है। बीजों से युक्त गेंदों को ड्रोन द्वारा एक लक्षित क्षेत्र में फैलाया जाता है, जो अन्य सामग्री के लेपन के वजन से पूर्व-निर्धारित स्थान पर गिरता है। ऐसे क्षेत्र जो दुर्गम हैं तथा जहां पारंपरिक वृक्षारोपण मुश्किल हो जाता है, ऐसे क्षेत्रों में यह तकनीक लाभप्रद है। इसके अलावा, इसमें बीज के अंकुरण और वृद्धि की प्रक्रिया ऐसी होती है कि इसके छिड़काव के बाद इस पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। ■